R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 19
01 से 15 जुलाई 2022
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

ऑपरेशन लोटस
या बगावत के शिकार उद्धव...?

विपक्ष का एक और किला ध्वस्त,
महाराष्ट्र में बनी नई सरकार

विधायक अब राजनीतिक उद्यमी बन गए हैं,
महाराष्ट्र इसकी ताजा मिसाल

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

भर्राशाही

9 | कागजों पर भोपाल 'स्मार्ट'

केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना को किस तरफ पलीता लगाया जा रहा है, इसका नजारा भोपाल में देखा जा सकता है। राजधानी में स्मार्ट सिटी का क्षेत्र आज भी खंडहर बना हुआ है। योजनाएं आधी-अधूरी पड़ी...

राजपथ

10-11 | दांव पर शिव-नाथ की साख

मप्र में 2022 और 2023 को चुनावी समर का साल कहा जा रहा है। अभी पंचायत और नगरीय निकाय के लिए घमासान हो रहा है तो 2023 में विधानसभा चुनाव के नगाड़े बजेंगे। माना जा रहा है कि 2023 के सत्ता के फाइनल...

पुलिसनामा

14 | महिला पुलिस की तादात...

प्रदेश में महिलाओं के लिए पुलिस बल में 33 फीसदी आरक्षण का निर्णय लिया है, लेकिन विडंबना यह है कि प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की तादात 10 फीसदी भी नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार की योजना अनुसार प्रत्येक थाने में 13 महिला पुलिसकर्मी...

नक्सली

18 | खूंखार नक्सलियों की घुसपैठ

मप्र में नक्सलियों का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सीमाई इलाकों में नक्सलियों का मूवमेंट तेजी से बढ़ा है। खुफिया रिपोर्ट कह रही हैं कि इस वक्त 97 खूंखार और हार्डकोर नक्सली मप्र में सक्रिय हैं ये सभी कमांडर इन चीफ स्तर के हैं। ये सभी मप्र में तेजी से अपना विस्तार कर रहे हैं। पुलिस ने इनसे...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

करीब एक पखवाड़े के बगावती खेल के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर गई। वहीं एकनाथ शिंदे ने भाजपा के सहयोग से नई सरकार बना ली है। ऐसे में देशभर में यह सवाल उठने लगा है कि विपक्ष का एक और किला ध्वस्त होने के पीछे भाजपा का ऑपरेशन लोटस या शिवसैनिकों की बगावत कारण बना है। वजह कोई भी हो, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है।

राजनीति

30-31 | बिखराव के साथ लक्ष्य...

देश में मोदी-शाह की भाजपा के खिलाफ विपक्ष ने एकजुट होने के कई प्रयास किए लेकिन अभी तक सारे प्रयास विफल हुए हैं। ऐसे में अब राष्ट्रपति चुनाव का ऐसा अवसर आया है, जब विपक्ष एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा सकता है। दरअसल, बिखराव के साथ विपक्ष का एक ही लक्ष्य...

महाराष्ट्र

35 | फडणवीस नए चाणक्य

महाराष्ट्र की राजनीति में 10 जून से 29 जून 2022 के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती के असली चाणक्य हैं और नि:संदेह मराठा क्षत्रप शरद पवार का युग...

बिहार

38 | सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने का सर्वदलीय निर्णय लिया है। इसके पूर्व फरवरी 2019 और 2020 में बिहार विधानसभा जातिगत जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर चुकी है। क्या बिहार के दल समझते हैं...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

अब जरूरतमंदों को मिलेगी भरपूर सहायता

किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि...

डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर।
खुद-ब-खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौंसला देखकर।।

यह शेर मप्र में सरकार और जनता के बीच बढ़ रही नजदीकियों पर सटीक बैठता है। दरअसल, प्रदेश की सरकार लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी योजनाओं को आकार देती है। इसी कड़ी में आमजन का सहयोग करने विधायकों के हाथ तंग न रहें इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने विधायक निधि के साथ ही स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि 150 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ करने की स्वीकृति और विधायक स्वेच्छानुदान राशि 15 लाख से बढ़कर 50 लाख की गई। इसके अलावा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना 1 करोड़ 85 लाख से बढ़ाकर 2.50 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया है। यानी अब जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री और विधायक भरपूर सहायता राशि बांट सकेंगे। लेकिन इस दौरान इस बात की भी निगरानी करनी होगी कि सहायता राशि की बंदरबांट न हो जाए। गौरतलब है कि स्वेचानुदान राशि की विधायक की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा जरूरत मंदो को वितरित की जाती है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि सरकारी सहायता में जमकर बंदरबांट हो रही है। सरकारी मशीनरी के साथ ही जनप्रतिनिधियों के करीबी जरूरतमंदों के हिस्से में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी हाल ही में अस्पतालों का भ्रष्टाचार सामने आया है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन की तर्ज पर प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम संचालक जरूरतमंद मरीजों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से मंजूर की जाने वाली सहायता राशि में भी गोलमाल कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि हड़पने के लिए फर्जी एस्टीमेट तैयार किए जाते हैं। फर्जीवाड़ा करने वालों की सेटिंग इतनी सॉलिड है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से अनुदान भी जारी करा लिया जाता है। ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं। ताजा मामला और हैरानी करने वाला है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग राजधानी के जिन 19 प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ आयुष्मान भारत योजना में धांधलियों की पोल खोल चुका है, वहां भर्ती होने वाले कई मरीजों के इलाज का खर्च अस्पताल के संचालक सरकार से ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार सांसदों और विधायकों की सिफारिश पर मरीजों के इलाज पर होने वाला खर्च मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से मंजूर होकर सीधे अस्पतालों के खाते में जा रहा है। ऐसे न जाने कितने भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। मप्र में सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति पर पूरा फोकस कर रखा है। उसके बावजूद आलम यह है कि सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं। इसलिए माननीयों को इस दिशा में सतर्कता दिखानी होगी। केवल स्वेच्छानुदान और विधायक निधि बढ़ा देने भर से जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होने वाली नहीं हैं। जरूरत यह है कि अनुदान राशि के वितरण में सतर्कता बरती जाए। तभी सरकार की इस कोशिश का फायदा जरूरतमंदों को हो पाएगा। प्रदेश में पिछले कुछ सालों के दौरान मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, विधायक स्वेच्छानुदान और विधायक निधि के वितरण में कई तरह की खामियां सामने आई हैं। अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो सरकार की मंशा पर पानी फिर सकता है।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 19, पृष्ठ-48, 1 से 15 जुलाई, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र-संपादक के नाम

akshnews.com

कन्यादान योजना में वसूली

प्रदेश में घोटालेबाजों ने हर एक योजना में भ्रष्टाचार किया है, यहां तक उन्होंने कन्यादान योजना को भी नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना का लाभ अपात्रों को दिलाने के लिए अवैध वसूली की गई, जिससे प्रदेशभर में लोग गुस्साए हुए हैं।

● **परशुराम शर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

मिलेगा रोजगार

कोरोना संक्रमण के कारण विदेशी निवेश लगभग बंद हो गया था। ऐसे में बंदिशों के कारण मप्र विदेशी निवेश को लेकर खास काम नहीं कर रहा था। अब स्थिति बदलने से वापस विदेशी निवेश पर फोकस किया गया है। जहां बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा।

● **नितेश नामदेव,** इंदौर (म.प्र.)

कुपोषण से मुक्ति कब?

मप्र में कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चला रखीं हैं। लेकिन यहां का सिस्टम ही इस कदर कुपोषित है कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई अव्यवस्था का शिकार हो जाती है। इसके कारण कई जिलों में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं।

● **सरफराज खान,** ग्वालियर (म.प्र.)

आने वाली पीढ़ियों की चिंता का विषय

देश में इन दिनों जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, उससे आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, ये बात सोचकर ही डर लगने लगता है। हमारी गंगा-जमुनी संस्कृति को किसकी नजर लग गई है, जो एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा होने लगा है। देश में जिस तरह सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है, ऐसे समय में न तो सत्तापक्ष और न ही विपक्ष अपनी भूमिका निभा पा रहा है। सभी लोगों को यह बात समझनी होगी कि इससे किसी को फायदा नहीं होगा, बल्कि हमारे देश को ही नुकसान होगा। एक तरफ हम दुनिया को पीछे छोड़कर विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस प्रकार से हिंसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे क्या सीखेंगी।

● **सोनम सूर्यवंशी,** राजगढ़ (म.प्र.)

खेतों में जहर

प्रदेश में एक तरफ सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान अच्छी फसल के लिए कीटनाशकों का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश में नर्मदापुरम संभाग में सबसे अधिक मूंग की खेती होती है और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक कीटनाशकों को इस्तेमाल हो रहा है। कीटनाशकों के जहर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से हर साल 30 लाख लोग बीमार होते हैं, जिनमें से ढाई लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

● **महेंद्र पालीवाल,** होशंगाबाद (म.प्र.)

मप्र में होगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट

इंदौर और भोपाल के बीच यात्रियों के साथ कार्गो और लॉजिस्टिक हब को बढ़ावा देने के लिए देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट बनने से एक तरफ जहां मप्र को आर्थिक रूप से लाभ होगा, वहीं यहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने के साथ ही इस पूरे क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होगी। ज्यादा जगह होने पर एयरलांइस इसे अपना बेस बना सकती है। जिससे लोगों को रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री में भी नए रोजगार पैदा होंगे।

● **पूजा सैन,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

विद्रोहपथ

भाजपा सांसद वरुण गांधी भी बगावत की राह पर हैं। केंद्र की अग्निपथ योजना पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने वाले वे भाजपा के इकलौते सांसद हैं। उन्होंने योजना की घोषणा के कुछ घंटों के भीतर ही ट्वीट कर फरमाया कि अगर सरकार पांच साल के लिए चुनी जाती है तो फिर युवाओं को ही देश की सेवा करने का अवसर केवल चार साल के लिए क्यों? अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में लगातार विरोध हो रहा है। इससे पहले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ही करा रहे थे केंद्र सरकार और भाजपा की किरकिरी। वरुण गांधी के बागी तेवरों का खमियाजा उनकी मां मेनका गांधी भी भुगत चुकी हैं। पिछली सरकार में उन्हें मंत्रिपद दिया गया था। पर 2019 में भाजपा पहले से ज्यादा सीटें जीतकर केंद्र की सत्ता में फिर आई तो मेनका का नाम मंत्रियों की सूची से कट गया। वरुण गांधी को तो खैर पार्टी में कोई पूछ ही नहीं रहा था। कहां तो 2013 में पार्टी के अध्यक्ष रहते राजनाथ सिंह ने 33 साल के वरुण गांधी को सबसे कम उम्र वाला पार्टी महासचिव बनाया था। कहां आज मां-बेटा पार्टी की कार्यकारिणी तक के सदस्य नहीं हैं। वरुण गांधी ने 2009 में भाजपा उम्मीदवार की हैसियत से अपनी मां मेनका गांधी की पीलीभीत सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। मेनका को बेटे के लिए दूसरी सीट आंवला जाना पड़ा था।

शिमला और सपना

हिमाचल सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज। जब 2017 में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर से चुनाव हार गए तो समीरपुर से मुख्यमंत्री के पद के लिए उनके नाम को आगे किया गया था। लेकिन बात नहीं बनी और जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। पिछले साढ़े चार साल में वे काफी कुछ करते रहे। पहले शिक्षा मंत्री थे तो संस्कृत विवि खोलने को लेकर उन्होंने बहुत प्रचार किया। उसके बाद संस्कृत भाषा को मान देने की बात भी वह करते रहे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बाद में उन्हें शहरी विकास विभाग दे दिया गया। यहां उन्होंने कई कोशिशें की। मंत्रिमंडल से कुछ मंजूर भी करवाते गए। अब लगता है कि उनके सितारे गर्दिश में पहुंच गए हैं। शिमला शहर की राजनीति के मद्देनजर उन्होंने शिमला विकास योजना का मसौदा तैयार कराया। इस पर एक करोड़ रुपए तक का खर्च भी कर दिया। उन्हें लगा कि शिमला विकास योजना को लागू कर शहर में कई मंजिला भवन खड़े करने की कुछ लोगों की मंशा को पूरा कर देंगे। लेकिन इस मसौदे पर राष्ट्रीय हरित पंचाट ने रोक लगा दिया। पंचाट के फैसले के मुताबिक शिमला में ढाई मंजिल से ज्यादा मकान नहीं बन सकते हैं। भारद्वाज ने शिमला विकास योजना के मसौदे के जरिए इस फैसले को पलटने की मुहिम छेड़ी थी अब तक नाकाम है।

साझा सरकार में अपना अंदाज

जद (एकी) और भाजपा बिहार में साझा सरकार तो जरूर चला रहे हैं पर दोनों के बीच चूहे और बिल्ली वाला खेल चल रहा है। कई मुद्दों पर नीतीश कुमार भाजपा के उलट अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। ताजा प्रसंग अग्निपथ योजना का है। बिहार में केंद्र की इस योजना का सड़कों पर विरोध हो रहा है। नीतीश ने खुद तो कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं जताई पर उनके भरोसेमंद और जद (एकी) अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने जरूर ट्वीट कर केंद्र सरकार को इस योजना पर तत्काल पुनर्विचार करने की सलाह दे डाली। राष्ट्रपति पद के सवाल पर भी नीतीश दो टूक कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। किसी से इस बाबत चर्चा भी नहीं की है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी वे भाजपा से असहमति जता चुके हैं। धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे भाजपाई राज्यों के कानूनों को भी उन्होंने खुलेआम खारिज किया है। जातीय जनगणना के सवाल पर भी वे भाजपा को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून का भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। वे हर मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ पलटवार करने में कितने मुखर हैं इसका उदाहरण उन्होंने इतिहास फिर से लिखने के मामले में भी किया।

अलग-थलग कांग्रेस

मौजूदा समय में कांग्रेस के लिए राजनीतिक दृष्टि से कई संदेश आ रहे हैं। पहला तो यह कि विपक्ष ने पूर्व भाजपा नेता और इस समय तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुन लिया है। दूसरा शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और उनके साथियों द्वारा उद्धव सरकार से बगावत करने के बाद महाराष्ट्र सरकार पर संकट गहरा गया है वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में भले ही कांग्रेस नेता सड़कों पर हैं, लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में प्रमुख विपक्षी दल खुलकर सामने नहीं आए हैं, अगर इन तीनों घटनाक्रमों को देखा जाए तो भविष्य की राजनीति में इसका सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर पड़ने वाला है। ऐसे में कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों में भी कांग्रेस अलग-थलग पड़ गई है। दरअसल देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन में कांग्रेस सीधे तौर पर मुख्य भूमिका में नहीं है। वह बैकफुट से ममता बनर्जी द्वारा प्रस्तावित यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है।

सीडीएस नियुक्ति की तैयारी

पिछले साल 8 दिसंबर को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के एक विमान हादसे में निधन के बाद से खाली पड़े चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नए सीडीएस की नियुक्ति को लेकर तैयारी तेज हो गई है। खबर है कि रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित तीनों रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी है। सीडीएस की नियुक्ति के लिए सरकार उन अधिकारियों पर विचार कर सकती है जो लेफ्टिनेंट जनरल समकक्ष या जनरल समकक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं। या ऐसे अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन नियुक्ति की तारीख को 62 वर्ष के नहीं हुए हों। बीते 25 मई को केंद्र सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना से वरिष्ठ सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम मांगे थे। सरकार ने यह कदम नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) की नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया के बीच में उठाया।

5 लाख के लिए फेरे पर फेरा

प्रदेश के एक रिटायर्ड प्रमोटी आईएएस अधिकारी इन दिनों काफी हैरान-परेशान हैं। साहब की परेशानी को देखकर कई लोग पसोपेश में हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल खबरचियों ने जब साहब की परेशानी का सबब जाना तो वे भी हैरान-परेशान हो गए। दरअसल, साहब खनिज संपदा वाले विभाग की निगरानी करने वाले विभाग में सीईओ के पद पर पदस्थ थे। लेकिन साहब जब तक यहां पदस्थ रहे, वे लक्ष्मीजी की कृपा नहीं पा सके। शायद इसी का असर है कि साहब ने समय से पहले वीआरएस ले लिया। लेकिन नियमों से अनभिज्ञ साहब ने वीआरएस नियमों के तहत अपनी तीन माह की सैलरी के एवज में 5 लाख रुपए जमा करा दिए। सूत्र बताते हैं कि जब साहब रिटायर्ड हो गए तो उन्हें किसी ने बताया कि यह नियम उन पर तब तक लागू होता था, जब तक उनका आईएएस अवार्ड नहीं हुआ था। दरअसल, नियम यह है कि अगर डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधिकारी वीआरएस लेता है तो उसे तीन महीने का वेतन जमा करना पड़ता है। आईएएस के लिए ऐसा नियम नहीं है। शायद साहब को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट के लिए तीन महीने के वेतन के रूप में 5 लाख रुपए जमा करा दिए। अब उक्त राशि को वापस लेने के लिए वे चक्करघिन्नी बने हुए हैं। यहां यह बता दें कि साहब को काफी विवादों के बाद आईएएस अवार्ड हुआ था।

दरियादिली संदेह के घेरे में

दरियादिल होना बड़प्पन की निशानी होती है, लेकिन इन दिनों एक केंद्रीय मंत्री के बंगले पर दिखाई जा रही दरियादिली संदेह के घेरे में आ गई है। आलम यह है कि प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में लोग सवाल खड़े करने लगे हैं कि माननीय के बंगले पर महीनेभर सन्नाटा छाए रहता है, फिर इतनी दरियादिली किस पर? दरअसल, विषय यह है कि पलायन करके सत्तारूढ़ पार्टी में आए माननीय केंद्र में मंत्री हैं। माननीय का राजधानी में एक प्यारा और न्यारा बंगला है। बंगले पर नौकर-चाकर के साथ तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन माननीय महीने में कभी-कभार ही बंगले पर आते हैं। लेकिन उनके बंगले पर हर महीने कम से कम 4 एलपीजी सिलेंडर की खपत हो रही है। इस अनियंत्रित खपत से खाद्य विभाग के अधिकारी भी परेशान हैं। क्योंकि जब न तब माननीय के बंगले से फोन आ जाता है कि हमें गैस सिलेंडर की जरूरत है। कृपया उसे भिजवा दीजिए। ऐसे में अब अफसरों ने पड़ताल शुरू कर दी है कि माननीय के न आने के बाद भी इतने सिलेंडर कहां खपाए जा रहे हैं। कहीं माननीय के बंगले पर तैनात नौकर-चाकर इन एलपीजी सिलेंडर को बेच तो नहीं रहे हैं। अब देखना यह है कि जांच के बाद किस पर आंच आती है।

माननीय की शिकायत पीएमओ पहुंची

अपने रंग-रूप, रवैये के कारण चर्चा में रहने वाले एक मंत्रीजी इन दिनों खासे चर्चा में हैं। इसकी वजह यह है कि मंत्रीजी की शिकायत प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। दरअसल, मंत्रीजी इन दिनों माई के मंदिर के नाम पर चंदा वसूली अभियान चला रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अपने आप को देवी का सबसे बड़ा भक्त बताने वाले मंत्रीजी अपने गृह जिले में माई का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। इसके लिए मंत्रीजी ने कवायद भी शुरू कर दी है। इस कवायद के तहत उन्होंने जमीनों पर कब्जा भी कर लिया है। सूत्र बताते हैं कि मंत्रीजी ने कई जमीनों को मंदिर के नाम पर कब्जा किया है। ऐसी ही एक जमीन का मामला विवाद में पड़ गया है। विवाद इस कदर बढ़ गया है कि इसकी शिकायत प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। जबसे यह खबर मंत्रीजी को लगी है उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि न जाने कब उन्हें दिल्ली से बुलावा आ जाएगा। बता दें कि इन दिनों मंत्रीजी के पास प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। हालांकि कई मामलों में मंत्रीजी की चल नहीं पा रही है। ऐसे में मंत्रीजी ने लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नया तरीका अपनाया है और माई का मंदिर बनाने का संकल्प लिया है। लेकिन इसके लिए जमीनों का जिस तरह कब्जा किया जा रहा है, उससे मामला विवादों में फंस गया है। अब देखना यह है कि माई के नाम पर उगाही मंत्रीजी पर भारी न पड़ जाए।

माननीय की लग गई लॉटरी

नगरीय निकाय चुनाव के घमासान के बीच एक माननीय को अपनी जेबें गर्म करने का ऐसा मौका मिल गया है कि उसे भुनाने के लिए उन्होंने पार्टी की प्रतिष्ठा को हथियार बना लिया। मामला प्रदेश की राजधानी का है। यहां अघोषित तौर पर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी संभालने वाले इन माननीय ने करीब दर्जनभर प्रत्याशियों की हार का डर दिखाकर 10 थाना प्रभारियों को इधर से उधर करने का मसौदा तैयार कर सरकार को दे दिया है। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश सरकार में बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले ये माननीय लक्ष्मीजी की कृपा पाने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। ऐसे में चुनाव का मौसम उनके लिए सुनहरा मौका बनकर आया है। बताया जाता है कि उन्होंने संगठन के पास प्रस्ताव भेजा है कि करीब दर्जनभर वार्डों में पार्षद प्रत्याशी हार के कगार पर हैं। अगर इनको जिताना है तो ये वार्ड जिस थाना क्षेत्र में आते हैं, वहां के थाना प्रभारियों को इधर से उधर कर दिया जाए। सूत्रों का कहना है कि हार-जीत तो बहाना है, माननीय ने मौके की नजाकत को देखते हुए पैसे के बल पर थाना प्रभारियों को उनका मनमाना थाना दिलाने का प्रयास किया है। देखना है दाल गलती है या नहीं।

विभाग की 'महाराज' ही मालिक

आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि इसका भगवान ही मालिक है... इसी तरह प्रदेश में एक विभाग ऐसा है, जिसकी मालिक 'महाराज' ही हैं। यानी कहावत के अनुसार जिसका भगवान मालिक होता है, वह उटपटांग हरकतें करता है। इसी तरह जिस विभाग की मालिक 'महाराज' हैं, उस विभाग में भी उटपटांग हरकतें होती रहती हैं। ऐसी ही एक उटपटांग हरकत इन दिनों चर्चा में है। दरअसल, विभाग के डायरेक्टर इन दिनों अपव्यय रोकने का अभियान चला रहे हैं। इसके लिए वे खर्चे कम कर रहे हैं, वहीं आमदनी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लेने आने वाले युवाओं पर फीस का आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। साहब के इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान युवा प्रशिक्षण लेने से वंचित हो सकते हैं। लेकिन साहब को इसकी फिक्र तनिक भी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि विभाग में खर्चों की कटौती के लिए उटपटांग कदम उठाने वाले साहब ने विभाग में अपने एक-दो चहेतों को संविदा नियुक्ति दे दी है। साहब का कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि विभाग की मालिक 'महाराज' जो ठहरीं।

मेट्रो की सुस्त रफ्तार

प्रदेश शासन के महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट मेट्रो रेल के लिए भोपाल और इंदौर में काम किया जा रहा है। इंदौर में मेट्रो के पहले चरण के लिए कई भारी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। प्रारंभिक हिस्से में पिलर निमार्ण के साथ अब गर्डर लांचिग का काम तेजी से किया जाएगा। वहीं भोपाल में एम्स से सुभाष नगर रेलवे ब्रिज के आगे तक करीब 6 किमी मेट्रो ट्रैक में अभी 30 पिलर, 15 सेगमेंट और रेलवे ब्रिज का काम होना बाकी है। वीर सावरकर सेतु से गणेश मंदिर की ओर रेलवे लाइन पर ट्रैक बिछेगा। इसका काम प्रक्रियाओं में है। हालांकि आजाद नगर समेत जमीन से जुड़ी दिक्कतें फिलहाल दूर कर ली गई हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अगले साल 15 अगस्त तक मेट्रो शुरू करने का टारगेट फिक्स किया है, पर जिस गति से काम चल रहा है, उस हिसाब से तब तक न तो स्टेशन तैयार हो पाएंगे, न डिपो और न ट्रेन आ सकेगी। नवंबर 2018 में शुरू हुए 6.22 किमी के सिविल वर्क की बाधाएं दूर करने में भी प्रशासन को दो साल का वक्त लग गया। डिपो व मेट्रो ट्रेन, सिग्नलिंग व ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन के लिए अभी टेंडर मंजूर नहीं हुआ है। यदि पूरी रफ्तार से काम चले तो इस साल के अंत तक प्रॉयोरिटी रूट का सिविल वर्क पूरा हो जाएगा। स्टेशन नवंबर 2023 तक पूरे हो पाएंगे। डिपो का काम शुरू होने के बाद पूरा होने में कम से कम दो साल लगेंगे और मेट्रो ट्रेन, सिग्नलिंग व ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन को केवल ट्रायल तक चलाने के लिए भी 2 साल का वक्त चाहिए, जबकि इस काम को शत-प्रतिशत पूरा होने में कम से कम 4 साल का वक्त लगेगा।

2023 में आमजन के लिए 6 किमी के शुरुआती हिस्से में मेट्रो शुरू करना है और इसके लिए काम में तेजी लाना होगी। सेगमेंट बिछने के बाद रेलवे ट्रैक ओर फिर सिग्नलिंग का काम करना है। एम्स से सुभाष नगर ब्रिज के आगे तक मेट्रो के 8 स्टेशन बनना है, जिसमें से 4 का जमीनी काम शुरू हो चुका है। हाल में मेट्रो रेल कारपोरेशन की एमडी छवि भारद्वाज ने स्टड फार्म पर डिपो व स्टेशन के काम का मुआयना किया था। एमपी नगर से लेकर साकेत नगर, एम्स की ओर स्टेशन के लिए खुदाई की जा रही है।

गणेश मंदिर से सावरकर ब्रिज की ओर से पिलर व सेगमेंट का काम चल रहा है तो बोर्ड ऑफिस के पास भी दो पिलर का काम किया जा रहा है। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों-अफसरों का कहना है कि एक साथ कई स्तरों पर काम किया जा रहा है, ताकि तय समय पर मेट्रो शुरू की जा सके। अभी मेट्रो के कोच, इंजन के साथ ही अन्य उपकरणों का काम भी शुरू कर दिया गया है। जल्द ही ये भी सबके सामने आएगी। भोपाल में रोहित एसोसिएट्स ने मेट्रो ट्रेन डीपीआर तैयार की थी, जिसके आधार पर यूरोपियन बैंक से लोन लिया गया है। पूरे शहर में 107 किमी लंबा मेट्रो ट्रैक प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए 6 कॉरिडोर तय किए हैं। हालांकि फिलहाल पहले कॉरिडोर की पहली लाइन पर ही काम किया जा रहा है।

परिवहन के साथ होगा जल संरक्षण

भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल के साथ हर साल 20 लाख लीटर बरसात के पानी की बचत होगी। इसके लिए एलीवेटेड ट्रैक के नीचे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। गर्डर पर बारिश का जितना पानी आएगा वह पाइप के जरिए भूगर्भ में जाएगा। बता दें कि पहले चरण में एम्स से सुभाष नगर तक प्रायोरिटी कॉरिडोर में वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 7 किलोमीटर के ट्रैक के साथ इनके बीच बनने वाले 8 स्टेशनों में बरसात के पानी को सीधे भूगर्भ में पहुंचाने के लिए पाइप लाइन डाली जा रही है। मप्र मेट्रो रेल के अधिकारियों ने बताया कि प्रायोरिटी कॉरिडोर में 226 पिलर बनना है। इनके बीच की दूरी 31 से 34 मीटर के बीच है। एक पिलर को छोड़कर यानी कि 65 से 70 मीटर की दूरी पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पाइप डाली जाएगी। इन पाइपों के सहारे पानी नीचे उतरकर ढाई मीटर की मिडियन में जाएगा। यहां कॉरिडोर के नीचे पानी के लिए रिर्चाज वेल होगा, जो पानी को साफ कर ग्राउंड लेवल में पहुंचाएगा। मेट्रो स्टेशनों और डिपो में बनने वाले पिट आयताकार होंगे जबकि एलीवेटेड रूट के नीचे बनने वाले पिट गोलाकार होंगे।

इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम सुपर कॉरिडोर, एमआर-10 से लेकर रिंग रोड तक तेज गति से चल रहा है। 600 से अधिक जो सेगमेंट प्री-कॉस्ट तैयार किए गए हैं, उन्हें गर्डर लॉन्चिंग क्रेन के जरिए लगाया जाएगा और उसके बाद पटरियों को बिछाने का काम भी शुरू होगा। गर्डर चढ़ाने के लिए दूसरी विशाल क्रेन भी इंदौर पहुंच गई है। वर्तमान में जारी कार्य में 31.55 किलोमीटर का पहला चरण पूरा किया जाएगा, जिसमें 29 स्टेशन बनेंगे। जिनमें 23 जमीन के ऊपर एलिवेटेड और आधा दर्जन अंडरग्राउंड स्टेशन रहेंगे। जानकारी के अनुसार अभी एमआर-10 से लेकर रिंग रोड तक चूंकि यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है और इससे यातायात अवरुद्ध भी हो रहा है, जिसके चलते रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तेजी से कार्य किया जा रहा है। वहीं 75 एकड़ जमीन पर मेट्रो डिपो का काम भी शुरू हो गया है।

वहीं गांधी नगर फुट ओवरब्रिज के समीप बनने वाले मेट्रो स्टेशन का भी काम शुरू हो चुका है। अगले साल अगस्त तक एक लाइन में मेट्रो चलाने का लक्ष्य भी रखा गया है। मप्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा इंदौर-भोपाल में मेट्रो के पहले चरण का काम कराया जा रहा है। एयरपोर्ट से सुपर कॉरिडोर, वहां से एमआर-10 होते हुए रिंग रोड, शहीद पार्क और उसके आगे रोबोट चौराहा तक इन दिनों काम चल रहा है। गर्डर लॉन्चिंग के लिए पिछले दिनों लोड टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक हो गई और एमआर-10 टोल नाके से शहीद पार्क तक 181 पिलर का निर्माण भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन पटरी में प्रवाहित विद्युत से चलेगी। दोनों जगहों पर मेट्रो चलाने के लिए थर्ड रेल डीसी ट्रैक्शन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक में खास बात यह है कि ट्रेन रुकने के दौरान ब्रेक लगाने से जो ऊर्जा बेकार हो जाती थी, अब उसे वापस सिस्टम में भेज दिया जाएगा।

● **कुमार विनोद**

कागजों पर भोपाल 'स्मार्ट'

केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना को किस तरफ पलीता लगाया जा रहा है, इसका नजारा भोपाल में देखा जा सकता है। राजधानी में स्मार्ट सिटी का क्षेत्र आज भी खंडहर बना हुआ है। योजनाएं आधी-अधूरी पड़ी हुई हैं, लेकिन करामाती अफसरों ने कागजों पर स्मार्ट सिटी को चकाचक बना दिया है। स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर केंद्र सरकार की वेबसाइट पर भरोसा किया जाए तो भोपाल में टीटी नगर स्मार्ट सिटी एबीडी का काम पूरा हो चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी योजना भोपालवासियों के लिए अभिशाप बन गई है। आज सात साल बाद भी जमीनी हकीकत बदहाल है।

सरकार के दावे अनुरूप स्मार्ट सिटी मिशन के परिणाम अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सात साल पहले स्मार्ट सिटी मिशन लांच करते वक्त लोगों को जीवन स्तर में सुधार लाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और शहर के समग्र विकास को बढ़ावा देने के जो सपने दिखाए थे वो अधूरे हैं। अफसर जिन योजनाओं को पूरा होना बता रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत जुदा है। कंपनी ने ऐसे कई कार्य करवा लिए हैं जो ड्राफ्ट में शामिल ही नहीं थे। ड्राफ्ट में शामिल कई परियोजनाओं पर काम ही नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर केंद्र सरकार की वेबसाइट पर भरोसा किया जाए तो भोपाल में टीटी नगर स्मार्ट सिटी एबीडी का काम पूरा हो चुका है। कोलार डैम से सप्लाई वाले इलाकों में 24 घंटे सातों दिन पानी मिल रहा है। ज्योति टॉकीज से बोर्ड ऑफिस **चौराहे पर टेक्टिकल अर्बनिज्म** एंड प्लेस मेकिंग का प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया है। इन तीनों प्रोजेक्ट की लागत 3093.52 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। एबीडी एरिया उजाड़ है। शहर में पानी सप्लाई का कोई ठिकाना नहीं है और ज्योति टॉकीज पर केवल शेड लगे दिखते हैं। नई कोलार लाइन का काम प्रोजेक्ट अमृत के तहत 130 करोड़ से हुआ है। लेकिन वेबसाइट बताती है कि 100 प्रतिशत घरों में मीटर लगाए जा चुके हैं। स्काडा भी लगाया गया है। जबकि स्काडा का काम शुरू ही नहीं हुआ है। एबीडी डेवलपमेंट की लागत 3000 करोड़ रुपए बताई गई है और इसे भी कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट में दिखाया गया है। जबकि यहां केवल एक बुलेवर्ड स्ट्रीट के अलावा कोई भी निर्माण पूरा नहीं हुआ है। हाट बाजार का काम भी अधूरा है।

कॉर्पोरेशन ने केंद्र सरकार से दावा किया था कि पांच साल में नॉर्थ और साउथ टीटी नगर की 333 एकड़ जमीन पीपीपी मोड पर विकसित की जाएगी। प्रोजेक्ट और जमीनें बेचकर 6644 करोड़ की आमदनी होगी, जबकि डेवलपमेंट कॉस्ट 3444 करोड़ आएगी। टीटी नगर में नॉलेज हब, एजुकेशन हब, एनर्जी हब, हेल्थ हब, इनोवेशन सेंटर सहित रेसीडेंस एवं कमर्शियल कैंपस बनाकर आधुनिक सुविधाएं देने का सपना दिखाया गया था। ठीक 7 साल पहले 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा की थी। भोपाल उन पहले 10 शहरों में शामिल था, जिन्हें स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया। आज भी केंद्र की रैंकिंग में कामकाज के आधार पर भोपाल की रैंकिंग अव्वल शहरों में है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटी पोर्टल पर हर शहर के पूरे हो चुके प्रोजेक्ट की लिस्ट दी गई है। भोपाल की इस लिस्ट को देखकर कोई भी चौंक जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल भोपाल ही नहीं, पूरे देश में यही हाल है। दुनिया के बेस्ट लिवेबल सिटी की लिस्ट आई है। इसमें भारत के शहर ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। होना यह चाहिए कि प्रोफेशनल प्लानर डेवलपमेंट प्लान बनाएं और प्रशासनिक अधिकारी व राजनीतिज्ञ उसे मिलकर लागू करें। लेकिन हमारे यहां इसके उलट होता है। प्लानर्स को कहा जाता है कि ऐसा प्लान बनाकर लाओ। स्मार्ट सिटी मिशन में भी कागज कुछ भी कहें लेकिन सच यही है कि न तो जनता की भागीदारी है, न प्लानर्स को शामिल किया गया है और जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट दिखाए गए हैं उनके हिसाब से बजट भी नहीं है।

भोपाल और इंदौर का तो 'स्मार्ट' होने लायक बजट भी लगभग खत्म हो गया है। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (एबीडी) हो या पैन सिटी प्रोजेक्ट दोनों में ही कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नजर नहीं आता, जिससे यह कहा जा सके कि यहां लोगों की जिंदगी स्मार्ट हो गई है। इन 7 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 650 प्रोजेक्ट पूरे होने थे। अब तक 386 ही पूरे हो पाए। 257 का काम जारी है। बाकी 7 अभी कागजों में हैं। ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 में पूरे होने थे, लेकिन अब केंद्र ने डेडलाइन बढ़ाकर 2023 कर दी है। काम की जो रफ्तार है, उस हिसाब से इनका डेडलाइन तक पूरा होना मुश्किल लग रहा है। बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इस दावे के साथ शुरू हुआ था कि शहरों को उनकी समस्याओं के इको फ्रेंडली हाईटेक सॉल्यूशन मिलेंगे। भोपाल, इंदौर और जबलपुर तो उन 20 शहरों में शामिल हैं जिन्हें 20 शहरों की पहली सूची में शामिल किया गया था।

● **अरविंद नारद**

अधूरे और लेट हुए प्रोजेक्ट्स की लिस्ट लंबी है...

27 करोड़ की स्मार्ट रोड पर डेडलाइन बीतने के 3 साल बाद ट्रैफिक शुरू हो गया, लेकिन फुटपाथ व साइकिल ट्रैक पर अतिक्रमण है। 40 करोड़ की बुलेवर्ड स्ट्रीट डेडलाइन से दो साल बाद शुरू हो पाई। यहां दूसरी सड़कों से आधा ही ट्रैफिक है। 175 करोड़ रुपए से 18 किमी की अन्य सड़कों का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। ये सितंबर 2020 तक बन जाना थीं। 42 करोड़ के अधूरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को स्मार्ट सिटी कंपनी बेचना चाहती है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा। 39 करोड़ के आर्च ब्रिज के लिए कंपनी के बजट से भुगतान हुआ। ट्रैफिक शुरू होने के बाद किलोल पार्क पर जाम की समस्या। 200 करोड़ के गवर्नमेंट हाउसिंग फेज-1 प्रोजेक्ट का 6वां टॉवर नाले को डायवर्ट करके बनाया जा रहा है। 525 करोड़ के गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट फेज-2 और फेज-3 का काम ठप हो गया है। इसे सितंबर 2020 में पूरा होना था। 180 करोड़ से महालक्ष्मी परिसर बीडीए के 551 फ्लैट तैयार, लेकिन अभी अलॉटमेंट का इंतजार। 31 करोड़ की लागत से स्मार्ट दशहरा मैदान नवंबर 2019 में पूरा होना था, पर काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। 41 करोड़ के वाटर स्काडा सिस्टम को बजट की कमी के कारण केवल नर्मदा प्रोजेक्ट तक सीमित किया जा रहा है।

मप्र में नगरीय निकाय चुनाव का घमासान चरम पर पहुंच गया है। भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस 16 नगर निगमों के महापौर की कुर्सी पर है। दोनों पार्टियों की कोशिश है कि अधिक से अधिक महापौर की सीटें जीतकर मिशन-2023 के लिटमस टेस्ट में पास हो जाएं। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरा दम लगा रखा है। क्योंकि इन चुनावों में दोनों नेताओं की साख दांव पर है।

दांव पर शिव-नाथ की साख

मप्र में 2022 और 2023 को चुनावी समर का साल कहा जा रहा है। अभी पंचायत और नगरीय निकाय के लिए घमासान हो रहा है तो 2023 में विधानसभा चुनाव के नगाड़े बजेंगे। माना जा रहा है कि 2023 के सत्ता के फाइनल मुकाबले के लिए पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव सेमी फाइनल जैसा होगा। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसलिए ये चुनाव दोनों नेताओं के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। प्रदेश में 347 नगरीय निकायों में चुनाव हो रहे है। इसमें 16 नगर पालिका निगम हैं, 76 नगर पालिका परिषद हैं और 255 नगर परिषद हैं। नगर निगम के चुनाव दो चरणों में होंगे। पहला चरण 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा। पहले चरण की मतगणना के परिणाम 17 जुलाई तक घोषित हो जाएंगे और दूसरे चरण के परिणाम 18 जुलाई को आएंगे।

इससे पहले चुनावी मैदान में दोनों पार्टियों के साथ ही शिवराज और कमलनाथ के लिए भी यह समय किसी चुनौती से कम नहीं है। भाजपा जहां सभी 16 नगर निगमों में अपना कब्जा बरकरार रखना चाहेगी, वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि वह इस बार भाजपा को मात देकर अपनी स्थिति मजबूत करे। गौरतलब है कि 2015 के नगरीय निकाय चुनाव की तो भाजपा के शत प्रतिशत मेयर चुने गए थे। भाजपा ने सभी 16 शहरों के मेयर पद पर कब्जा किया था। वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष के 97 पदों के निर्वाचन में 53 पर भाजपा ने और 39 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए हुए मुकाबले में भाजपा ने 154 और कांग्रेस ने 96 सीटें जीती थीं। जिला पंचायत और जनपद पंचायत चुनाव के आंकड़े भी भाजपा की तरफ झुके हुए थे। जिला पंचायत की 51 सीटों में से 40 पर भाजपा ने कब्जा किया था। कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें ही मिली थीं। जनपद पंचायत अध्यक्ष के 313 पदों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 214 और कांग्रेस ने 99 सीट जीती थीं।

लंबे अंतराल के बाद 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासनकाल में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे। साल 2003 तक कांग्रेस के शासनकाल में निकायों में कांग्रेस का दबदबा रहा। इसके बाद के 17 साल शिवराज सरकार ने राज किया। 2014-15 के बाद अब 7 साल के अंतराल के बाद हो रहे चुनाव में तगड़ा मुकाबला हो गया हैं। अपनी पसंद से **टिकिट वितरण** करके भाजपा की कमान शिवराज ने अपने हाथों में रखी है। वहीं, कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ संभाल रहे हैं, जिन्होंने अधिकांश टिकिट अपने सर्वे के आधार पर बांटे है। भाजपा को सभी 16 नगर निगम बचाने के लिए ताकत लगानी पड़ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि यह चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल हो सकता है। फिलहाल गांव और शहर में 4 लाख से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है। वैसे वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में शिवराज ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसानों की नाराजगी, शहरी क्षेत्रों में असंतुलित विकास उनके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तो उनके लिए 2020 में सत्ता गंवाने के बाद यह चुनाव बड़े मौके की तरह है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हीं के हाथ में कमान थी और कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी थी। अपनी पसंद के लोगों को टिकिट दिलाने के कारण दोनों पर ही बेहतर प्रदर्शन का दबाव है। दोनों ही नेताओं ने राजनीतिक सभाओं के माध्यम से जोर अजमाइश शुरू कर दी है। प्रदेश में हो रहे पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए इन चुनावों में भाजपा और कांग्रेस ने अपना पूरा दम लगा दिया है। कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि निकाय चुनाव में भाजपा के अभेद गढ़ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में पार्टी के महापौर प्रत्याशी को हर हाल में जिताना है।

11 सीटों पर आमने-सामने की लड़ाई

प्रदेश के 16 नगर निगम में महापौर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। चुनावी रण में 13 सीटें ऐसी हैं, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा की नजर में छिंदवाड़ा, सागर और सिंगरौली में कड़ी टक्कर है। भोपाल और इंदौर कॉडर के दम पर जीतने की उम्मीद है, लेकिन चुनावी जंग दिलचस्प हो गई है। 11 सीट पर मुकाबला तगड़ा है। भाजपा ने संगठन और कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर हर शहर की रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के बाद मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और संगठन के नेता रण में झोंके गए हैं। इधर, कांग्रेस भी सभी 16 नगर निगम में जीत की व्यूहरचना तैयार कर मैदान में उतरी है। भाजपा से मालती राय प्रत्याशी हैं। विधायक विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर की पसंद का टिकट है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर साथ हैं। नेता एक साथ प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल को पार्टी के परंपरागत वोट बैंक, मुस्लिम वोट और किरार समाज की एकजुटता के भरोसे जीत की उम्मीद है। आप से रानी विश्वकर्मा ने परचा वापस ले लिया। यहां 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है। सबसे बड़े निगम में कमल और पंजे के बीच सीधी लड़ाई है। दोनों दलों ने ब्राह्मण चेहरे उतारे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला दो महीने से प्रचार कर रहे हैं। भाजपा ने 40 वर्ष के युवा लॉयर पुष्यमित्र भार्गव को उतारा है। कोई तीसरा फेक्टर नहीं है। भाजपा की चुनौती क्षत्रप नेताओं की एकजुटता की है, जबकि संजय चुनावी रण में बिखरी कांग्रेस की जगह अपने दम पर ही मुकाबला लड़ रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस से विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा लड़ रही हैं, जबकि भाजपा ने सुमन शर्मा को लड़ाया है।

अगर इन चार नगर निगमों पर पार्टी ने कब्जा जमा लिया तो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की राह आसान हो जाएगी। दरअसल, 2020 में सत्ता से बाहर होने के बाद से ही कांग्रेस वापसी के प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि तैयारियों और सक्रियता में वह भाजपा के आसपास भी नहीं है। फिर भी कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर उम्मीद से लबरेज है, पर निकाय चुनाव में प्रमुख शहरों के महापौर पद पर मिलती शिकस्त को जीत में बदलना उसके लिए चुनौतीपूर्ण है। दरअसल, सूबे के चारों प्रमुख शहरों के महापौर पद भाजपा के अभेद किले हैं। ग्वालियर में सबसे ज्यादा 58 साल से कांग्रेस महापौर पद से दूर है। इंदौर में 22 साल, जबलपुर में 16 साल और भोपाल में 13 साल से महापौर पद पर भाजपा का कब्जा है। अब भाजपा के लिए भी इन सीटों को बचाने की चुनौती है।

मप्र के निकाय चुनाव में जिस बात की आशंका थी, वो सच भी साबित होता दिख रहा है। पार्टियां एकजुटता के दावे करती रहीं, उधर कुनबा बिखरता रहा। नाराज दावेदारों को दिग्गज मनाते रहे, लेकिन साथी बागी बने रहने पर आमादा दिखे। अब नौबत ये है कि निकाय चुनाव में भाजपा-कांग्रेस दोनों में ही बागी भरे पड़े हैं। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ ही सियासी रण में अपने ताल ठोंक रहे हैं। बागियों की वजह से ना सिर्फ पार्टियों को हार का खतरा सता रहा है, बल्कि लोकल लेवल पर सियासी समीकरण भी बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बागी जीते तो आगे के लिए उस वार्ड में दबदबे वाली पार्टी की चुनौती बढ़ जाएगी। वैसे सवाल सुर्खियों में है कि आखिर घर में ही घमासान की नौबत क्यों आई? तो कहा जा रहा है कि कई जगहों पर सिफारिश पर टिकट दिए गए हैं। दिग्गजों की पैरवी पर टिकट बांटे जाने की बात भी कही जा रही है। जो पहले से काम कर रहे थे, उनकी दावेदारी कमजोर पड़ गई। सर्वे में जो नाम आए थे, उनकी अनदेखी की गई। इससे नाराज होकर दावेदार निर्दलीय मैदान में उतर गए। हालांकि, भाजपा-कांग्रेस दोनों को इस बात का अहसास है कि टिकट बंटवारे में चूक हुई है, लेकिन

उम्मीदवारों के पैरवीकार ही क्षेत्रीय क्षत्रप थे, इसीलिए ज्यादा जगहों पर बदलाव संभव नहीं हो सका और बागियों को मनाने में कामयाबी नहीं मिल पाई।

नगर निगम चुनाव के लिए नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद अब 16 नगर निगमों में स्पष्ट हो गया है, कि इस बार चुनावी मुकाबला काफी रोचक है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के चुनावी गणित को बिगाड़ने की कोशिश में आम आदमी पार्टी भी जुटी है, वहीं दोनों ही दलों को टिकट बंटवारे की वजह से कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भी झेलना पड़ रहा है। भोपाल नगर निगम में मेयर का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि यहां नगर निगम में मेयर के अब 8 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। इनमें भाजपा से मालती राय, कांग्रेस से विभा पटेल, बसपा से प्रिया मकवाना, जनता दल (यूनाइटेड) की मंजू यादव, जय लोक पार्टी की संगीता प्रजापति, निर्दलीय लेखा जायसवाल, रईसा बेगम मलिक और सीमा नाथ शामिल हैं। रईसा मलिक ने आम आदमी पार्टी से नामांकन भरा था, लेकिन उन्हें पार्टी ने मेंडेड नहीं दिया। इस कारण वे निर्दलीय हो गई हैं। अब इन्हीं प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। इंदौर में मेयर पद के लिए मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल सकता है। यहां कुल 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें पुष्यमित्र भार्गव (भाजपा), संजय शुक्ला (कांग्रेस), कमल कुमार गुप्ता (आप), कुलदीप पवार (एनसीपी), बाबुलाल सुखराम (निर्दलीय), डॉ. संजय बिंदल, (निर्दलीय), नासिर मोहम्मद सहित सभी 19 प्रत्याशी हैं। इनमें से किसी ने नामांकन वापस नहीं लिया है। 17 बार चुनाव हार चुके और इंदौर से सबसे पहले नामांकन फॉर्म जमा करने वाले परमानंद तोलानी भी मैदान में डटे हुए हैं। ग्वालियर नगर निगम में महापौर पद के लिए 7 महिलाएं मैदान में हैं। जिनके बीच कड़ा मुकाबला होगा। इनमें भाजपा से सुमन शर्मा, कांग्रेस से डॉ. शोभा सतीश सिकरवार, आम आदमी पार्टी से रूचि गुप्ता, बहुजन से सुनीता गौतम, अन्य दलों से सुनीता पाल, विद्याबाई पत्नी खेमराज, हेमलता पत्नी मुकेश सोनी मैदान में हैं। नगर निगम जबलपुर में महापौर पद के लिए अब 11 उम्मीदवार महापौर के लिए मैदान में हैं। जगत बहादुर सिंह (कांग्रेस), लखन अहिरवार (बहुजन समाज पार्टी), इंद्रकुमार-निर्दलीय, रश्मि पोर्ते-(गोंडवाना गणतंत्र पार्टी), शशि स्टैला-निर्दलीय, सचिन गुप्ता-(स्मार्ट इंडियन पार्टी), डॉ. जितेंद्र जामदार (भाजपा), राजेश सेन-निर्दलीय, भूपेंद्र मेहरा-निर्दलीय, राजकुमार त्रिपाठी-निर्दलीय, विनोद कुमार-जनता दल(यू)। भाजपा के प्रहलाद पटेल, कांग्रेस के मयंक जाट, आम आदमी पार्टी के अनवर खान, समाजवादी पार्टी की आफरीन खान, नेशनलिस्ट पार्टी के जहीरूद्दीन और भाजपा के बागी उम्मीदवार अरुण राव महापौर पद के मुकाबले में बचे हुए हैं।

● **कुमार राजेन्द्र**

कांग्रेस के लिए बड़े निगम चुनौती

नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़े नगर निगम जीतना किसी चुनौती से कम नहीं हैं। दरअसल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर भाजपा के अभेद गढ़ बन चुके हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस को उम्मीद की लौ दिखी है। इस बार राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने पूर्व महापौर विभा पटेल को महापौर प्रत्याशी बनाया है। भोपाल में कांग्रेस की स्थिति ठीक है, पर यहां 13 साल भाजपा के महापौर रहे हैं। कांग्रेस से आखिरी महापौर सुनील सूद थे, जो 20 दिसंबर 2004 से 20 दिसंबर 2009 तक पद पर रहे। फिर भाजपा से कृष्णा गौर, आलोक शर्मा ने जीत हासिल की। सूद से पहले कांग्रेस की विभा पटेल 8 जनवरी 2000 से 7 अगस्त 2004 तक महापौर थीं। इस बार विभा ने कांग्रेस में आस जगाई है। भोपाल की सीट से कांग्रेस उम्मीदें संजोए है। इसके पीछे विभा की पिछली जीत और दिग्विजय खेमे के मजबूत नेटवर्क का सपोर्ट होना है। कांग्रेस सड़क पानी, परिवहन, बिजली बिल जैसे मुद्दे उछाल रही है। वहीं भाजपा से मालती राय मैदान में हैं। भाजपा के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। भाजपा विकास के आधार पर चुनाव लड़ रही है। वहीं सत्ता-संगठन और तीनों भाजपा विधायक साथ हैं।

बर्बरता की हद!

भड़काऊ बयानों पर अंकुश जरूरी

उदयपुर की घटना के बाद जिस तरह से हत्यारे अपने चाकू लहराकर इसे अपनी जीत बता रहे थे, तो उनकी बेवकूफी पर तरस आया। उन्होंने अपने एक ऐसे धार्मिक विश्वास के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया जिसका उन्हें इल्म भी नहीं कि वह ठीक है या नहीं। क्या उनकी इस हरकत से उन्हें जन्नत नसीब होगी या नहीं, लेकिन आम मुसलमानों के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। उन दोनों हत्यारों ने एक आदमी का कत्ल किया और ऐसा करके करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी की मुश्किलें बढ़ा दीं। इस बीच, अपने जहरीले बयानों के लिए बदनाम एआईएमआईएम के नेता सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी कन्हैयालाल की हत्या की निंदा की है। पर जब उन्हीं की पार्टी के लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा के बयान पर विरोध जताने के लिए एक रैली में शामिल हुए थे तब नुपुर शर्मा का सिर काटने के नारे लग रहे थे। इम्तियाज जलील ने उन शातिर लोगों को एक शब्द भी कुछ नहीं कहा था जो नारेबाजी कर रहे थे। भारत को गर्त में झोंकने की कोशिश करने वालों को कुचलना होगा। केंद्र तथा राज्य सरकारों को कन्हैयालाल के हत्यारों और उनकी मानसिकता रखने वाले सभी को कुचलना होगा। इस बिंदु पर अगर-मगर का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर सरकारें ये भी नहीं कर सकती तो फिर तो देश राम भरोसे ही चलेगा।

उदयपुर में एक नवयुवक दर्जी कन्हैया लाल की बर्बरतापूर्ण ढंग से गर्दन काटने की घटना पर देश का गुस्सा या हैरानी जायज है। आखिर ये भारत को सीरिया या इराक बनाने की एक असफल किंतु दुस्साहसपूर्ण कोशिश है। इन दोनों देशों के वीडियो हमने देखे हैं जिनमें किसी भी मासूम की गर्दन कैसे बर्बरतापूर्वक कलम की जा रही होती थी। पर यह हमारे ही हिंदू बहुल मुल्क में ही होगा यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह मत भूलिए कि नुपुर शर्मा की सर तन से जुदा की मांग तो लगातार हो ही रही थी। खुल्लम-खुल्ला ऐलान भी हो रहा था कि नुपुर शर्मा के धड़ को गर्दन से अलग कर दिया जाएगा। पर हैरानी की बात यह है कि नुपुर शर्मा के प्रति सहानुभूति रखने वाले किसी निर्दोष शख्स की भी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। अब बचा ही क्या है।

निर्दोष की जान लेना शौर्य नहीं एक घृणित अमानवीय कृत्य है। तमाम चीजों से जूझ रहे देश को शांति की ज्यादा जरूरत है वह भी उस स्थिति में जब कई नेता, खासकर कट्टरपंथी धार्मिक गुरु और उलेमा गृह युद्ध की आशंका तक जता रहे हैं कई दिनों से। अब कौन सुरक्षित रह गया है इस देश में कोई भी तो नहीं। कुछ तालिबानी तत्व भारत में जिस तरह से बढ़ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक है। इस्लाम में सुधार तो अब दूर की बात ही दिखती है। पहले इस्लाम से जुड़े विद्वानों को यह चिंता करनी होगी कि ऐसे तालिबानी तत्वों को किस तरह से अलग-थलग करें और इस मजहब को मुल्ला मौलवियों की जकड़न से कैसे मुक्त किया जाए।

अभी देश में अल्लाह के इस्लाम की जगह मुल्ला के इस्लाम को चलाने की कोशिश हो रही है! अगर इस्लाम से जुड़े लोग ऐसे तत्वों की मुखालफत में तुरंत सामने नहीं आते, अपने नौजवानों को कट्टरपंथ के जहर से मुक्त करने की कोशिश नहीं करते, तो क्यों न मान लिया जाए कि वे भी इन तत्वों का साथ दे रहे हैं? उदयपुर में जो कुछ हुआ क्या यह पहली घटना है या फिर आपको लगता है यह आखिरी है। नहीं यह तो एक सिलसिला सा कायम किया जा रहा है। यह भी समझना होगा है कि हजारों की भीड़ जो नारे लगा रही थी सर तन से जुदा वह क्या कन्हैयालाल की मौत से दुखी हुई होगी? क्या वे लोग इस कत्ल में शुमार नहीं है? ये तमाम लोग अभी दुआ कर रहे होंगे और वे दुआ किसके लिए होगी आप समझ सकते हैं। उदयपुर की घटना में जरा राजनीतिक साजिश को भी देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की मांग की है।

हत्या के बाद कांग्रेस की सक्रियता की तारीफ हो रही है। मुआवजा देने, गिरफ्तारी और त्वरित मामले की सुनवाई को लेकर। कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत सोशल मीडिया पर उसकी टीम अशोक गहलोत सरकार के एक्शन को आदर्श की तरह प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस के साथ नजर आने वाला विपक्ष भी प्रतिक्रिया देने में पीछे नहीं रहा। आनंद पटवर्धन जैसे लोगों ने भी निंदा की है। ब्रदरहुड का नारा देने वाले और कतर की जीडीपी से भारत की औकात बताने वाले भी निंदा कर रहे हैं। वक्त का तकाजा है कि अशोक गहलोत प्रधानमंत्री मोदी से अपील करने की बजाय अपने राजस्थान को जरा संभालें। अन्य राज्यों में सक्षम सरकारें हैं और वे एहतियात भी बरत रही हैं। क्या गहलोत एक तरह से दबाव की राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या वे राजस्थान की घटना की जिम्मेदारी लेने से बच नहीं रहे हैं?

उदयपुर से आ रही खबरों से साफ है कि राजस्थान सरकार कन्हैयालाल को सुरक्षा देने में नाकाम रही। कन्हैयालाल को पता था कि उसकी जान को खतरा है। उसने पुलिस में शिकायत भी की। वह कई दिनों से अपनी दुकान पर भी नहीं गया था। पर अशोक गहलोत के राज्य की पुलिस ने धमकी देने वालों को पकड़ने की बजाय उस बेचारे कन्हैयालाल को सतर्क रहने की हिदायत दी। ना तो आरोपियों को गिरफ्तार करने में दिलचस्पी दिखाई और ना ही पीड़ित को सुरक्षा देने में। अशोक गहलोत सरकार को बताना चाहिए कि आतंकियों की धमकी मिलने के बाद भी कन्हैयालाल को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? वह भी तब जब आरोपियों ने धमकी का वीडियो भी जारी कर दिया गया था। सारा देश जानता है कि राजस्थान बीते कई महीनों से जल रहा था। वहां दंगे भी हुए। नुपुर शर्मा मामले में जिस तरह बखेड़ा हुआ था उसके मद्देनजर तो इस मामले में और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत थी। पर यह नहीं हुआ।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

सरकारी भवनों में लगेंगे प्रीपेड मीटर

मप्र के सभी शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। यह प्रीपेड मोबाइल की तरह ही होगा। उपभोक्ता उतनी ही यूनिट बिजली का उपभोग कर पाएंगे, जितने का रीचार्ज कराएंगे। यह लगातार अपडेट करता रहेगा कि कितनी बिजली की खपत कर रहे हैं। महीने का बिल तैयार करने के लिए विभाग के मीटर की रीडिंग नहीं लेनी पड़ेगी। बिल उपभोक्ताओं के ई-मेल या वाट्सएप नंबर पर भेजा जाएगा। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव को पत्र लिखकर कहा कि भारत सरकार द्वारा 26 मई 2022 के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर का अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन 2019 के प्रावधानों के अनुसार में मौजूदा मीटरों की पूर्व भुगतान करने प्रीपेड स्मार्ट मीटरों से बदलने की समयसीमा निर्धारित की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार दिसंबर 2023 तक पूर्ण भुगतान (प्रीपेड) स्मार्ट मीटरों से मीटरीकृत किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से रिवेम्पड़ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) जारी की गई है। योजना अंतर्गत स्मार्ट मीटरों की स्थापना तथा वितरण कंपनियों की हानियों में कभी वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य किए जाने हैं। इस हेतु केंद्र सरकार द्वारा 15 फीसदी तथा 60 फीसदी अनुदान प्रदान किया जा रहा है। योजनांतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पूर्व आर्हताओं में यह प्रावधान भी है कि सभी सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, संबंधी कार्यालयों, स्वशासी संस्थाओं में प्रतिबद्धता के अनुसार प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाएं। स्वीकृत शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि को ऋण में परिवर्तन कर दिया जाएगा। इससे वितरण कंपनियों के अधोसंरचना, उन्नयन इत्यादि के कार्य प्रभावित होंगे। साथ ही वाणिज्यिक साध्यता भी प्रभावित होगी। अत: यह आवश्यक है कि वितरण कंपनियों द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों स्थानीय निकायों, संबंधित कार्यालयों स्वशासी संस्थाओं में निर्धारित समयसीमा अंतर्गत दिसंबर 2023 तक मौजूदा मीटरों को पूर्व भुगतान वाले स्मार्ट मीटरों में बदला जाए। इसके लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

गौरतलब है कि जून के मध्य में बिजली कंपनियों के कर्मियों के आत्मनिरीक्षण पर केंद्रीय मंथन-2022 कार्यशाला में बिजली हानि कम करने और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की आर्थिक सेहत सुधारने की दो योजना पर अगले कुछ महीने में अमल करने की घोषणा की गई थी। पहला सबसे अधिक हानि वाले क्षेत्रों में सबसे पहले एबी केबलिंग या भूमिगत केबलिंग के कार्य कराए जाएं। दूसरा सरकारी भवनों में प्रीपेड मीटर लगाया जाए। इससे उधारी बंद होगी और नकदी की समस्या दूर होगी। मंथन-2022 में ऑनलाइन जुड़े केंद्रीय विद्युत सचिव आलोक कुमार ने कहा था कि मप्र के तीनों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को हानि वाले क्षेत्रों में सबसे पहले एबी केबलिंग और अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य करना चाहिए। इसके समानांतर स्मार्ट व प्रीपेड मीटरिंग का कार्य भी करें। मप्र की बिजली वितरण कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर और त्वरित सेवाएं मिल सकें।

प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कहा था कि मप्र में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आरडीएसएस योजना को लागू किया जा रहा है। इस पर 24 हजार करोड़ रुपए अगले कुछ सालों में खर्च होंगे। इसमें 8700 करोड़ रुपए स्मार्ट एवं प्रीपेड मीटरिंग पर खर्च होने हैं। वहीं 15 हजार 400 करोड़ रुपए अधोसंरचना की मजबूती पर व्यय किए जाएंगे। प्रमुख ऊर्जा सचिव ने कहा कि ब्लॉक स्तर तक लगभग 8 हजार शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट व प्रीपेड मीटर प्राथमिकता से लगाए जाएंगे। इससे हर महीने 600 से 700 करोड़ रुपए की उधारी बंद हो जाएगी।

प्रदेश में अधिकतर सरकारी भवनों में या तो मीटर खराब पड़े हैं या फिर औसत बिलिंग की जाती है। सरकारी भवनों पर बकाया होने के बावजूद पावर कट विभाग नहीं कर पाता है। हर महीने करोड़ों का बकाया होने पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की आर्थिक हालत गड़बड़ा जाती है। प्रदेश में जबलपुर, भोपाल, इंदौर व ग्वालियर नगर निगम का ही हर महीने का बिल 100 करोड़ रुपए बनता है। इसके अलावा अन्य निकायों का लगभग 250 करोड़ का बिल बनता है। इतना ही बिजली खर्च अन्य सरकारी भवनों का महीनेभर का है। मतलब 600 से 700 करोड़ हर महीने 8 हजार सरकारी भवनों में खर्च होते हैं। प्रीपेड व स्मार्ट मीटर लगाने से ये राशि हर महीने कंपनी को नकद मिलेगी।

सामान्य मीटर से अलग ये स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर होगा। इसमें मोबाइल की तरह बिजली का रिचार्ज होगा। उपभोक्ता उपयोग के अनुसार बिजली का रिजार्च करवा सकता है। मीटर में हर वक्त बिल की खपत के साथ बकाया यूनिट संबंधी जानकारी प्रदर्शित होगी। उपभोक्ता के मोबाइल पर भी रिचार्ज समाप्ति का मैसेज आएगा और मोबाइल से रिचार्ज कराया जा सकेगा। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने सुझाव बिजली वितरण कंपनियों को कहा है कि वे मप्र विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल करें, कि रात में प्रीपेड मीटर के कनेक्शन न बंद हों। भले ही उपभोक्ता का रिचार्ज खत्म हो जाए। दोबारा रिचार्ज के लिए कुछ दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए। ताकि किसी वजह से उपभोक्ता प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं करवा पाए, तो उसे दोबारा रिचार्ज करवा सके।

● **राकेश ग्रोवर**

पावर सेक्टर को पेपरलेस की ओर बढ़ना होगा

प्रमुख सचिव ने कहा कि रेलवे व बैंकों की तरह पूरा स्टेट पावर सेक्टर पेपरलेस कार्य करने की मानसिकता बना लें। तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करें। इससे कम मैनपावर में हम अधिक कार्यकुशलता दिखा पाएंगे। पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी विवेक पोरवाल ने कहा कि भविष्य में प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 40 फीसदी हो जाएगी। इसको देखते हुए पावर मैनेजमेंट कंपनी में एक अलग प्लानिंग सेल का गठन होना चाहिए। उपभोक्ताओं को भी सोलर रूफटॉप स्थापित करने के लिए प्रेरित व उत्साहित करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा की अधिकता और उपलब्धता से सस्ती बिजली मिल सकेगी। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में बढ़ती बिजली की मांग एक चुनौती है। इस ओर विशेष ध्यान देना होगा।

महिला पुलिस की तादात 10 फीसदी भी नहीं

मप्र-तेलंगाना फिसड्डी

मप्र और तेलंगाना देश के उन राज्यों में शामिल हैं जहां पुलिस में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। मप्र में 100 में मात्र 6 पुलिसकर्मी महिलाएं हैं, तेलंगाना में 100 में मात्र 5 पुलिसकर्मी महिलाएं हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का अध्ययन है कि पिछले तीन सालों में तकरीबन सभी राज्यों में पुलिस फोर्स में महिलाओं की नियुक्ति बढ़ी है, लेकिन हरियाणा, गोवा, मिजोरम इसके अपवाद रह गए हैं। यानी यहां महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में गिरावट हुई है। भारत में महिला सशक्तिकरण के दावे भले ही जोर-शोर से किए जाते रहे हों, लेकिन पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। भारत में हर 10 पुलिसकर्मियों में मात्र 1 महिला है, जबकि 9 पुलिसकर्मी पुरुष हैं। 2017 में देश में पुलिस की भागीदारी 7 प्रतिशत थी जो कि अब मामूली रूप से बढ़कर 10 फीसदी हो गई है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में राज्यों की न्याय करने की क्षमता का पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी मदद जैसे मानकों पर आंकलन किया जाता है।

प्रदेश में महिलाओं के लिए पुलिस बल में 33 फीसदी आरक्षण का निर्णय लिया है, लेकिन विडंबना यह है कि प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की तादात 10 फीसदी भी नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार की योजना अनुसार प्रत्येक थाने में 13 महिला पुलिसकर्मी की तैनाती कैसे की जाएगी। केंद्र के इस आंकड़े की तुलना में प्रदेश का आंकड़ा बेहद कमजोर है। स्थिति यह है कि मप्र के पुलिस थानों में 13 तो दूर, तीन महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार देशभर के पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में हैं। केंद्र की योजना प्रत्येक थानों में 13 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। इस योजना पर तेजी से काम भी हो रहा है, लेकिन इस मामले में मप्र की स्थिति बेहद लचर है। मौजूदा स्थिति में प्रदेश में मैदानी पदस्थापना में महिला पुलिसकर्मियों की तादात 9.81 फीसदी है। प्रदेश पुलिस की सभी 104 इकाइयों को मिला दिया जाए, तो यह आंकड़ा डेढ़ फीसदी को भी पार नहीं कर रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रदेश में केंद्र सरकार की मंशा कैसे पूरी होगी।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में एक लाख 26 हजार पुलिस बल मौजूद है। इनमें से महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 9.81 प्रतिशत है। यह आंकड़ा मैदानी पुलिसकर्मियों का है। अफसरों की माने तो डीएसपी स्तर पर महिलाओं की संख्या 30 फीसदी के पार है। उसके नीचे यानी आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक का आंकड़ा 10 फीसदी से कम है। प्रदेश पुलिस में कुल 104 इकाइयां हैं। बहुत सारी इकाइयों में महिलाओं की संख्या एक फीसदी भी नहीं है। उस हिसाब से प्रदेश पुलिस में महिलाओं का आंकड़ा 1.26 प्रतिशत बैठता है। यह सही है कि फॉल्ड पोस्टिंग (मैदानी पदस्थापना) में संख्या 10 फीसदी के करीब है, लेकिन केंद्र की योजना की तुलना में यह आंकड़ा भी बहुत कम है।

केंद्र सरकार ने महिला पुलिस की भागीदारी 33 प्रतिशत करने के लिए सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जो राज्य पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 33 प्रतिशत नहीं करेंगे, उनके **मॉडर्नाइजेशन फंड** पर रोक लगा दी जाएगी। केंद्र सरकार का ये मानना है कि बिना सख्ती के राज्य सरकारें इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहीं। अगर फंड में कटौती होती है तो राज्य सरकारें महिलाओं की भर्ती बड़े पैमाने पर करेंगी। बता दें कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 26 हजार करोड़ रुपए का फंड तय किया गया है। केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि देश के हर पुलिस थाने में एक महिला हेल्पडेस्क बनाना जरूरी हो। इसके लिए राज्यों से हर पुलिस स्टेशन में कम से कम 3 सब इंस्पेक्टर और 10 सिपाही महिलाएं होनी चाहिए। इसके लिए नई भर्तियां जल्द शुरू होंगी। इस सिलसिले में गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक और पत्र लिखा है। इसमें याद दिलाया गया है कि उन्हें पुलिस बलों में 33 फीसदी महिलाएं सुनिश्चित करने के लिए 10 साल में 5 बार लिखित रूप से कहा गया है। बता दें कि पहला अनुरोध पत्र 20 अप्रैल 2013, दूसरा 21 मई 2014, तीसरा 12 मई 2015, चौथा 21 जून 2021, और पांचवा पत्र 22 जून 2021 को भेजा गया है।

प्रदेश पुलिस में कुल बल का तकरीबन 40 फीसदी बल एसएएफ का है। एसएएफ में महिलाओं की संख्या नहीं के बराबर है। कमोबेश इसी तरह के हालात दूसरी इकाइयों में हैं। अफसरों की माने तो विभाग में एसएएफ के साथ टेलीकॉम, महिला सेल सहित तमाम शाखाएं हैं। कुछ सालों में महिला सेल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ी है। हां, दीगर थानों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत है। मौजूदा स्थिति है कि भोपाल जिले के सभी थानों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं है। शहर के कुछ प्रमुख थानों को छोड़ दिया जाए, कई थाने तो ऐसे भी हैं, जहां पर एक-एक महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में महिला पुलिसकर्मियों का आंकड़ा तो थोड़ा ठीक-ठाक कह सकते हैं, लेकिन अन्य जिलों में स्थिति बहुत खराब है। अफसरों की माने तो तकरीबन 25 से 30 फीसदी थाने ऐसे हैं, जहां पर अभी तक महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं है।

मप्र सरकार पुलिस विभाग में महिलाओं की हिस्सेदारी को 33 फीसदी करना चाहती है। भर्ती को लेकर सरकार के तमाम दावे भी हैं, लेकिन असल में स्थिति कमजोर है। कुछ सालों में महिलाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी गई है, लेकिन आंकड़ा बराबरी में आने में बहुत वक्त लगेगा। मैदानी पदस्थापना में महिलाओं की संख्या कम होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि भर्ती के बाद महिलाएं मैदानी पदस्थापना में रुचि नहीं रखती हैं। तमाम पारिवारिक कारणों का हवाला देकर वे ऑफिस में अपनी पदस्थापना करा लेती हैं। फील्ड की पदस्थापना 24 घंटे की होती है, जबकि दफ्तरों में रहती है। बहरहाल बदलते दौर में महिला पुलिसकर्मियों में मैदानी पदस्थापना की दरकार है, क्योंकि कानून व्यवस्था लेकर तमाम तरह की स्थितियों से जूझना पड़ता है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

गांव अभी भी बदहाल

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान प्रदेश में गांवों की बदहाली की ऐसे तस्वीरें आ रही हैं जो डिजिटल इंडिया के इस दौर में हैरान करने वाली हैं। एक ओर जहां केंद्र और राज्य सरकार गांव-गांव तक सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन, नलजल योजना के तहत पानी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मार्ग प्रदान करने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में हजारों ऐसे गांव हैं जहां की आबादी सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रही है। हैरानी की बात यह है की डिजिटल इंडिया के इस दौर में आज भी प्रदेश के गांवों की आधी आबादी शुद्ध पानी के लिए तरस रही है। वहीं 2081 गांव अब तक अंधेरे में हैं, वहीं 2200 गांवों तक सड़क भी नहीं पहुंच पाई है। पंचायत चुनावों में सीधे तौर पर कोई राजनीतिक दल सामने नहीं है पर उम्मीदवारों की राजनीतिक आस्थाएं जरूर हैं। चुनाव के बाद दावे होंगे कि हमारे इतने पंच-सरपंच या जनपद और जिला पंचायत सदस्य जीतकर आए हैं। लेकिन, जीत के बाद जनप्रतिनिधि इन गांवों का कितना भला कर पा रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। गांवों में लोग आज भी पानी, बिजली, सड़क आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं।

2,200 गांव में सड़क ही नहीं

मप्र में सरकारी दावों के अनुसार सड़कों का जाल गांव से लेकर शहर तक बिछा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी लगभग 2,200 गांव में सड़क नहीं पहुंच सकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 90,577 किलोमीटर लंबी सड़कें बननी थी। अभी 5 हजार किमी सड़कें बाकी हैं। हालांकि योजना में लगभग 17 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। राज्य सरकार ने इस साल बजट में 3 हजार किमी लंबी नई सड़कें बनाने और 1,250 किमी सड़कों के नवीनीकरण का प्रावधान किया है। इनमें गांवों की 709 सड़कों को लिया गया है। जिलों से जुड़ने वाली 111 सड़कों का अपग्रेडेशन और 31 सड़कों की मरम्मत का वादा किया है। सड़कों के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क निधि से भी पैसा मिला है। इस साल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4,584 किमी और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,200 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में हजारों गांवों में वर्षों से ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। गांव की पुरुष और महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। ये हालत तब है जबकि प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पेयजल आपूर्ति के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनके प्रचार पर ही हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 5,62,736 हैंडपंप अब तक लगे हैं। इनमें से 32,994 खराब हैं। जलस्तर कम होने से 24,285 हैंडपंप बंद हो गए। गर्मी में 22 गांवों में पेयजल बाहर से लाया गया। घरों तक नल से पानी पहुंचाने के लिए 17,177 गांवों में नल-जल योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 16,008 में चालू है, जबकि 1,169 गांवों में बंद पड़ी हैं। जल जीवन मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में 90.27 लाख घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में 29,180 गांव कवर किए गए हैं। इनमें से 4,612 गांवों में ही सभी घरों में कनेक्शन लग पाए हैं। अब तक कुल 50.63 लाख कनेक्शन लगाने का दावा किया जा रहा है। फिर भी आधी आबादी प्यासी है। इस महीने डेढ़ लाख कनेक्शन का लक्ष्य था, 46500 ही लग सके।

वर्ष 2024 तक मप्र के सभी लगभग 122 लाख ग्रामीण परिवारों तक पेयजल उपलब्धता के लक्ष्य के मुकाबले गत दिसंबर तक 45 लाख 10 हजार परिवारों तक पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका था। अभी यह संख्या 46 लाख से अधिक हो गई है। अगले तीन माह में 52 लाख 62 हजार परिवारों तक पेयजल उपलब्ध होगा। नल और बिजली से जुड़े मरम्मत कार्यों के लिए 50 हजार मैकेनिक प्रशिक्षित करने की योजना है। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए मप्र राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से आईटीआई और **अन्य संस्थाएं प्रशिक्षण** प्रारंभ कर चुकी हैं। जल जीवन मिशन में ग्राम और एफएचटीसी (फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन) कार्य-योजना में 25 हजार 399 ग्रामों की समूह नल जल योजनाओं में से 9 हजार 351 कार्य प्रगति पर हैं। कुल 26 हजार 186 ग्रामों की एकल ग्राम नल जल योजना में 8 हजार 176 कार्य प्रगति पर हैं। यह व्यवस्था भी की गई है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए सड़क खुदाई की अनुमति के लिए कांट्रेक्टर जल निगम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगा। यह अनुमति अलाइनमेंट परीक्षण के बाद प्रदान की जाएगी और उसके बाद ही कांट्रेक्टर रोड कटर का उपयोग करेगा। पाइपलाइन डालने के बाद कांट्रेक्टर द्वारा सड़क की आवश्यक मरम्मत करवाई जाएगी। सड़क को पूर्वास्था में लाने के लिए योजना की डीपीआर में प्रावधानित राशि का भुगतान किया जाएगा। भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना में वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्रांश-राज्यांश की राशि के व्यय में मप्र 2,790 करोड़ की राशि का उपयोग कर प्रथम स्थान पर है। हर घर जल उपलब्ध करवाने में मप्र तीसरे स्थान पर है, जहां हाल ही में 4,044 अतिरिक्त ग्राम में यह सुविधा दिलवाई जा चुकी है। पिछले डेढ़ साल में काफी गति से कार्य हुआ है। प्रदेश में मई 2020 से वर्तमान तक 27 लाख 65 हजार परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया था। इस अवधि में प्रदेश का नल से जल आपूर्ति का प्रतिशत 14.5 से बढ़कर 37.10 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

पंचायत चुनाव के इस दौर में कई गांवों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है कि जब तक उनके गांव में बिजली नहीं आएगी, वे वोट नहीं डालेंगे। दरअसल प्रदेश में हजारों गांव ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। प्रदेश में कुल 1.66 करोड़ बिजली कनेक्शन हैं, इनमें से 1.12 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 54 लाख शहरी क्षेत्रों में हैं। ग्रामीणों और किसानों के लिए ऊर्जा विभाग ने इंदिरा गृह ज्योति, अटल किसान ज्योति, उदय और सौभाग्य जैसी कई योजनाएं बनाई। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद 2,081 गांव अभी भी अंधेरे में हैं।

● **जितेंद्र तिवारी**

2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और संघ ने मप्र संगठन और सरकार को 51 फीसदी वोट का टारगेट दिया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए पार्टी कई जतन कर रही है। ऐसे में एनडीए द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करना मप्र भाजपा के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का जश्न मनाया, उससे ऐसा लगता है जैसे सत्ता और संगठन को 51 फीसदी वोट का फॉर्मूला मिल गया है।

आदिवासी भरोसे 51 फीसदी की आस

2018 के चुनाव में 41.5 फीसदी वोट मिलने के बावजूद सत्ता से बाहर हुई भाजपा ने 2023 के चुनाव में 51 फीसदी वोट लाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी सत्ता में आते ही जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने सभी वर्गों को साधने के लिए तमाम तरह के जतन किए हैं। पार्टी को उम्मीद है कि 22 फीसदी आदिवासी वोट अगर भाजपा के पक्ष में आ जाए तो यह लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। ऐसे में आदिवासी समाज की नेत्री द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना मप्र के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है। बता दे, मप्र में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है और देश के सर्वोच्च पद के लिए अपने समाज से उम्मीदवार का घोषित होना एक गर्व की बात है, जिसका जश्न मनाना तो बनता है। दरअसल, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से ही आती हैं। उन्होंने आदिवासियों के हितों और उत्थान के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसके बाद वह आज इस ओहदे पर पहुंच सकी है। वह हमेशा से ही आदिवासियों, बालिकाओं के हितों को लेकर सजग रहीं। आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर वे कई बार सरकार को सीधे निर्देश देते हुए नजर आईं हैं।

मप्र में आदिवासी संख्या 2 करोड़ से अधिक होने के कारण, यह 84 विधानसभा सीटों पर सीधे-सीधे असर डालती हैं। 2018 के चुनाव में प्रदेश की 230 में से 82 सीटें आरक्षित थीं। इसमें से भाजपा 34 सीट ही जीत सकीं थी। 25 सीटों पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। अनुसूचित जाति की 47 सीटों में से 30 पर वर्तमान में कांग्रेस काबिज है और 17 पर भाजपा। अब भाजपा कांग्रेस के खाते वाली 30 सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है। मप्र की चुनावी रणनीती को भाजपा ने अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक इस बार मप्र विधानसभा चुनावों में पार्टी की रणनीति अपने वोट शेयर को कम से कम 51 प्रतिशत तक पहुंचाने का है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भाजपा ने एससी और एसटी समुदायों के बीच अपनी पैठ को और मजबूत करने का फैसला किया है। पार्टी लगातार इस वर्ग से जुड़े मुद्दों को उठा रही है और कांग्रेस के इस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए लगातार काम कर रही है। पार्टी ने इसके लिए एक प्लान तैयार किया है। वैसे भारतीय संविधान में सदियों से पीड़ित, शोषित व पिछड़े हुए लोगों, विशेष रूप से आदिवासी जनजातियों के विकास व उत्थान की समुचित व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने व वर्गहीन, शोषण-रहित व भयमुक्त समाज की स्थापना के उद्देश्य से देश में अनेकानेक योजनाएं चलाई गई हैं। मप्र सरकार ने भी इस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश में शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया है। वर्तमान में मप्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के **आर्थिक रूप** से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान एवं चहुंमुखी विकास के लिए अन्त्योदय योजना चलाई जा रही है।

आगामी विधानसभा चुनाव में 51 फीसदी वोट के टारगेट को पूरा करने के लिए भाजपा का पूरा फोकस 22 फीसदी आदिवासी वोट बैंक पर है। इस वोट बैंक को पाने के लिए प्रदेश में आदिवासियों पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। दरअसल,

भाजपा के लिए ट्रंप कार्ड हैं द्रौपदी मुर्मू

द्रौपदी मुर्मू के नाम से भाजपा ने आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा पासा फेंका है। भाजपा ने न सिर्फ ओडिशा बल्कि देश के सभी आदिवासी प्रदेशों में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए संदेश देना शुरू कर दिया है। ओडिशा, मप्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में आदिवासियों की अच्छी खासी तादाद है। भाजपा ने ओडिशा की आदिवासी महिला नेता और झारखंड की पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू पर दांव लगाकर क्या वास्तव में कोई ऐसा ट्रंप कार्ड चला है, जो भाजपा के लिए आने वाले चुनावों में सफलता की नई इबारत लिखने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने अनुसूचित जनजाति की महिला का नाम आगे करके न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक निशाने भी साध लिए हैं। जिसका असर पार्टी को आने वाले विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनावों में तो दिखना तय माना ही जा रहा है, साथ ही पार्टी की छवि राजनीतिक ही नहीं बल्कि समाज में एक विशेष जाति समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने की भी बन रही है।

आदिवासी वोट पर नजर

प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने आदिवासियों पर अपना फोकस तेज कर दिया है, ताकि 2018 की तरह उसे बहुमत से दूर न रह जाना पड़े। यूं तो भाजपा पूरे देश में जनजाति समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए कई तरह के आयोजन कर रही है, लेकिन मप्र में सबसे अधिक करीब 21.1 फीसदी आबादी के चलते उसकी विशेष अहमियत है, जिनका रुझान ज्यादातर कांग्रेस की ओर रहा है। सो, आदिवासियों पर डोरे डालने की कोशिशें भाजपा के शिखर नेतृत्व की ओर से जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भील जनजाति की प्राचीन पद्धति हलमा की तारीफ भी की थी। गृहमंत्री अमित शाह भी भोपाल में आदिवासियों के विशाल सम्मेलन में शामिल हुए। पिछले वर्ष नवंबर में बिरसा मुंडा की जयंती पर विशाल जनजातीय सम्मेलन हो चुका है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा के जयंती दिवस (15 नवंबर) को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इन विशाल आयोजनों के अलावा राज्य में जिला स्तर पर लगातार आयोजन का सिलसिला चल रहा है।

विधानसभा चुनाव 2018 के परिणाम के बाद भाजपा को आदिवासी वोट की ताकत का अंदाजा हो गया है। यही वजह है कि मिशन 2023 के लिए भाजपा का फोकस आदिवासियों पर है। इसके लिए सितंबर 2021 में अमित शाह जबलपुर में राजा शंकरशाह-कुंवर रघुनाथ शाह के 164वें बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए। उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गौंड रानी कमलापति के नाम पर किया। फिर भोपाल में अमित शाह तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल हुए। 2013 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने इन 47 आदिवासी सीटों में से 37 पर जीत हासिल की थी और लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी थी। हालांकि, 2018 में कांग्रेस ने इस सीटों में से 31 सीटें जीतीं, जिससे भाजपा को यहां सिर्फ 16 सीटें मिली थीं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 41.02 फीसदी वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 40.89 फीसदी वोट मिले थे। सीटों के मामले में भाजपा को 109 और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थीं।

2011 की जनगणना के मुताबिक मप्र में 43 आदिवासी समूह हैं। प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती हैं। इनमें सबसे ज्यादा आबादी भील-भिलाला करीब 60 लाख, तो गोंड जनजाति की आबादी करीब 50 लाख है। कोल 11 लाख, तो कोरकू और सहरिया करीब 6-6 लाख हैं। करीब 10 साल बाद ये आंकड़े काफी हद तक बदल चुके हैं। प्रदेश में वर्ष 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए भाजपा का फोकस आदिवासी वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनाने पर दिखाई पड़ रहा है। दरअसल, मप्र में 22 प्रतिशत आदिवासी हैं, जो विधानसभा की करीब 82 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। प्रदेश में भाजपा की सत्ता बरकरार रखनी है, तो इन्हें साथ लेना जरूरी है। विकास के मुद्दे पर भाजपा कमजोर न पड़े, इसके लिए गरीब कल्याण की योजनाओं को आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस करते हुए गढ़ा जा रहा है। जैसे, राशन आपके द्वार योजना, जिसमें आदिवासी गांवों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए वाहन भी युवाओं को दिए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास, मुफ्त राशन, रोजगार दिवस, घरों तक नल से पानी पहुंचाने सहित कई योजनाओं का रुख आदिवासी क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया गया है।

भाजपा के पास आदिवासी चेहरों की कमी की चुनौती बनी हुई है। इसके बावजूद भाजपा प्रदेश में अपना वोट शेयर 50 प्रतिशत के पार ले जाने के लिए प्रयासरत है, जो आदिवासी समुदायों को जोड़े बिना संभव नहीं है। प्रदेश में आदिवासी लगभग 21 प्रतिशत हैं। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 42.5 प्रतिशत, वर्ष 2008 में 37.6 प्रतिशत, वर्ष 2013 में 45.7 प्रतिशत एवं वर्ष 2018 में घटकर 41.5 प्रतिशत हो गया। भाजपा का लक्ष्य आदिवासी वोट को भी 10 प्रतिशत बढ़ाने का है। यही वजह है कि भाजपा लगातार केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में बड़े आयोजन कर आदिवासियों को **संदेश देना** चाहती है कि वह उनकी सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। शिक्षा और सस्ते राशन के बाद भी मप्र में सबसे ज्यादा भुखमरी और कुपोषण के शिकार आदिवासी ही हैं। मप्र में आदिवासियों की आबादी करीब 2 करोड़ है। इनमें भी एक तिहाई भील और इससे कुछ कम आबादी गोंड आदिवासियों की है। वैसे राज्य में 43 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां हैं, लेकिन इनमें भी 6 जनजातियां कुल आदिवासी आबादी का 92 फीसदी हैं। जिन बिरसा मुंडा की स्मृति में यह महाआयोजन हो रहा है, उस मुंडा समुदाय की मप्र में जनसंख्या केवल 5 हजार है।

कुल की करीब 22 फीसदी आबादी होने से मप्र में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। दरअसल सारा खेल इन्हीं सीटों पर काबिज होने का है। 2003 के पहले तक मप्र की अधिकांश आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। कुछ अपवाद छोड़ दें तो इसका बड़ा कारण कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी की आदिवासियों तक ज्यादा पहुंच ही नहीं थी। बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे दलों ने गोंड इलाकों में जरूर कुछ जोर मारा दिखाया। यूं भी राज्य में सभी आदिवासी समुदाय भाषा, रहन-सहन, संस्कृति,परंपरा और भौगोलिक हिसाब से बंटे हुए हैं। केवल आदिवासी होना ही उनके बीच समान सूत्र है। आदिवासियों के बढ़ते धर्मांतरण के बीच बीते तीन दशकों से आरएसएस और भाजपा ने आदिवासी इलाकों में अपनी पैठ बनाई है। जिसका नतीजा रहा कि 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 47 आदिवासी सीटों में से 31 सीटें जीतने में कामयाब रही। आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की सक्रियता के मद्देनजर संघ ने आदिवासियों को हिंदुत्व से जोड़ने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 आदिवासी सीटें गंवा दीं और ये ज्यादातर कांग्रेस ने जीत लीं। संदेश गया कि आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की पैठ ज्यादा गहरी है, बजाय भाजपा के।

● **सुनील सिंह**

खूंखार नक्सलियों की घुसपैठ

3 राज्यों का ट्राई जंक्शन है बालाघाट

मप्र में बालाघाट नक्सल आंदोलन का अहम केंद्र है, इसलिए यहां नक्सलियों की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। पहले यहां टांडा और मलाजखंड दलम ही थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इनकी मॉनीटरिंग के लिए दो डिविजनल कमेटी बालाघाट में काम कर रही हैं। यहां नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि यहां के जंगल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और महाराष्ट्र के गोंदिया-गढ़चिरोली के जंगलों से जुड़े हैं। ये ट्राई स्टेट कॉरिडोर नक्सलियों के लिए बेहद मुफीद है। इसी बेल्ट में सबसे ज्यादा आदिवासी गांव भी हैं।

मप्र में नक्सलियों का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सीमाई इलाकों में नक्सलियों का मूवमेंट तेजी से बढ़ा है। खुफिया रिपोर्ट कह रही हैं कि इस वक्त 97 खूंखार और हार्डकोर नक्सली मप्र में सक्रिय हैं ये सभी कमांडर इन चीफ स्तर के हैं। ये सभी मप्र में तेजी से अपना विस्तार कर रहे हैं। पुलिस ने इनसे निपटने के लिए केंद्र से सीआरपीएफ की तीन बटालियन मांगी हैं। हाल ही में बालाघाट पुलिस और हॉक फोर्स ने थाना बहेला के खराड़ी गांव में मुठभेड़ में तीन नक्सलियों को मार गिराया था। मारे गए सभी नक्सली कमांडर इन चीफ रैंक के थे। दो दशकों में ये पहला मौका है जब इतने सीनियर लेवल के नक्सली मारे गए थे। नक्सली टांडा एरिया कमेटी के मेंबर थे।

पता चला है कि मप्र, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ यानि एमएमसी जोन के हॉर्ड कोर नक्सली ही मप्र में सक्रिय होकर अपना नेटवर्क तेजी से फैला रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में नक्सली विरोधी अभियान के आईजी फरीद शापू ने जानकारी दी कि मप्र में इस समय करीब 100 नक्सली सक्रिय हैं। उन्होंने कहा हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। नक्सलियों का खात्म करना है। पिछले तीन साल में सात एनकाउंटर में दस नक्सलियों को मारा गया। सभी नक्सली मप्र में अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे थे। हाल ही में तीन नक्सलियों के मारे जाने के बाद प्रदेश के बालाघाट, डिंडौरी, सिवनी-मालवा समेत नक्सल प्रभावित इलाकों में 97 खूंखार नक्सली सक्रिय हैं। ये सभी नक्सली कमांडर इन चीफ स्तर के हैं। ये टॉप स्तर के नक्सली होते हैं, जो तेजी से अपने नक्सली दलम को फैलाते हैं। शापू ने कहा प्रदेश में खटियामोचा, मालखंड, टांडा और दर्रेकसा दलम सक्रिय हैं। ये दलम प्रदेश में अपना विस्तार करने की फिराक में हैं। प्रदेश में **नक्सली मूवमेंट** बढ़ने के कारण राज्य सरकार ने केंद्र से सीआरपीएफ की तीन बटालियन मांगी हैं। आईजी फरीद शापू ने जानकारी दी कि केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हमारी मीटिंग चल रही है। नक्लसियों को सरेंडर और उनके पुर्नवास के लिए भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा पिछले पांच साल में नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ा है। कान्हा नेशनल पार्क एरिया में विस्थापन के कारण गांव नहीं बचे हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि कोर जोन में गांवों का विस्थापन होने के कारण अब पहले के मुकाबले कम सूचनाएं पुलिस को मिल रही हैं।

कान्हा नेशनल पार्क, दक्षिण बैहर क्षेत्र और मप्र, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों ने अपना तेजी से विस्तार किया है। नक्सलियों के मूवमेंट की सूचनाएं कम मिलने की वजह से कान्हा नेशनल पार्क एरिया को नक्सलियों ने अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। कान्हा नेशनल पार्क के अलावा जिले के रुपझर, बैहर, मलाजखंड, बिरसा, लांजी, किरनापुर थाना इलाके में आने वाले जंगलों में मूवमेंट बढ़ा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में टांडा दलम, मलाजखंड दलम, दर्रेकसा दलम, प्लाटून-2, प्लाटून-3, विस्तार दलम, खटियामोचा दलम की मौजूदगी है। मप्र को नक्सलियों ने अपना सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। यही वजह है कि तीन साल में सिर्फ दस ही नक्सली मारे गए। हाल ही में तीन नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद भी 97 नक्सली सक्रिय हैं। यह बात हम नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसी के अफसर कह रहे हैं। अब मप्र पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इन हार्डकोर नक्सलियों का वो कैसे सफाया करेगी।

पुलिस मुख्यालय के अफसर भी मानते हैं कि बालाघाट और इसके आसपास अब भी 100 से 110 नक्सली एक्टिव हैं। पुलिस ने नक्सलियों का जो रिकॉर्ड तैयार किया है, उसमें कई के फोटो तक पुलिस के पास नहीं हैं। जिनके फोटो हैं भी, वो 10 से 20 साल पुराने हैं। ऐसे में अगर नक्सली पुलिस के सामने भी आ जाएं, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। नक्सली गांव में पैठ बनाने और आदिवासियों का भरोसा जीतने के लिए उनकी बेटियों से शादी भी कर रहे हैं। पावेल उर्फ सरवन पहले परसवाड़ा दलम में था, उसने आदिवासी लड़की सुनीता से शादी की। बाद में सुनीता नक्सल कमांडर बनीं। हाल ही में एनकाउंटर में मारी गई रामे से मंगेश ने शादी की थी। मंगेश की मौत के बाद रामे कमांडर बनीं। सबसे पहले मप्र में सूरज टेकाम ने राशिमेटा गांव में आकर एक आदिवासी लड़की से शादी की थी, बाद में वो नक्सल कमांडर बनीं। एनकाउंटर में मारे गए नागेश ने जानकी से विवाह किया था। जानकी से भी उसका रिश्ता नक्सली बनने के बाद हुआ था। 2016 में पुलिस के हत्थे चढ़ी 10 लाख की ईनामी झीनिया बाई ने पुलिस को बताया था कि दलम में रहते हुए उन्हें शादी की इजाजत होती है लेकिन बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं होती।

मप्र पुलिस रिकॉर्ड में इनमें से ज्यादातर नक्सलियों पर ईनाम घोषित है। ईनाम की ये राशि 3 लाख से 7 लाख तक है। इनमें से 50 नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने भी अलग-अलग 5 से 10 लाख रुपए के ईनाम घोषित किए हुए हैं। तीनों राज्यों में एक नक्सली पर करीब 10 से 15 लाख रुपए तक का ईनाम है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि तीनों राज्यों की पुलिस की ओर से नक्सलियों पर 20 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। ईनाम की ये राशि नक्सलियों के कैडर के हिसाब से बढ़ती रहती है। आईजी एंटी नक्सल सेल, साजिद फरीद शापू कहते हैं कि ये सही है कि 2016 के बाद दलम बढ़े हैं, लेकिन नक्सलियों का दायरा नहीं बढ़ने दिया गया है। कान्हा में सुरक्षा बलों के 2 कैंप बनाकर हमने वहां उनका रास्ता रोक दिया है। 2016 के बाद नक्सलियों ने विस्तार का प्लान बनाया था, उसी प्लान के तहत उनकी एक्टिविटी यहां बढ़ी है। स्थानीय स्तर पर मदद न मिल पाने के कारण बहुत से नक्सली लौट भी रहे हैं।

● **विकास दुबे**

दोराहे पर घाटी

कश्मीरी पंडित और प्रवासी मजदूर

90 के दशक की शुरुआत में कश्मीरी पंडितों के पलायन से पहले उनकी संख्या घाटी की आबादी का लगभग दो फीसदी थी। 90 के दशक के अंत में शोधकर्ता अलेक्जेंडर इवांस, जो बाद में भारत में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त बन गए, के कश्मीर पर प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, '1 लाख 60-70 हजार समुदाय में से लगभग 95 फीसदी ने घाटी को छोड़ दिया, जिसे अक्सर जातीय मामले के रूप में वर्णित किया जाता है। लेकिन कश्मीर घाटी में रहने वाले छोटे अल्पसंख्यक यह निर्धारित करने में अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि कश्मीर किस तरह का समाज बनता है।' आज 3,000 से भी कम कश्मीरी पंडित घाटी में हैं। वे कभी पलायन नहीं करते थे। वे यहीं रुके थे और मुसलमानों के साथ रहते थे। हालांकि हाल के वर्षों में सरकार ने कई हजार कश्मीरी पंडितों को वापस लाया और उन्हें सरकार द्वारा निर्मित भवनों में रखा। इनमें से ज्यादातर विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी हैं। अगर हम केंद्र सरकार के आंकड़ों पर जाएं, तो पिछले 3 वर्षों में अधिक पंडितों ने घाटी में लौटना शुरू कर दिया था।

घाटी में कश्मीरी पंडितों सहित आम नागरिकों की हत्याओं ने देशभर में कोहराम मचा दिया है। कई कश्मीरी पंडित जो प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी करने के लिए कश्मीर लौटे थे, उन्होंने हाल की घटनाओं के बाद घाटी छोड़ दी है, जिससे केंद्र सरकार की उन्हें उनकी मातृभूमि में फिर से बसाने की योजना खटाई में पड़ गई है। हालांकि केवल कश्मीरी पंडितों पर ही हमला नहीं किया गया है। आतंकवादियों ने कश्मीरी मुस्लिम नागरिकों, जम्मू और कश्मीर पुलिसकर्मियों, प्रवासी मजदूरों और जम्मू और भारत के अन्य हिस्सों के हिंदुओं को भी अपनी हिंसा का शिकार बनाया है। वहीं सुरक्षा बल अब तक हत्यायों को रोकने में नाकाम रहे हैं। समझा भी जा सकता है कि उनके लिए घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के एक-एक सदस्य को सुरक्षित रखना आसान नहीं होगा।

जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए चीजों को और कठिन बनाने वाली बात यह है कि एक विशेष पैकेज के तहत 4,000 पंडित कर्मचारियों की भर्ती की गई है, लेकिन हाल की घटनाओं के बाद ये सभी नए सिरे से पलायन के कगार पर हैं। इसी तरह जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों के करीब 8,000 कर्मचारी एक अंतर-जिला स्थानांतरण नीति के तहत कश्मीर में काम कर रहे हैं और उनमें से अधिकांश गैर-मुस्लिम हैं। भले सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है, लेकिन उन्हें इस पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं मिल रहा है। पंडित कर्मचारी अब चाहते हैं कि सरकार उस बांड को रद्द कर दे, जो उन्हें अपने रोजगार के दौरान घाटी में स्थायी रूप से रहने के लिए बाध्य करता है। वे चाहते हैं कि पद (पोस्ट) को हस्तांतरणीय बनाया जाए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक हिंदू कश्मीरी पंडित कॉलोनी के अध्यक्ष अवतार कृष्ण भट्ट ने बताया कि सुरक्षा की भावना के अभाव में पंडितों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा- 'कॉलोनी में रहने वाले 300 परिवारों में से लगभग आधे ने हाल ही में हुई हत्या की होड़ के बाद घाटी छोड़ दी थी।' कश्मीरी पंडितों ने भी जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा और कश्मीर के बाहर पोस्टिंग की मांग को लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन किए हैं।

साल 2008 के आसपास तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने कश्मीरी पंडितों को घाटी में लौटने के एवज में नौकरी और वित्तीय सहायता की पेशकश की थी। पंडितों को प्रति परिवार 7.5 लाख रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता दी गई थी, जिसे बाद में घाटी में बसने वालों के लिए तीन किस्तों में बढ़ाकर 20 से 25 लाख रुपए कर दिया गया था। सरकार ने घाटी के विभिन्न हिस्सों में लौटने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सुरक्षित, अलग-अलग एन्क्लेव बनाए। योजना सफल साबित हुई। जो पंडित कार्यरत थे और उनके परिवारों ने इन परिक्षेत्रों में निवास किया, वे मुसलमानों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपने-अपने धार्मिक/सामाजिक आयोजनों में भी शामिल हुए, लेकिन किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं।

बाहरी लोगों और अल्पसंख्यकों की हत्याएं नई दिल्ली के अनुच्छेद-370 को रद्द करने के बाद शुरू हुईं, जिसने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर एक अर्ध-स्वायत्त दर्जा दिया। 5 अगस्त, 2019 को विशेष संवैधानिक पद वापस लेने के दो महीने के भीतर आतंकवादियों ने सेब व्यापार से जुड़े तीन गैर-स्थानीय लोगों को मार डाला। इसने अस्थायी रूप से घाटी के फल उद्योग को संकट में डाल दिया, जिसका सालाना कारोबार 10,000 करोड़ रुपए है, जिसे घाटी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। हत्याओं ने बाहर से यहां आकर काम कर रहे ट्रक ड्राइवरों और सेब व्यापारियों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया और स्थिति को फिर सामान्य होने में समय लगा। तब ऐसी खबरें आई थीं कि उग्रवादियों ने स्थानीय फल उत्पादकों को बाहरी लोगों को काम पर नहीं रखने के लिए कहा था। हालांकि बाद में हत्याएं कम हो गईं, लेकिन आतंकी जल्द ही बिहार और भारत के अन्य हिस्सों के मजदूरों की हत्याओं के साथ फिर सक्रिय हो गए। स्थिति तब चिंताजनक हो गई, जब 31 दिसंबर, 2020 को आतंकवादियों ने एक हिंदू सुनार की हत्या कर दी। पिछले साल भी उन्होंने प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित केमिस्ट माखन लाल बिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी। कुल मिलाकर कश्मीरी मुसलमान पिछले तीन साल में मारे गए लोगों में सबसे ज्यादा हैं। हालांकि इस तरह की हत्याओं को आमतौर पर मीडिया में अलग ही जगह मिलती है।

अल्पसंख्यकों की हत्याओं में वृद्धि ने केंद्र सरकार को घाटी में कश्मीरी पंडितों और हिंदू कर्मचारियों में भरोसा भरने के लिए कदम उठाने को मजबूर किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 17 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने मौजूदा स्थिति के लिए तैयारियों का जायजा लिया। घाटी और आगामी अमरनाथ यात्रा जो दो साल बाद 30 जून से शुरू होने वाली है, पर भी चर्चा हुई। साल 2020 और 2021 में कोरोना वायरस में हुई तालाबंदी के कारण तीर्थयात्रा रद्द कर दी गई थी। यात्रा में लगभग तीन लाख तीर्थ यात्रियों के भाग लेने की संभावना है, जो 11 अगस्त तक चलेगी। केंद्र सरकार अब यात्रा को सुरक्षित करने के लिए कम से कम 12,000 अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ-साथ हजारों जम्मू-कश्मीर पुलिस जवानों को तैनात करने जा रही है।

● **जय सिंह**

रेत बिगाड़ेगी खेल

सरकार को 250 करोड़ रुपए का लगा फटका

मोटी कमाई की आस में मप्र में लागू की गई नई रेत नीति उलटा घाटे का सौदा बन गई है। अब तक राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हो गया है। यही नहीं, रेत का अवैध खनन भी बढ़ गया है। पहली बार ऐसे हालात बने हैं कि रेत खदानों वाले 41 जिलों में से 19 जिलों में वैध खदानें ठेकेदारों ने छोड़ दी है। यह सभी कोर्ट चले गए हैं। लिहाजा, इन खदानों से अवैध रेत खनन हो रहा है। सरकार इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। जबकि, वर्तमान में अधिकृत रूप से केवल 23 जिलों में रेत का वैध उत्खनन हो पा रहा है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार वर्ष 2019 में नई रेत नीति लाई थी। इसके तहत हुए 41 जिलों में 1200 करोड़ रुपए में रेत के ठेके हुए थे। बाद में स्थिति उलटी पड़ गई। कोरोनाकाल के चलते 40 फीसदी ठेकेदार भाग गए। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि ठेकेदारों को दबाव डालकर भगा दिया गया। अब इनमें से कई जगह भाजपा नेता अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं। हालांकि, खनिज विभाग का दावा है कि अब ऐसे जिलों में नए सिरे से टेंडर करवाए जा रहे हैं।

प्रदेश में अभी मौसम ने करवट लेने की तैयारी की ही है, लेकिन इसका असर रेत के दामों पर पड़ना शुरू हो गया है। हालात यह हो गए है कि प्री-मानसून की बौछारें पड़ते ही रेत महंगी हो गई है। मानसून की आहट की संभावना बनने के दस दिनों में ही एक ट्राली रेत पर करीब 1200 रुपए तक की वृद्धि हो चुकी है और यह दाम एक-दो दिन में 1500 रुपए तक बढ़ सकते हैं। यानी की अब तक रेत के दाम 350 रुपए प्रति 100 घन फीट तक बढ़ चुके हैं। मानसून की बारिश होते ही हफ्ते दस दिन में रेत की खदाने पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। इसके बाद रेत के दाम आसमान छूने लगेंगे। इसकी वजह है सिर्फ भंडार कर रखी गई रेत ही बिक्री के लिए मिल सकेगी। यही नहीं रेत माफिया से लेकर ठेकेदार भी कमाई के हिसाब से बारिश व ठंड का शुरूआती कुछ समय कमाई के हिसाब से मुफीद मानते हैं। यही वजह है कि मंहगी रेत के साथ ही ढुलाई भी महंगी कर दी जाती है।

रेत के दामों में होने वाली वृद्धि का असर भवनों की निर्माण लागत पर भी पड़ना तय है। रेत के दामों में हो रही वृद्धि का इससे ही समझी जा सकती है कि 20 दिन पहले 650 घन फीट रेत का एक ट्रक रेत 28 से 29 हजार रुपए में मिलता था, वह अब 40 हजार रुपए तक में मिलने लगा है। कुछ स्थानों पर एक ट्रक रेत के लिए तो इससे अधिक रुपए देने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से अब फुटकर में तो यही रेत साढ़े पांच हजार रुपए से लेकर छह हजार तक में मिल रही है। खास बात यह है कि जो रेत 100 घनमीटर बताकर दी जाती है वह उससे कम निकलती है, जिसकी वजह से वह और अधिक मंहगी हो जाती है।

गौरतलब है कि प्रदेश में सरकारी अनुमान के मुताबिक हर माह 55 करोड़ 80 लाख फीट (दो करोड़ घन मीटर) रेत की जरूरत रहती है। इसमें अगर भोपाल की बात करें तो शहर में रोज सवा सौ से लेकर डेढ़ सौ ट्रक रेत आती है। इसमें सर्वाधिक रेत नर्मदापुरम (होशंगाबाद) की खदानों के समूहों से आती है पर इन खदानों से करीब छह माह से रेत नहीं निकल रही है। दरअसल, समय से रॉयल्टी राशि न देने के कारण खनिज विभाग ने समूह का ठेका निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ ठेकेदार कोर्ट गया है और तब से खदानों से रेत निकालने पर रोक लगी है। यह बात अलग है कि अधिकृत रूप से रेत नहीं निकल रही है, लेकिन अनाधिकृत रूप से खुलेआम जमकर रेत निकाली जा रही है।

दरअसल मोटी कमाई की आस में मप्र में लागू की गई नई रेत नीति उलटा घाटे का सौदा बन गई है। अब तक राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हो गया है। यही नहीं, रेत का अवैध खनन भी बढ़ गया है। प्रदेश के 47 जिलों में रेत का भंडार है। इनमें से वर्तमान में 17 जिलों से रेत निकाली जा रही है। करीब 9 जिलों में रेत खदानें नीलाम होना है। जिन्हें अब जिला स्तर पर नीलाम किया जाएगा। इसके लिए अगले साल सरकार नई रेत नीति लाएगी। जिसमें रेत उत्खनन का पूरा काम जिलों को सौंपा जा सकता है। मोटी कमाई की आस में मप्र में लागू की गई नई रेत नीति उलटा घाटे का सौदा बन गई है। अब तक राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हो गया है। यही नहीं, रेत का अवैध खनन भी बढ़ गया है। पहली बार ऐसे हालात बने हैं कि रेत खदानों वाले 41 जिलों में से 19 जिलों में वैध खदानें ठेकेदारों ने छोड़ दी है। यह सभी कोर्ट चले गए हैं। लिहाजा, इन खदानों से अवैध रेत खनन हो रहा है। सरकार इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। जबकि, वर्तमान में अधिकृत रूप से केवल 23 जिलों में रेत का वैध उत्खनन हो पा रहा है।

तत्कालीन कांग्रेस सरकार वर्ष 2019 में नई रेत नीति लाई थी। इसके तहत हुए 41 जिलों में 1200 करोड़ रुपए में रेत के ठेके हुए थे। बाद में स्थिति उलटी पड़ गई। कोरोनाकाल के चलते 40 फीसदी ठेकेदार भाग गए। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि ठेकेदारों को दवाब डालकर भगा दिया गया। अब इनमें से कई जगह भाजपा नेता अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं। हालांकि, खनिज विभाग का दावा है कि अब ऐसे जिलों में नए सिरे से टेंडर करवाए जा रहे हैं।

ठेकेदारों ने जब ठेके छोड़े तो राज्य शासन ने रेत नीति में कुछ संशोधन किए थे। इसके बाद फिर से टेंडर भी जारी किए गए, लेकिन ठेकेदारों ने रूचि नहीं दिखाई। वहीं, हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट डीसीआर निरस्त होने से खदानें बंद पड़ी है। अब यहां फिर से टेंडर बुलाना पड़ेंगे। प्रदेश में होशंगाबाद, रायसेन, पन्ना, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, भिंड, छतरपुर, धार, राजगढ़, जबलपुर, दमोह, शिवपुरी, बड़वानी, अलीराजपुर, आगर-मालवा, टीकमगढ़, खरगौन में रेत खदानें नई सिरे से होना बाकी है।

● **राजेश बोरकर**

पर्याप्त बजट... सड़कें अधूरी

केंद्र और राज्य सरकार से मिले बजट के बावजूद कई विभाग परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे रहे हैं। इस कारण हर साल करोड़ों का बजट लैप्स हो जाता है। ऐसे ही विभागों में पीडब्ल्यूडी सबसे आगे है। विभाग के पास पर्याप्त बजट है, लेकिन सड़कें आधी-अधूरी पड़ी हुई हैं।

पंचायत चुनाव के शंखनाद के साथ ही आधी-अधूरी सड़कों का मुद्दा गर्मा गया है। जब नेता ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो उन्हें मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसे में लोकनिर्माण विभाग और मंत्री गोपाल भार्गव केंद्र सरकार से पर्याप्त बजट नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि विभाग के पास पर्याप्त बजट है। निष्क्रियता और सुस्ती के कारण लोनिवि पूरा बजट खर्च नहीं कर पाया है और ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहा है।

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के विभाग ने बजट से अधिक यानी 105 प्रतिशत खर्च करके वाहवाही लूटी थी। खर्च बजट आवंटन से ज्यादा होने की वजह लोक निर्माण विभाग ने जिन विभागों का काम किया, उसे उनसे जो राशि प्राप्त हुई, लेकिन उसे मूल बजट में नहीं दिखाया गया। अब विभाग की हकीकत सामने आने लगी है। यही नहीं विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। गांवों की सड़कों के निर्माण, मेंटेनेंस से लेकर मॉनिटरिंग का सारा काम जीएम और एजीएम के भरोसे रहता है। प्रदेश में जीएम के 75 में से 22 पद खाली पड़े हैं। विभाग ने इनके लिए भर्ती की प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू कर दी थी। इंजीनियरों के इंटरव्यू भी हो चुके हैं पर विवादों के चलते अक्टूबर 2021 में नियुक्तियां रोक दी गई। इसका असर मेंटेनेंस पर पड़ रहा है।

लोकनिर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भले ही आधी-अधूरी सड़कों के लिए केंद्र से पर्याप्त राशि नहीं मिलने का ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी विभाग में पास 522 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। इसके लिए विभाग के पास कोई कार्ययोजना ही नहीं है। विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि सड़कों के विकास के लिए पिछले साल मिले 1,252 करोड़ में 730 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। अनुसूचित जाति क्षेत्रों में 1,113 करोड़ के स्थान पर 737 करोड़ रुपए खर्च हुए। आदिवासी बहुल झाबुआ, अलीराजपुर, धार, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और शहडोल जिलों में निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं। प्रदेश के 20 आदिवासी जिलों में विभिन्न विकास कार्य के लिए हर साल एक हजार करोड़ से ज्यादा की राशि आदिवासी उपयोजना में आवंटित होती है। इन जिलों के पिछले 6 साल के आंकड़े देखें, तो वहां शत-प्रतिशत बजट राशि खर्च नहीं हुई। झाबुआ, अलीराजपुर, धार अनुसूचित जाति क्षेत्रों बड़वानी, खंडवा, खरगोन, केमजरे-टोलों में बुरहानपुर, रतलाम, मंडला, निर्मित होने वाली सिवनी, डिंडोरी, अनूपपुर की सड़कें नहीं बन पा रहीं। छिंदवाड़ा, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, सीधी, श्योपुर, होशंगाबाद, बैतूल जिलों के 89 विकासखंडों में सड़कों के लिए बजट जाएगा। बजट जारी किया जाता है, लेकिन उपयोजना में आवंटित होने वाली राशि का पूरा उपयोग इन जिलों में नहीं हो रहा है।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि गांव को जोड़ने वाली 20 हजार किमी से अधिक सड़कें उधड़ गई हैं। इनके अब चुनाव के बाद ही ठीक होने की संभावना है, क्योंकि पंचायत चुनावों की आचार संहिता लागू हो गई है। ये सड़कें 16 जिलों की हैं। ऐसे में खस्ताहाल सड़कें बारिश में आफत बन सकती हैं। सड़कों के ठीक नहीं होने के पीछे बड़ी वजह बजट और अमले की कमी बताई जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों का कहना है कि इन सड़कों के लिए उपरोक्त 16 जिलों के सांसद और विधायकों ने भी पत्र लिखे हैं। चुनाव से पहले इन सड़कों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिया जा चुके हैं। सीएस की साधिकार समिति की बैठक में भी मेंटेनेंस का मुद्दा उठ चुका है। हाल ही में विभागीय बैठक में शिकायतों के चलते इंदौर जीएम को विभागीय मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने फटकार लगाई है। इसके बाद बजट के लिए फंड जारी किए गए हैं।

● **बृजेश साहू**

20 हजार किमी से अधिक ग्रामीण सड़कें बदहाल

मप्र में एक-एक गांव को सड़कों को जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने करीब 90 हजार किमी सड़कों का जाल बिछा दिया है। इससे गांवों में आने-जाने की व्यवस्था सुगम हो गई है। लेकिन भारी वाहनों की धमाचौकड़ी और मरम्मत नहीं होने के कारण करीब 20 हजार किमी सड़कें खराब हो गई हैं। अब इन सड़कों की मरम्मत पंचायतों में 'सरकार' बनने के बाद की संभव है। ऐसे में इस साल मानसून में ये सड़कें ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। क्योंकि मानसून के दौरान सड़कों का मरम्मत होना संभव नहीं है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें पिछले कुछ साल से खराब होती जा रही है। राजनीतिक उठापटक, कोरोना संक्रमण और बजट के अभाव के कारण सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही थी। अब जाकर स्थिति सामान्य हुई है तो पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग गई है। ऐसे में सड़कों के सुधार का काम अब पंचायतों के गठन के बाद ही होगा। तब तक प्रदेश में मानसून आ चुका होगा। ऐसे में करीब 20 हजार किमी खराब सड़कों की मरम्मत मानसून के बाद होने की ही संभावना है।

अटकी अफ्रीकी चीतों को लाने की कवायद

मप्र के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीता लाने की जारी रुकावटें दूर होने के बाद अब उसमें आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह से अब एक बार फिर इसमें देरी होना तय है। दरअसल इसकी वजह है दो विभागों के बीच आपसी सहमति न बन पाने की वजह से फंड का इंतजाम नहीं हो पाना। इसकी वजह से परियोजना के लिए किए जाने वाले काम में देरी होना तय है। दरअसल अफ्रीका से चीता हवाई मार्ग से ही लाए जा सकते हैं। इसके लिए भी बड़ी राशि की जरूरत है। इसके अलावा उन्हें लाने से पहले कई अन्य तरह के कामों को भी कराया जाना जरूरी है। इसके लिए अब तक केंद्र सरकार से भी कोई फंड नहीं मिल सका है। इसके लिए इंडियन आयल कॉरपोरेशन 50 करोड़ रुपए देने को तैयार है, लेकिन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच अनुबंध अटका हुआ है। इसकी वजह बताई जा रही है अनुबंध के लिए संबंधित मंत्रियों से समय न मिल पाना।

दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला एशियाई चीता करीब 70 साल पहले भारत में विलुप्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन अब फिर से इसका दीदार किया जा सकेगा। साउथ अफ्रीका से इन चीतों की पहली खेप इस साल अगस्त में लाई जा रही है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक, इस दौरान 5-6 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा और उन्हें मप्र के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। ये अभयारण्य भोपाल से लगभग 340 किलोमीटर दूर चंबल क्षेत्र में 750 किलोमीटर इलाके में फैला है। पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन एशियाई चीतों को भारत लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता हो चुका है और सभी कार्यवाही पूरी कर ली गई हैं। अब विदेश मंत्रालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। दक्षिण अफ्रीका से विशेषज्ञों का एक दल 15 जून को भारत आकर चीतों को रखने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगा।

सूत्रों की माने तो इस परियोजना के लिए कॉरपोरेशन जनवरी 2022 में ही राशि देने को तैयार था। वन विभाग के एक अफसर का कहना है कि यह परियोजना केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र ने अब तक कोई राशि नहीं दी है, बल्कि वन विभाग को अपने हिस्से की राशि से काम शुरू करने कह दिया था। राशि मिलने की प्रत्याशा में विभाग द्वारा टाइगर फाउंडेशन सोसायटी मद से 10 करोड़ रुपए खर्च कर कूनो पालपुर में चीता रखने के लिए बाड़े का निर्माण कराया जा चुका है। अब विभाग की नजर केंद्र से मिलने वाली राशि पर लगी हुई है। यह राशि न मिल पाने की वजह से आगे के काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल परियोजना में सबसे बड़ा खर्च अब अफ्रीका से चीता लाने पर होना है।

दरअसल, कतर हवाई अड्डे से दिल्ली तक चीता हवाई जहाज से लाने के बाद उन्हें करीब 500 किमी की दूरी सड़क मार्ग से तय करनी होगी। इसके लिए राशि का इंतजाम किए बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है। ऐसे में अगर इंडियन आयल कॉरपोरेशन से ही राशि मिल जाती है, तो समय पर चीता लाना संभव हो सकेगा। गौरतलब है कि पार्क में इन चीतों के लिए 5 वर्ग किलोमीटर के एनक्लोजर (बाड़ा) में रखने की तैयारी है। अफ्रीकी दल ने कूनो नेशनल पार्क का जायजा लेने के बाद किए गए प्रबंधों की तारीफ की है। इस दल ने चीतों के भोजन की जानकारी ली और खुले मैदान देखने के बाद व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान दल के सदस्यों ने कूनो में चीता के भोजन के लिए मौजूद वन्यजीवों की जानकारी ली, वहीं खुले वनक्षेत्र का जायजा लिया। दल के सदस्यों ने कहा कि चीता प्रोजेक्ट के लिए यह अनुकूल जगह है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए सुरक्षा, शिकार और आवास के लिए अपने क्षेत्रफल की वजह से पूरी तरह से उपयुक्त है। चीते के रहने के लिए 10 से 20 वर्ग किमी एरिया और उनके प्रसार के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए। यह सभी चीजें कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद है।

सरकार की योजना नए सिरे से चीता बसाने की है, जिसके लिए दो देशों से उन्हें लाया जाना है। इसमें दक्षिण अफ्रीका से 12 और नामीबिया से 8 चीता लाने की तैयारी है। कूनों में बनाए गए बाड़े में 10 से 12 चीते एक साथ रखे जा सकते हैं। इसी माह प्रदेश के दौरे पर आए विदेशी विशेषज्ञों ने कूनों के बाद राजस्थान की मुकुंदरा हिल्स को भी इनके लिए उपयुक्त माना है। यह बात अलग है कि राजनीतिक कारणों से मुकुंदरा हिल्स में चीता बसने के लिए सहमति नहीं बन पा रही है। जबकि नौरादेही और गांधी सागर अभयारण्यों में अभी काफी तैयारी की जाना जरूरी है। ऐसे में कूनो पालपुर नेशनल पार्क में ही चीते बसाने की उम्मीद बढ़ गई है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

अगस्त में लाने की तैयारी

मप्र सरकार चाहती है कि इस काम को जल्द ही पूरा कर लिया। यही वजह है कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि अगस्त माह के अंत तक चीते लाकर पार्क में छोड़ दिए जाएं। यह बात अलग है कि सरकार की इस मंशा से विशेषज्ञ सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि वर्षाकाल में चीता लाना और उन्हें नई जगह पर बसाना उचित नहीं होगा। चीता हमारे लिए नया वन्य प्राणी है। उसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। दरअसल देश में 1952 में चीता विलुप्त हो गया था। यह चीते एक छोटी सी छलांग में 80 से 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार में दौड़ सकता है। इसी स्पीड से 460 मीटर तक लगातार दौड़ सकता है। खास बात यह है कि 3 सेकंड में ही 103 की रफ्तार पकड़ लेता है। चीता एक बार में 23 फीट की एक लंबी छलांग लगा सकता है। वह दौड़ते वक्त आधे से अधिक समय हवा में रहता है।

औद्योगिक गलियारा बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे

देश के नक्शे में बुंदेलखंड की तस्वीर काफी धुंधली थी और पिछड़ापन और बदहाली यहां की तकदीर बन चुका था। इसी तस्वीर को साफ करने के लिए भाजपा ने अपने मेनिफेस्टो में बुंदेलखंड को प्राथमिकता में रखा और 2017 के चुनावों के बाद यहां पर एक के बाद एक सौगातों की बारिश करना शुरू कर दी। इसी का नतीजा हुआ कि इस वर्ष हुए विधानसभा के चुनावों में भाजपा पार्टी ने बुंदेलखंड में दोबारा अपना परचम लहराया और यहां के बाशिंदो को हर घर नल, डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे जैसी योजनाओं से नवाजा। उप्र की योगी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखी और मात्र 27 महीने में एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार हो गया। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड वासियों के लिए विकास की धुरी साबित होगा।

296 किमी लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे 14849.09 करोड़ की लागत से बनकर लगभग तैयार है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत भी शामिल है। उप्र एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा एक्सप्रेस-वे को विकसित किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की नींव 2019 के फरवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड के लोगों के लिए यह बड़ी सौगात दी थी और कहा था कि चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा।

सरकार ने बुंदेलखंड वासियों को एक्सप्रेस-वे के साथ ही बुंदेलखंड में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजना की सौगातों को शामिल किया है। इस क्षेत्र के झांसी और चित्रकूट में रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए जमीन सरकार ने तैयार की है। यूपीडा सीईओ का मानना है कि एक्सप्रेस-वे बनने से बुंदेलखंड विकास की मुख्यधारा में होगा। इस क्षेत्र में निवेश करने को उद्यमी आकर्षित होंगे। एक्सप्रेस-वे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। अब तक पिछड़े रहे इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं जन्म लेगी। इसके साथ ही बेरोजगारी की समस्या भी खत्म होगी। कोरोनाकाल में अपने घर वापस लौटे 50 हजार से ज्यादा मजदूरों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में रोजगार मिल चुका है।

केंद्र सरकार आने वाले कुछ दिनों में ही बुंदेलखंड की जनता को एक्सप्रेस-वे की सौगात देने जा रही है। 14848.09 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण कुछ ही दिनों में मोदी सरकार करने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे लगभग 296 किलोमीटर लंबा है जिसकी चार लेन बनकर लगभग तैयार हैं और इसका भविष्य में 6 लेन तक विस्तारीकरण करने की योजना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे बनने के साथ ही चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों से होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे आगरा एक्सप्रेस-वे और यमुना एक्सप्रेस-वे के माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ेगा। मिली जानकारी के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर चार रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया है। इसके साथ ही एक्सप्रेस-वे के कुल 19 फ्लाई ओवर्स का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। यमुना और बेतवा नदी पर पुल का निर्माण कार्य भी रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है। केन नदी पर बन रहा पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक्सप्रेस-वे पर 15 पेट्रोलिंग वाहनों की तैनाती की जाएगी। एक्सप्रेस-वे पर 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड स्टैंडर्ड रूप में बनाई गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे इटावा में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा, वहीं चित्रकूट के भरतकूप से इटावा होकर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर कुदरैल के पास मिलेगा। इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने से बुंदेलखंड अन्य एक्सप्रेस-वे जैसे आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और यमुना एक्सप्रेस-वे के माध्यम से अन्य जिलों से जुड़ जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर 6 पेट्रोल पंप भी होंगे। इसके अलावा एक्सप्रेस-वे केन, बेतवा, बागेन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना और सेंगर नदियों के ऊपर से गुजरेगा।

बुंदेलखंड के विकास को लेकर के पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने केन-बेतवा लिंक परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। माना जा जा रहा है कि इसके कारण बुंदेलखंड की आर्थिक और सामाजिक दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन होगा। सरकार इस परियोजना के माध्यम से पनबिजली भी बनाने जा रही है। साथ ही साथ सोलर ऊर्जा का भी उत्पादन किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड में सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। सरकार का दावा है कि इससे पेयजल की समस्या खत्म होगी, साथ ही साथ ग्राउंडवाटर रिचार्ज भी होगा।

● **सिद्धार्थ पांडे**

बुंदेलखंड में बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर

इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार बुंदेलखंड के विकास को लेकर के यहां एक डिफेंस कॉरिडोर भी बनाने जा रही है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए की घोषणा भी कर दी है। उप्र में बनने वाला यह रक्षा गलियारा झांसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, कानपुर एवं लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। इसका करीब 60 फीसदी हिस्सा झांसी में है। माना यह जा रहा है कि इस कॉरिडोर के बनने से 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस रक्षा गलियारे में अपनी इकाई लगाने के लिए देशी समेत विदेशी कंपनियों ने भी दिलचस्पी भी दिखाई है। इससे देश को रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकेगा। मेक इन इंडिया के तहत इस गलियारे में बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर तोप एवं उसके गोले, मिसाइल, बंदूकें निर्मित होंगी। यहां छोटी यूनिट भी लगेगी जहां पैराशूट, दस्ताने आदि बनाए जाएंगे। भाजपा के युवा नेता मनोज यादव का मानना है कि बुंदेलखंड के विकास को लेकर आजादी के बाद से कोई प्रयास नहीं किए गए जिसके कारण यह विकास की मुख्य धारा में पिछड़ गया। मनोज यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। जिसका परिणाम है कि बुंदेलखंड आज किसी भी मायने में विकास की दौड़ में पीछे नहीं रह गया है और आने वाले दिनों में यहां विकास की बयार बहेगी।

ऑपरेशन लोटस या बगावत के शिकार उद्धव...?

विपक्ष का एक और किला ध्वस्त, महाराष्ट्र में बनी नई सरकार

विधायक अब राजनीतिक उद्यमी बन गए हैं, महाराष्ट्र इसकी ताजा मिसाल

करीब एक पखवाड़े के बगावती खेल के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर गई। वहीं एकनाथ शिंदे ने भाजपा के सहयोग से नई सरकार बना ली है। ऐसे में देशभर में यह सवाल उठने लगा है कि विपक्ष का एक और किला ध्वस्त होने के पीछे भाजपा का ऑपरेशन लोटस या शिवसैनिकों की बगावत कारण बना है। वजह कोई भी हो, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। देश में पिछले कुछ सालों से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने का जो खेल चल रहा है, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

● राजेंद्र आगाल

महाराष्ट्र में 2004 में चुनाव के दौरान तत्कालीन शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे से पूछा गया था कि क्या वे गठबंधन की जीत के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने नकारते हुए कहा था कि सीएम कोई भी बने रिमोट मेरे हाथ में ही रहेगा। महाराष्ट्र में ऐसा होता भी रहा और देखा भी गया, लेकिन 2019 में बहुमत नहीं होने के बाद भी उद्धव ठाकरे जिस तरह बाला साहेब ठाकरे की परिपार्टी को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री बने, उसी समय लग गया था कि शिवसेना और मातोश्री की अहमियत कम होगी और अंतत: ऐसा ही हुआ। अब मातोश्री के हाथों से शिवसेना के साथ ही सरकार का रिमोट भी दूर चला गया है। उधर, सियासी ड्रामे के 11वें दिन एकनाथ शिंदे ने राज्य के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही गठबंधन के जरिए ही सही राज्य में ढाई साल बाद भाजपा ने फिर सत्ता में वापसी कर ली है।

महाराष्ट्र में भाजपा ने सत्ता में वापसी का जो तरीका अपनाया गया, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दरअसल, भाजपा ने 8 साल में 5 राज्यों में सेंधमारी कर सत्ता हासिल की है। जिसे ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया है। हालांकि भाजपा हमेशा इनकार करती है कि उसने किसी भी पार्टी में सेंधमारी नहीं की है। लेकिन पार्टी में बगावत के बाद अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में ही बनी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में जो नई सरकार गठित की गई है, वह ऑपरेशन लोटस है या फिर बगावत। वजह कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि भाजपा ने 23वें राज्य में अपनी सत्ता कायम कर ली है। गौरतलब है कि 2014 में भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया था। इस संकल्प को पूरा करने के लिए पार्टी साम, दाम, दंड, भेद सबका सहारा लेती रही है। आज इसी का परिणाम है कि देश के करीब 59 फीसदी आबादी वाले 18 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। महाराष्ट्र में देश की 9 फीसदी से ज्यादा आबादी रहती है। वहीं, कांग्रेस की सरकार अब 4 राज्यों तक ही सिमटकर रह गई है। इन 4 राज्यों में देश की करीब 16 फीसदी आबादी रहती है। भाजपा जिस तरह की राजनीति इस समय कर रही है उसका एकमात्र लक्ष्य है कि वह देश में पूरी तरह विपक्ष को कमजोर कर दे।

जनाधार बढ़ाने नई नीति

भाजपा के ऑपरेशन लोटस को भले ही लोकतंत्र के लिए खतरा माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्ष के असंतुष्ट नेताओं के लिए यह संजीवनी बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि भाजपा ने पिछले कुछ सालों से जनाधार बढ़ाने के लिए जो नई नीति बनाई है, उसके तहत विपक्ष से आए नेताओं को मुख्यमंत्री सहित कई अहम पदों पर बैठाया जा रहा है। वर्तमान में देश के जिन 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहीं 5 ऐसे राज्य हैं, जहां भाजपा किसी अन्य दल के साथ सरकार में शामिल है। ऐसे में कुल मिलाकर 23 राज्यों की सत्ता में भाजपा शामिल है। अपनी नई रणनीति के तहत भाजपा ने दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को मुख्यमंत्री भी बनाया है। इनमें त्रिपुरा में कांग्रेस से आए डॉ. माणिक साहा, नगालैंड में **नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोगेसिव** पार्टी से आए नेफियू रियो, असम में कांग्रेस से आए हिमंत बिस्वा सरमा, मणिपुर में कांग्रेस से आए एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं महाराष्ट्र में सियासी कयासों को धता बताते हुए भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को अपने विधायकों का समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हर तरफ की बाजी पलट गई।

बगावत को प्रोत्साहन

महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उससे बगावत को प्रोत्साहन मिलेगा। बिना सबूत के कोई आरोप लगाना मुश्किल है कि ये बगावतें मुख्यतः पैसे के लिए होती हैं। लेकिन अगर आप यह नहीं भी मानते कि इनमें से अधिकतर बगावतों का विचारधारा या सरकार के कामकाज से कोई संबंध नहीं होता बल्कि विधायकों की खरीद-फरोख्त से ही होता है, तब भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके कारण सैकड़ों करोड़ का नुकसान होता है। विधायकों को चार्टर्ड विमान में देशभर में घुमाने का खर्च कौन देता है? पांच सितारा होटलों और रिजॉर्टों में विधायकों को पहरे के अंदर रखने पर कितना खर्च होता है? किन्हीं कारणों से, इस तरह के सवाल शायद ही उठाए जाते हैं। अगर उठाए भी जाते हैं तो उनका कभी जवाब नहीं दिया जाता। भाजपा की अजेयता के किस्से को मजबूत करने (आपने भाजपा सरकार के लिए वोट न भी दिया हो तो भी उसकी सरकार बन ही जाती है) के अलावा ये तख्तापलट और बगावतें मतदाताओं को यही दर्शाती हैं कि चुनाव नतीजे का मोल कितना कम है। जब आप किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तब आप वास्तव में ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनते, जो आपके हितों का प्रतिनिधित्व करे या जो अपनी उस विचारधारा को लागू करे जिसमें आस्था रखने का उसने वादा किया है। चुनाव में जीत आज किसी स्टार्ट-अप को दिए जाने वाले कर्ज के जैसा राजनीतिक कर्ज बन गया है। कुछ विधायक जनादेश लेते हैं और फिर उसे पैसे से भुना लेते हैं, और अपनी तकदीर संवारने के लिए राजनीतिक उद्यमी बन जाते हैं। मतदाता उनकी समृद्धि को संभव बनाने वाले साधन भर हैं। इसके कारण मतदाताओं के मन में जो संशय पनपता है उसे कमतर नहीं आंकना चाहिए। कभी भी कोई राजनीतिक दल 45 फीसदी से ज्यादा वोट से चुनाव नहीं जीतता (बल्कि अक्सर इससे कम वोट प्रतिशत से चुनाव जीतता है)। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय लोकतंत्र जब ठीक-ठाक काम कर रहा होता है, तब भी सरकारों को बहुमत का समर्थन नहीं हासिल होता है, चाहे हम 'जोरदार जीत' का जितना भी शोर क्यों न मचाएं। ज्यादातर संसदीय लोकतंत्रों में यह बड़ी समस्या नहीं बनती क्योंकि चुनाव जीत कर बनी सरकारें सबको साथ लेकर चलने की ज्यादा कोशिश करती हैं।

भाजपा के भी कुछ लोगों को इसकी भनक नहीं थी। हर कोई यह मानकर चल रहा था कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सियासी दांव-पेंच इस करवट आकर बैठेगा, यह अप्रत्याशित था। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है।

दोष उद्धव का भी

मप्र और कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में जिस तरह सरकार को गिराया गया, इससे लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठने लगा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ उन्हीं के शिवसैनिकों की बगावत और उनको भाजपा का सहयोग मिलना ऑपरेशन लोटस माना जा रहा है। भाजपा भले ही कुछ न कहे, लेकिन विपक्ष खुले तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि मप्र, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह सरकार गिराई गई, वह ऑपरेशन लोटस का ही परिणाम है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर छाए संकट के लिए एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा को जितना जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा दोष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का है। खतरा तो उन्हें अपने सहयोगियों कांग्रेस और एनसीपी से होना चाहिए था। पर गठबंधन के उनके ये दोनों सहयोगी तो विपरीत विचारधारा के बावजूद पुख्ता तौर पर अभी तक उनके साथ खड़े हैं। शिंदे ने हिंदुत्व की विचारधारा की तो महज आड़ ली है। हकीकत तो यह है कि वे शिवसेना और सरकार में खुद को हाशिए पर पा रहे थे। मुंबई में किससे छिपा है कि सरकार उद्धव नहीं बल्कि उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे चला रहे थे। बाकी रिमोट शरद पवार के हाथ में था।

बहरहाल भाजपा आज जो खेल महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ खेल रही है, 1995 में वही खेल कांग्रेस ने भाजपा के साथ खेला था। तब भाजपा की देश में इकलौती गुजरात में ही सरकार थी। मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल सितंबर 1995 में अमेरिकी दौरे पर थे। उनकी

पार्टी पर दावेदारी का दंगल

अब महाराष्ट्र में शिवसेना पर दावेदारी का दंगल शुरू हो चुका है। बागी विधायकों का दावा है कि अब शिवसेना पर उनका अधिकार है, जबकि उद्धव ठाकरे ताल ठोंक रहे हैं कि चूंकि उनके पिता ने यह पार्टी बनाई थी, इसलिए इस विरासत पर उनका अधिकार है। फिर सारे जिलों के संगठन प्रमुख उनके साथ हैं, इसलिए बागी विधायकों का इस पार्टी पर अधिकार जताना बेमानी है। दरअसल, महाराष्ट्र में शिवसेना का एक बड़ा जनाधार है और जिसके पास उसका चुनाव निशान रहेगा, पार्टी पर जिसका कब्जा रहेगा, भविष्य में उसी के लिए वहां की राजनीति में जगह बनाने की संभावना भी रहेगी। इसलिए बागी विधायक जानते हैं कि अगर उन्होंने अलग पार्टी बनाई, तो उन्हें उस तरह समर्थन हासिल नहीं हो सकेगा, जैसा शिवसेना में रहते मिला करता था। इसका उदाहरण उनके सामने है कि शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, पर वैसा समर्थन नहीं मिल सका, जैसा शिवसेना को प्राप्त है। इसलिए वे उसे हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर उद्धव ठाकरे अपने पिता की बनाई पार्टी को इस तरह किसी को हड़पने नहीं दे सकते। उसे बचाने के लिए वे अपनी राजनीतिक गोटियां ठीक कर रहे हैं। बागी विधायकों ने पार्टी पर अधिकार पाने के लिए निर्वाचन आयोग में अर्जी भी दे दी है। कानूनी नुक्ते से निर्वाचन आयोग पार्टी पर उन्हें कब्जा दिला सकता है। नियम के मुताबिक जिस पक्ष के पास दो तिहाई से अधिक सदस्य हैं, उसे पार्टी का असली हकदार मान लिया जाता है। बागी विधायकों का दावा है कि उनके पास फिलहाल 38 विधायक हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे का दावा है कि सारे जिलों के प्रमुख और कार्यकर्ता उनके साथ हैं। मगर कानून पार्टी की स्थिति का निर्णय कार्यकर्ताओं के आधार पर नहीं, प्रतिनिधियों के आधार पर करता है।

अनुपस्थिति में भाजपा के ही शंकर सिंह वाघेला पार्टी के 47 विधायकों को लेकर पड़ोसी मप्र के खजुराहो पहुंच गए थे। सरकार संकट में दिखी तो भैरो सिंह शेखावत और अटल बिहारी वाजपेयी ने वाघेला को मनाया। पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। सुरेश मेहता मुख्यमंत्री बने और तबके गुजरात प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात छोड़ना पड़ा था।

उद्धव प्रसंग ने फिर साबित किया है कि पिता से विरासत में पार्टी और हैसियत पाना अलग बात है पर उसे बनाए रखने का कौशल हर वारिस में नहीं होता। जैसे चौधरी चरण सिंह का जनाधार उनके पुत्र अजित सिंह के बजाय मुलायम सिंह यादव ने छीन लिया था। जैसे एमजीआर का जनाधार उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन नहीं संभाल पाई थी और जयललिता ने खुद को उनका उत्तराधिकारी साबित किया था। आंध्र में एनटीआर की पत्नी लक्ष्मी पार्वती के बजाय उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू सियासी वारिस बनकर उभरे थे। कमोबेश यह अखिलेश यादव के लिए भी नसीहत है। जो पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालने में अभी तक निपुण नहीं हुए हैं।

पिक्चर अभी बाकी है

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने सोचा था कि बाल ठाकरे की वैचारिक तथा राजनीतिक विरासत पर दावा करने के लिए शिवसेना कुल 55 में से 36 के आसपास विधायकों को तोड़ लेना काफी होगा। उन्होंने शायद सोचा था कि बगावत करने वाले दो तिहाई विधायकों को अलग गुट के रूप में मान्यता मिल जाएगी और वह भाजपा को सरकार बनाने में मदद कर सकेगा। शिंदे को संविधान की 10वीं अनुसूची को ध्यान से पढ़ना चाहिए था। दल से अलग हुए दो तिहाई विधायकों को अलग गुट की मान्यता नहीं मिल जाती। ये विधायक अगर दूसरे दल में शामिल नहीं होते तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन बाल ठाकरे की वैचारिक तथा राजनीतिक विरासत के स्वयंभू झंडाबरदार भाजपा को इस विरासत पर कैसे कब्जा करने दे सकते हैं? आखिर, वे अपनी बगावत को हिंदुत्व की विचारधारा पर दावा करने का सच्चा आंदोलन बताते हैं, जिसे उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर कथित रूप से कमजोर कर दिया है। इसलिए, ये बागी अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो वे अपना नैतिक दावा, शिवसेना वाली पहचान और शिवसैनिकों का समर्थन गंवा देंगे। सेना से अलग होते ही और भाजपा में शामिल होते ही मोलभाव करने की उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। इसलिए विलय वाले विकल्प को फिलहाल तो टालना ही होगा।

महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में एक इस विकल्प की भी चर्चा हो रही है कि शिंदे समूह निर्दलीय विधायक ओमप्रकाश बाबाराव काडू की प्रहार जनशक्ति पक्ष (पीजेपी) में शामिल हो जाए। काडू एक मंत्री हैं, जो शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। इस विकल्प के साथ दिक्कत यह है कि काडू एक मनमौजी नेता हैं, जो हेमा मालिनी को 'बंपर पियक्कड़' कह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री रावसाहब दानवे को उनके घर में घुसकर 'पिटाई करने' की धमकी दे चुके हैं। जाहिर है, शिंदे और भाजपा काडू के साथ सहयोग करने पर दो बार सोचेंगे, क्योंकि काडू ही पीजेपी चीफ के रूप में केंद्र में रहेंगे। शिंदे के सामने **तीसरा विकल्प** यह है कि वे शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दें। लेकिन चुनाव अगर हमदर्द भी हो तो भी शिंदे को सेना के विधायकों, सांसदों, पार्षदों और पार्टी पदाधिकारियों के बहुमत का समर्थन साबित करना होगा। लेकिन यह बड़ा सवाल है। शिंदे और उनके समर्थक फिलहाल महाराष्ट्र लौटने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें शिवसैनिकों के कोप का सामना करना पड़ सकता है और खुद उनके खेमे के विधायक दलबदल करके उद्धव के साथ जा सकते हैं। यह दुविधा ही भाजपा नेताओं की चुप्पी का कारण लगती है।

पीढ़ी परिवर्तन के संकेत

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन अंतिम सांसें गिन रहा है। ठाकरे के सामने अब चुनौती पार्टी बचाने की है। इस राज्य का राजनीतिक घटनाक्रम सभी परिवारवादी पार्टियों के लिए सबक है। बेटे को आगे बढ़ाने के फेर में पार्टी जाती हुई दिख रही है। शिवसेना में बगावत महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव लेकर आई है। यह बदलाव पीढ़ी परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। ठाकरे के साथ पवारों और चव्हाणों के दिन जा रहे हैं या कहिए कि गए ही समझिए। कहावत है सौ सुनार की, एक लोहार की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, गांधी परिवार मिलकर पिछले ढाई साल से

ऑपरेशन लोटस

'ऑपरेशन लोटस' भाजपा की उस स्ट्रैटजी के लिए गढ़ा गया शब्द है, जिसमें सीटें पूरी न होने के बावजूद पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती है। ऑपरेशन लोटस के तहत भाजपा उन राज्यों को अपना टारगेट बनाती है जहां भाजपा सत्ता में नहीं होती या कम सीटें होनी की वजह से वो सत्ता में आ नहीं पाती। महाराष्ट्र से पहले भी भाजपा कई राज्यों में अपना ऑपरेशन लोटस चला चुकी है। जिसमें से कई राज्यों में भाजपा को सफलता मिली तो कई राज्यों में उसे असफलता का स्वाद चखना पड़ा। इस ऑपरेशन के तहत भाजपा अलग-अलग तरीके से सत्ता को गिराकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है। 2016 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन पार्टी के अंदर विवाद हो गया। इसके बाद कांग्रेस के 42 विधायकों ने बागी रूख अख्तियार कर लिया। इन सभी ने पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल बना ली और भाजपा के साथ गठबंधन सरकार बनाई। बाद में पीपीए का भाजपा में विलय हो गया था। 2017 में गोवा में भी चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन भाजपा ने खेल बिगाड़ दिया। यहां भी भाजपा ने ऑपरेशन लोटस चलाया और कांग्रेस के 10 विधायकों ने एक साथ राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सभी भाजपा में शामिल हो गए। यहां भी भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई। वहीं 2018 में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लेकिन बहुमत के आंकड़ों से दूर थी। उस समय जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। फिर ऑपरेशन लोटस चला। एक साल बाद इन दोनों पार्टियों के कई विधायकों ने एकसाथ इस्तीफा दे दिया। इसके चलते कुमारस्वामी की सरकार गिर गई। भाजपा ने कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई। तब विपक्ष ने भाजपा पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया था। 2020 में ऑपरेशन लोटस मप्र में भी सफल हुआ था। यहां 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तब मुख्यमंत्री का सपना देख रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी सामने आई। कुछ समय बाद उन्होंने बगावत कर दी। सिंधिया के पास 22 विधायकों का साथ था। सभी ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। सिंधिया गुट के 22 विधायक भाजपा के साथ चले गए। भाजपा के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। वहीं, सिंधिया को राज्यसभा का सांसद बनाकर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री बना दिया। वहीं अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य में भाजपा ने अपनी सत्ता कायम कर ली है।

भाजपा पर हमलावर थे। उनके निशाने पर राज्य का भाजपा नेतृत्व कम और राष्ट्रीय नेतृत्व ज्यादा था। उन्हें गालियां दी जा रही थीं, उनके मरने की इच्छा जाहिर की जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप सुन रहे थे। ये सारे धतकरम ही महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के गले का पत्थर बन गए। मोदी ने सीधे कुछ नहीं किया। घर में ही भारी झगड़ा हो गया।

आजकल भारतीय राजनीति के बारे में बात करते हुए महाभारत के उस प्रसंग की याद आती है, जिसका निहितार्थ है कि सत्ता के बंटवारे में बेईमानी और हठधर्मी कभी काम नहीं आती। दूसरी बात यह कि जो पांच गांव नहीं देते, उन्हें पूरा राजपाट देना पड़ता है। महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री पद पर भाजपा का दावा स्वाभाविक था, लेकिन शिवसेना अचानक यह दावा करने लगी कि भाजपा ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। अब शिवसेना के विधायक ही कह रहे हैं कि यह झूठ था। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, वह भले ही शिवसेना का अंदरूनी मामला हो, लेकिन इस घटनाक्रम ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार की बहुत बड़े रणनीतिकार की छवि को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इस सरकार के मुखिया भले ही उद्धव ठाकरे थे, पर इसके जनक तो पवार ही थे। शिवसेना की बगावत में वह कुछ नहीं कर सकते थे, पर जिस सरकार को उन्होंने बनाया और जिसे वह बाहर से चला भी रहे थे, उसमें इतने बड़े संकट की उन्हें आहट भी नहीं लगी। एक जमाने में 6 विधायक लेकर अपना राज्यसभा उम्मीदवार जिता लेने वाले शरद पवार राज्य में राज्यसभा और विधानपरिषद चुनाव में युवा नेता देवेंद्र फडणवीस से मात खा गए।

परिवारवादियों के लिए सबक

महाराष्ट्र का घटनाचक्र उन सभी परिवारवादी पार्टियों के लिए यह सबक है कि जहां संगठन और सरकार के फैसले खाने की मेज या बेडरूम में होते हैं, वहां पतन और बिखराव ही होता है। आम कार्यकर्ता संगठन और विचारधारा से जुड़ा होता है। वह किसी नेता का बंधुआ मजदूर नहीं होता। जिस नेता को यह गलतफहमी हो जाए, उसका पराभव तय मानिए। महाराष्ट्र के संकट में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, जबकि वह अघाड़ी सरकार में शामिल है। कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, लेकिन राष्ट्रपति के उम्मीदवार के चयन में उसकी कोई भूमिका नहीं। पूरी विपक्षी राजनीति में कहीं बिखराव, कहीं ठहराव, कहीं टकराव और कहीं पराजित भाव नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष देश की राजनीति में फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने की इच्छाशक्ति ही खो चुका है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि वह फिनिशिंग लाइन से कितना पहले गिरेगा।

महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, वह केवल उद्धव ठाकरे के राजनीतिक पतन की कहानी नहीं बता रहा। यह राज्य के सबसे कद्दावर मराठा नेता शरद पवार के राजनीतिक नेपथ्य में जाने की मुनादी भी कर रहा है। यह देवेंद्र फडणवीस के राज्य के सबसे लोकप्रिय और कद्दावर नेता के रूप में उभरने की भी कहानी है। वह अब महाराष्ट्र में भाजपा के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता बन गए हैं। यह मानकर चला जाना चाहिए कि एकनाथ शिंदे के रूप में भाजपा को एक नए लोकप्रिय मराठा नेता का साथ मिलने वाला है। वह भाजपा में आएं या शिवसेना पर कब्जा करके साथ रहें, कम से कम हिंदुत्व की विचारधारा के मुद्दे पर शिंदे के मन में कोई दुविधा नहीं है। इन सब बातों और घटनाक्रम का निष्कर्ष क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तात्कालिक राजनीतिक फायदे के नजरिये से कोई कदम नहीं उठाते। उनकी रणनीति हमेशा दीर्घकालिक होती है। उनकी राजनीति का मकसद यह नहीं है कि जब तक मैं रहूं, सब ठीक रहे, उसके बाद जो हो, वह आगे आने वाला जाने। वह भविष्य की भाजपा बना रहे हैं और इसका प्रबंध कर रहे हैं कि उनके बाद जो लोग आएं, उन्हें उनके जैसा परिश्रम न करना पड़े। नेतृत्व परिवर्तन में केवल पीढ़ी परिवर्तन पर ही ध्यान नहीं रहता। नेतृत्व की गुणवत्ता की जांच-परख भी की जाती है। महाराष्ट्र का मामला हो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार का प्रकरण हो,

मंत्रिमंडल में चयन का मामला हो, सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता। जो नए लोग लाए जाते हैं, उनमें भी इसका ध्यान रखने की कोशिश होती है। कुल मिलाकर भाजपा और विपक्ष में होड़ लगी है क्रमशः बेहतर होने और पतन की ओर जाने की।

बहुत कठिन है डगर आगे की

अलग-अलग दौर में शिवसेना छोड़कर राजनीतिक जमीन की तलाश में निकले नेताओं में सिर्फ दो ही नाम हैं जो ठीक-ठाक पोजीशन में हैं और उसकी एक वजह उनका एक खूंटे को पकड़कर बने रहना भी लगता है। राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी बनाई और नारायण राणे पाला बदलते रहे, लेकिन छगन भुजबल एक बार जो शरद पवार की शरण में गए तो अब तक बने हुए हैं। ठीक ऐसा ही हाल सुरेश प्रभु का है। मंत्री पद न सही, लेकिन केंद्र में सत्ताधारी भाजपा के साथ बने हुए तो हैं ही। कभी शिवसेना के ओबीसी फेस रहे छगन भुजबल ने 1991 में 18 विधायकों के साथ शिवसेना छोड़ी थी, लेकिन तब 12 वापस चले गए। फिर भी छगन भुजबल ने अपने वादे के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और अपना योगदान देते रहे। बाद में करीब 8 साल बाद जब शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई तो छगन भुजबल भी साथ हो लिए। हाल ही में गिरी महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में वो मंत्री थे।

हाल ही में राज ठाकरे को खासा एक्टिव देखा गया था। मस्जिदों से लाउडस्पीकर के खिलाफ मुहिम शुरू की थी और अल्टीमेटम दे दिया था। अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने के बाद भी कहे थे कि महाराष्ट्र की मस्जिदों से सारे लाउडस्पीकर उतारे जाने तक उनकी मुहिम जारी रहेगी। उसी दौरान मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर पुलिस ने अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और फिर राज ठाकरे के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई की आशंका जताई जाने लगी थी। फिर अचानक एक दिन रैली में

राज ठाकरे ने अपनी अयोध्या यात्रा तक रद्द करने की घोषणा कर डाली। कह रहे थे वो किसी के जाल में नहीं फंसना चाहते। बताया कि उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं।

राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा की घोषणा पर ही भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने वहां घुसने न देने का ऐलान कर दिया था। भाजपा सांसद का कहना रहा कि जब तक राज ठाकरे अपनी पुरानी हरकतों के लिए उत्तर भारतीय लोगों से माफी नहीं मांग लेते, उनको अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। हालांकि, उद्धव ठाकरे की अयोध्या यात्रा तय हुई तो वैसा कुछ नहीं हुआ। 15 जून को उद्धव ठाकरे तो नहीं लेकिन आदित्य ठाकरे जरूर अयोध्या गए थे। शिवसेना छोड़ने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाकर राज ठाकरे में तमाम कोशिशें की, लेकिन अब तक महाराष्ट्र में अपनी कोई अलग राजनीतिक जमीन खड़ा नहीं कर सके हैं। ये ठीक है कि राज ठाकरे के समर्थक काफी हैं और उनकी एक कॉल पर सड़कों पर उत्पात मचा सकते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में तो अब तक वो फेल ही रहे हैं। फिलहाल मनसे के पास एक विधायक है।

19 राज्यों में भाजपा सत्ता में

अभी 19 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हैं। दोनों राज्यों में अभी भाजपा सत्ता में हैं। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मप्र, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। अभी कर्नाटक, त्रिपुरा, मप्र में भाजपा की सरकार है। इसके अलावा मेघालय, नगालैंड में भाजपा गठबंधन के साथ सरकार में है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस जबकि तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। 2024 में लोकसभा और 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। इनमें सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड शामिल हैं। अभी हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भाजपा की सरकार है। ओडिशा में बीजद, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी सरकार है। इन राज्यों में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती यह है कि जहां वह सरकार में है, उसे कायम रखना और जहां वह विपक्ष में है, वहां जीत हासिल करना।

शिवसेना में बगावत...यह तो होना ही था

शिवसेना में बगावत को लेकर हैरानी नहीं। जब शिवसेना ने विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भाजपा से नाता तोड़कर अपने धुर विरोधी दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि यह बेमेल सरकार अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं। वास्तव में तब यह भी साफ हो गया था कि इस विचित्र प्रयोग की सबसे बड़ी कीमत शिवसेना को ही चुकानी पड़ेगी। वैसे तो सत्ता के लोभ में पहले भी परस्पर विरोधी दल एक साथ आते रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने राकांपा और कांग्रेस के साथ जाकर अपने उस आधार को अपने ही हाथों खिसकाने का काम किया, जिस पर उसकी समस्त राजनीति केंद्रित थी। हिंदुत्व को अपनी राजनीति का आधार बताने वाली शिवसेना ने राकांपा और कांग्रेस के पाले में जाकर अपनी विचारधारा से मुंह ही मोड़ा। इसके चलते वह हर गुजरते दिन के साथ अपनी साख गंवाती जा रही थी। इसे शिवसेना के समर्थक, कार्यकर्ता और नेता न केवल महसूस कर रहे थे, बल्कि यदा-कदा व्यक्त भी कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे इस सबकी अनदेखी करते रहे। वह ऐसे कई निर्णय भी करते रहे, जो शिवसेना के मूल चरित्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। हद तो तब हो गई, जब ऐसे फैसलों का बचाव करते हुए शिवसेना नेताओं की ओर से बाल ठाकरे के विचारों को भी खारिज करने की कोशिश की गई। यह सत्ता की भूख का ही नतीजा था कि शिवसेना कांग्रेस नेताओं की ओर से उन वीर सावरकर के अपमान की भी अनदेखी करती रही, जिन्हें वह अपना प्रेरणास्रोत बताती है। राकांपा प्रमुख शरद पवार कह रहे हैं कि शिवसेना में बगावत उसका आंतरिक मामला है। इसके पहले कांग्रेस की ओर से यह कहा जाता रहा है कि वह अगला चुनाव अपने दम पर लड़ेगी।

अमेरिका के कारण खाद्य संकट

संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को गेहूं का निर्यात निलंबित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कह रहे हैं। अध्ययन करने से जो आंकड़े सामने आते हैं, उनसे जाहिर होता है कि आसन्न खाद्य संकट के लिए भारत नहीं, बल्कि अमेरिका को दोषी ठहराया जाना चाहिए। अनाज मनुष्यों के इस्तेमाल होने की चीज है, लेकिन अमेरिकी सरकार के वित्त पोषित इथेनॉल उद्योग 473 मिलियन टन अनाज के वैश्विक विश्व व्यापार के 35 फीसदी के बराबर का उपयोग करता है। भूख को रोकने के लिए निर्धारित भारतीय निर्यात प्रतिबंध इस राशि के दो फीसदी से भी कम को प्रभावित करेगा। इस मामले में वास्तविक दोषी पशु आहार के साथ-साथ अन्य गैर-खाद्य उपयोगों, मुख्य रूप से कृषि-ईंधन के लिए भोजन का उपयोग होना है। विडंबना यह है कि अमेरिकी सरकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत से गेहूं निर्यात को निलंबित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कह रहे हैं। उनकी चिंता यह है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच निर्यात प्रतिबंध भोजन की कमी को बढ़ा देंगे। लेकिन तर्क तकनीकी या नैतिक रूप से जमीन पर नहीं टिकता।

विदेश व्यापार के महानिदेशक, संतोष कुमार सारंगी कहते हैं कि गेहूं की कीमतों में वैश्विक स्तर पर अचानक तेजी आई है, जिसके परिणामस्वरूप भारत और पड़ोसी देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में है। नतीजतन सरकार ने अपनी निर्यात नीति में कुछ संशोधन किए। हालांकि सरकार ने गेहूं निर्यात को प्रतिबंधित करने पर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य विभाग की तरफ से जारी 13 मई के अपने आदेश में कुछ छूट की घोषणा की। यह निर्णय किया गया कि जहां कहीं भी गेहूं की खेप जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंपी गई है और 13 मई को या उससे पहले उनकी व्यवस्था में पंजीकृत की गई है, ऐसी खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।

सरकार ने मिस्र के लिए एक गेहूं शिपमेंट की भी अनुमति दी, जो पहले से ही कांडला बंदरगाह पर लोड हो रहा था। इसके बाद मिस्र सरकार ने कांडला बंदरगाह पर लदान किए जा रहे गेहूं के माल की अनुमति देने का अनुरोध किया। मिस्र को गेहूं के निर्यात का जिम्मा उठा रही कंपनी मीरा इंटरनेशनल इंडिया ने भी 61,500 मीट्रिक टन गेहूं की लोडिंग पूरी करने के लिए एक प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें से 44,340 मीट्रिक टन गेहूं पहले ही लोड किया जा चुका था और केवल 17,160 मीट्रिक टन लदान किया जाना बाकी था। सरकार ने 61,500 मीट्रिक टन की पूरी खेप की अनुमति देने का निर्णय किया और इसे कांडला से मिस्र जाने की अनुमति दी।

33 फीसदी से अधिक अन्न का गैर-खाद्य उपयोगों में इस्तेमाल

भोजन की कमी के बजाय वास्तविकता यह है कि जितना हम खाते हैं, दुनिया उससे कहीं अधिक अन्न का उत्पादन करती है। विश्व स्तर पर उत्पादित अन्न का 33 फीसदी से अधिक पशु आहार के साथ-साथ अन्य गैर-खाद्य उपयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से कृषि-ईंधन। करीब 400 मिलियन टन मकई का 40 फीसदी (160 मिलियन टन) से अधिक इथेनॉल उत्पादन में जाता है। अन्य 40 फीसदी पशु आहार में जाता है। केवल 10 फीसदी का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, जबकि बाकी 10 फीसदी का निर्यात किया जाता है। साल 2022-2023 में भारत से 10 मिलियन टन से अधिक गेहूं निर्यात करने की संभावना नहीं थी, जो कि अमेरिकी संख्या की तुलना में नगण्य है। वास्तव में कृषि-ईंधन के उत्पादन के लिए भोजन की बढ़ती मात्रा-वैश्विक अनाज बाजारों में तनाव पैदा करने वाला एक प्रमुख कारक है। अमेरिका में इथेनॉल उत्पादन 2001 में 3.6 मिलियन बैरल से बढ़कर अब 102 मिलियन बैरल से अधिक हो गया था। यह इस तथ्य के बावजूद है कि इथेनॉल गैसोलीन की तुलना में कम से कम 24 फीसदी अधिक कार्बन गहन है। यह किसी पाखण्ड से कम नहीं है कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व व्यापार संगठन, सभी देशों से व्यापार को खुला रखने और खाद्य या उर्वरक पर निर्यात प्रतिबंध जैसे प्रतिबंधात्मक उपायों से बचने का आग्रह कर रहे हैं, जिससे सबसे कमजोर लोगों की पीड़ा ही बढ़ेगी।

सरकार ने पहले भारत में समग्र खाद्य सुरक्षा स्थिति का प्रबंधन करने के लिए और पड़ोसी और कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था, जो गेहूं के लिए वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं और पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इस आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां निजी व्यापार द्वारा लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से पूर्व प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ उन स्थितियों, जहां भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की अनुमति दी जाती है, जब उनकी सरकारों का अनुरोध होता है।

आदेश ने तीन मुख्य उद्देश्यों को पूरा किया- भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति की जांच करना। यह अन्य देशों को खाद्य घाटे का सामना करने में मदद करता है और यह एक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की विश्वसनीयता बनाए रखता है। आदेश का उद्देश्य गेहूं की आपूर्ति की जमाखोरी को रोकने के लिए गेहूं बाजार को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करना भी है। दिलचस्प बात यह है कि द ऑकलैंड इंस्टीट्यूट, सैन फ्रांसिस्को के नीति निदेशक फ्रेडरिक मूसो ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की 6 मई, 2022 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया अनाज की अपेक्षाकृत आरामदायक आपूर्ति स्तर का लाभ उठाती है। विश्व बैंक ने भी इसकी पुष्टि की है, जिसने पाया कि अनाज का वैश्विक स्टॉक ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर है और युद्ध शुरू होने से पहले ही रूसी और यूक्रेनी गेहूं का लगभग तीन-चौथाई निर्यात किया जा चुका था। इन सबका मतलब है कि वास्तव में भोजन की कोई कमी नहीं है।

● अक्स ब्यूरो

बिखराव के साथ लक्ष्य एक समान

देश में मोदी-शाह की भाजपा के खिलाफ विपक्ष ने एकजुट होने के कई प्रयास किए लेकिन अभी तक सारे प्रयास विफल हुए हैं। ऐसे में अब राष्ट्रपति चुनाव का ऐसा अवसर आया है, जब विपक्ष एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा सकता है। दरअसल, बिखराव के साथ विपक्ष का एक ही लक्ष्य है कि भाजपानीत एनडीए सरकार को किसी तरह सत्ता से बाहर किया जाए। लेकिन विपक्ष के सारे दांव अब तक खाली गए हैं।

राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने एकजुट होने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए साझा उम्मीदवार खड़ा करने का प्रयास किया गया है। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी से शुरू होकर राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की सुई पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नाम पर आकर खत्म हो गई है। वे विपक्ष के साझे उम्मीदवार बन गए हैं। यह दौर बड़ा ही दिलचस्प है। राष्ट्र के राजनीतिक रंगमंच पर तीन अलग-अलग नाटक खेले जा रहे हैं। इसमें विपक्षी दल अपनी-अपनी पटकथाओं पर अलग-अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। कांग्रेस प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को तलब किए जाने के विरुद्ध सत्याग्रह कर रही है। विपक्षी दलों की एक टुकड़ी आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई भाजपा की निलंबित प्रवक्ता की टिप्पणी पर बवाल का जिम्मा एआईएमआईएम जैसी खांटी मुस्लिम पार्टी और कथित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उठा रखा है। यह पूरा परिदृश्य राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं एवं रणनीति में भिन्नता को ही दर्शाता है, फिर भी उन सभी का एक लक्ष्य समान है और वह यह कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना। इसके विपरीत भाजपा का पूरा ध्यान चुनाव जीतने पर केंद्रित है।

विपक्ष से बेपरवाह भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों पर अपनी नजर गड़ाई हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुजरात का चुनावी रण होगा। सत्तारूढ़ दल अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई अवांछित टिप्पणी पर अरब देशों की प्रतिक्रिया वाले विवाद से भी उसने अपना पीछा छुड़ा लिया है। प्रधानमंत्री नई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा में लगे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अगले डेढ़ साल में 10 लाख सरकारी भर्तियों का ऐलान किया तो वहीं अग्निपथ जैसी योजना की घोषणा की गई, जिसमें हर साल 40,000 से अधिक भर्तियों की गुंजाइश है। पार्टी को अपने बुलडोजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है, की दमदार नीतियों की एक तबके द्वारा हो रही आलोचना की भी कोई परवाह नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो जहां विपक्ष यह सिद्ध करने पर तुला हुआ है कि देश में कुछ भी सही नहीं चल रहा, वहीं भाजपा यह दर्शा रही है कि सबकुछ सामान्य ढंग से चल रहा है। इस विभाजन से तो आम नागरिकों को दुविधा में होना चाहिए। हालांकि वे नेताओं की नूरा-कुश्ती के बजाय अपने दैनिक जीवन की तात्कालिक चुनौतियों से कहीं ज्यादा जूझ रहे हैं। विपक्षी दल इसी बिंदु को अनदेखा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उनकी असमान-असंगत रणनीतियों के कोलाहल में वास्तविक मुद्दों की आवाज दम तोड़ती जा रही है। इससे विपक्षी नेताओं में इसी विसंगति के ही संकेत दिखते हैं कि वे अपनी महत्वाकांक्षा के जाल में ही उलझे हुए हैं। स्पष्ट है कि इसने जनता को मायूस किया है।

बीते दिनों कांग्रेस ने उदयपुर में अपना बहुप्रचारित नव संकल्प (चिंतन) शिविर आयोजित किया। उस शिविर में पारित हुए संकल्प की स्याही सूखी भी नहीं थी कि उसके मर्म को अनदेखा किया जाने लगा। राहुल गांधी ने विदेश दौर पर जो तमाम साक्षात्कार दिए, उनसे यही साबित हुआ कि पार्टी का सर्वेसर्वा कौन है। कहा तो यह गया था कि राज्यसभा के लिए प्रत्याशी चयन हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त राजनीतिक मामलों की समिति गठित की गई है और कहां यह बात सामने आई कि परिवार के तीन सदस्यों ने ही यह सब तय कर लिया और वह भी कथित रूप से जूम कॉल पर। इससे यही संकेत निकला कि परिवार संचालित उपक्रम में कुछ भी नहीं बदला। इसी शिविर में भारत जोड़ो आंदोलन का जोरशोर से ऐलान हुआ। कहा गया कि इसके अंतर्गत राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करेंगे। बाद में यह सामने आया कि वह पूरी यात्रा के साथ नहीं जुड़ना चाहते और उसका नेतृत्व तो कतई नहीं करेंगे। इसके बजाय पार्टी ने अपनी पूरी ऊर्जा ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस के विरोध में सत्याग्रह नाम से देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन में लगा दी। इसका संदेश स्पष्ट है

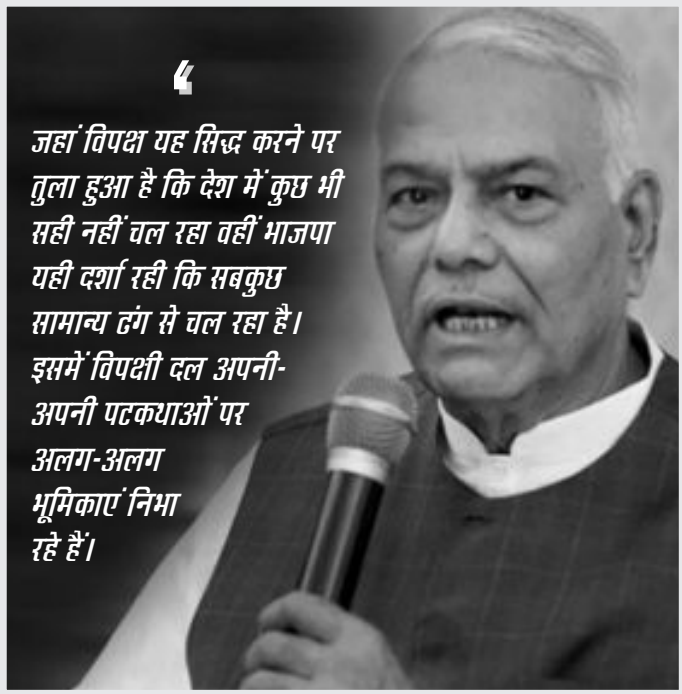

विपक्ष बार-बार क्यों फिसलता रहा

पहले शरद पवार, फिर फारूक अब्दुल्ला और अब महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी, तीनों ने उत्साही विपक्ष के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के तत्काल बाद विपक्ष में राष्ट्रपति पद पर कब्जा करने की जो तेजी दिखाई दी थी, वह धीरे-धीरे अब सतह पर आ गई है। अंततः यशवंत सिन्हा प्रत्याशी बने। जब तक राष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, विपक्ष की ओर से सबसे ज्यादा सक्रियता 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार 2 ही नेताओं में दिख रही थी। एक तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी और दूसरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। ममता और केसीआर राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से रायसीना के भव्य भवन में अपना प्रत्याशी लगाने की कोशिशों में लगे हैं। सबको पता है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरा सी भी चुनौती देनी है तो एकजुट होकर लड़ना होगा।

राष्ट्रपति चुनाव में मतों का गणित

यह रिपोर्ट लिखे जाने समय तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए बहुमत के आंकड़े से करीब 13,000 मत (वोट) दूर है। पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल पर निर्भर है। दोनों का समर्थन मिल जाता है, तो एनडीए उम्मीदवार की जीत का रास्ता साफ हो जाएगा। इन दोनों दलों ने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। राज्यों में कुल 4,790 विधायक हैं। उनके वोटों का मूल्य 5.4 लाख (5,42,306) होता है। सांसदों की संख्या 767 है, जिनके मतों का कुल मूल्य भी करीब 5.4 लाख (5,36,900) बैठता है। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल मत लगभग 10.8 लाख (10,79,206) हैं। एक विधायक के मत (वोट) का मूल्य राज्य की आबादी और विधायकों की संख्या के आधार पर तय होता है। सांसदों के मत का मूल्य विधायकों के मतों का कुल मूल्य को लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की संख्या से भाग देकर तय होता है। एनडीए के पास 5,26,420 मत हैं। यूपीए के हिस्से में 2,59,892 मत हैं। अन्य (तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल, सपा और वामपंथी) के पास 2,92,894 मत हैं। अगर वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल (43,500+31,700 मत) एनडीए के पाले में जाते हैं, तो उसका उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा, अन्यथा एनडीए को दिक्कत नहीं आएगी। कारण यह है कि हाल के महीनों में क्षेत्रीय दलों के साथ भाजपा के संबंध खराब हुए हैं। शिवसेना और अकाली दल उसके पाले से बाहर हैं। अभी तक भाजपा विपक्ष के एकजुट नहीं होने से ताकतवर दिखती। यदि विपक्ष एकजुट होता है, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश में दिख रहे हैं। गैर-कांग्रेस उम्मीदवार बनाकर विपक्ष का काम नहीं चलेगा। ऐसे में सब साथ आते हैं, तो कुछ कमाल हो सकता है।

कि संगठन के लिए देश और पार्टी से पहले परिवार के मामले ही प्राथमिकता में हैं।

कहते हैं कि अपनी लड़ाई का अखाड़ा चुनने में बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए और बड़ा युद्ध जीतने के लिए छिटपुट लड़ाइयां हारनी भी पड़ती हैं। समझना कठिन है कि ईडी की पूछताछ को राजनीतिक रंग देने से कांग्रेस को क्या लाभ मिलने वाला है? इसे कानूनी सलाहकारों के साथ मिलकर एक सामान्य मामले के रूप में संभाला जा सकता था। इस मामले में कांग्रेस की रणनीति के पीछे दो मकसद नजर आते हैं। पहला यह कि वह विक्टिम कार्ड खेलकर गांधी परिवार को बलिदानी के रूप में दिखाना चाहती है। दूसरा, वह यह दर्शाने की फिराक में है कि मोदी सरकार अपने विरोधियों के विरूद्ध जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। यह रणनीति तभी कारगर हो सकती है, जब पूछताछ में कुछ निकलकर सामने न आए। हालांकि इसकी संभावना कम ही दिखती है कि बिना किसी मजबूत साक्ष्य के सरकार ने इतने ऊंचे मामले में एजेंसियों को आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी दिखाई होगी। अब कुछ ठोस बात सामने निकलकर आती है तो यह दांव गांधी परिवार के लिए उलटा साबित हो सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी को एक बड़ा चुनावी हथियार थमा देगा।

राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेशी वाले दिन इसे 'राजनीतिक बदला' बताते हुए जिस तरह विरोध के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ईडी दफ्तर के बाहर जुटे, उससे यह जाहिर हो गया है कि कांग्रेस अब मोदी सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई की तैयारी कर चुकी है। इधर कांग्रेस यह सब कर रही थी, उधर तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्ष के 22 नेताओं को 15 जून को दिल्ली में बैठक बुलाकर भाजपा के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश की।

राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए और विपक्ष के उम्मीदवारों के नाम साफ हो गए हैं। मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव को जरिया बनाना चाहता है। विपक्ष की कोशिश है कि किसी भी सूरत में भाजपा (एनडीए) को और वोटों का इंतजाम करने से रोका जाए। एनडीए के पास अभी राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकने लायक वोट नहीं हैं। कांग्रेस सहित विपक्ष उस पर दबाव बनाए रखना चाहता है।

उधर राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव भी राष्ट्रीय राजनीति में कूदने की तैयारी में जुट गए हैं। वह अपनी पार्टी टीआरसी का विस्तार करके उसे राष्ट्रीय स्वरूप देने की तैयारी कर रहे हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को सूचित किया है कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझे उम्मीदवार का समर्थन करेगी।

इस तरह विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव के लिए अलग-अलग ही सही भाजपा के खिलाफ मजबूत तैयारी करता दिख रहा है। महीने बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव है, लिहाजा वार्ताओं का दौर शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस शरद पवार को राष्ट्रपति पद के लिए आगे करने के हक में थी। ऐसा करके पार्टी एक तीर से दो निशाने साधना चाह रही थी। एक, पवार के कद को देखते हुए विपक्ष उनके नाम पर एकजुट हो सकता था। भाजपा के पास अभी भी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए पूरे वोट नहीं हैं। ऐसे में पवार उस पर भारी पड़ सकते थे, लेकिन अंत में यशवंत सिन्हा का नाम फाइनल किया गया।

इस बीच टीआरएस नेता और तेलंगना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव भी राष्ट्रीय राजनीति की चाह रखने लगे हैं। कई बार वे कांग्रेस के समर्थन में दिखते हैं, और कहते रहे हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की कल्पना नहीं की जा सकती। भले तेलंगना की राजनीति में कांग्रेस उनकी विरोधी है, एक समय वह कांग्रेस के ही नेता रहे हैं। हाल में अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने उनकी सरकार की कुछ मुद्दों को लेकर आलोचना भी की थी।

राव जल्द ही अपनी पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, इस पार्टी का नाम भी तय कर लिया गया है और यह भारतीय राष्ट्र समिति हो सकता है। पिछले 5-6 महीने से राव अचानक सक्रिय हुए हैं और वे शरद पावर, ममता बनर्जी सहित कई बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। राव को विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और ऐसे में प्रधानमंत्री पद के लिए चंद्रशेखर, देवेगौड़ा या आईके गुजराल की तरह किसी को मौका मिल सकता है।

● **विपिन कंधारी**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से कई शिकार करने में महारथ हासिल कर चुके हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाकर देश के बड़े वोटबैंक को साधने की कोशिश की है। अपनी इस रणनीति के तहत भाजपा ने आगामी ढाई साल में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर फोकस किया है। पार्टी को उम्मीद है कि मुर्मू को प्रत्याशी बनाए जाने से भाजपा को आदिवासी वर्ग का साथ मिलेगा, जिसका लाभ चुनावों में होगा।

ढाई साल के मिशन पर फोकस

द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर भाजपा ने अगले ढाई साल में होने वाले चुनावों की रणनीति तैयार कर ली है। वर्ष 2024 में लोकसभा के साथ ही इस दौरान 18 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इनमें से चार राज्य ऐसे हैं जहां आदिवासी आबादी 50 फीसदी से ज्यादा, मतलब बहुसंख्यक है। वहीं 13 राज्य ऐसे हैं जहां आदिवासी आबादी 10 फीसदी से ज्यादा है। इसमें पूर्वोत्तर के भी 6 राज्य शामिल हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। उन्हें एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करना भाजपा की एक दीर्घकालिक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इसका असर उनके नाम की घोषणा के साथ ही दिखने भी लगा। द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा की रहने वाली हैं। लिहाजा उनके नाम की घोषणा होते ही ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा कर दी। उधर बिहार में जेडीयू समेत राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। एनडीए के घटक हिन्दुस्तानी आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। केवल भाजपा और बीजद के ही मतों को मिला दिया जाए तो, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में तकरीबन 52 फीसदी मत हैं, जो कि जीत के लिए पर्याप्त हैं।

द्रौपदी मुर्मू, संताल आदिवासी समूह से आती हैं, जिनकी सबसे ज्यादा आबादी झारखंड में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद संताल समुदाय से हैं और द्रौपदी मुर्मू से उनके बेहतर रिश्ते हैं। लिहाजा संभावना जताई जा रही है कि 30 विधायकों वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा भी राज्य में कांग्रेस गठबंधन के इतर राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे सकता है। झारखंड के अलावा असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी संताल समुदाय की मौजूदगी है।

वर्ष 2024 तक 18 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें से चार राज्य मेघालय, नगालैंड, मिजोरम और आंध्र प्रदेश में आदिवासी बहुसंख्यक हैं। इन राज्यों की कुल आबादी में आदिवासियों की संख्या 50 फीसदी से ज्यादा है। 2024 तक 9 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें गुजरात, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मप्र, राजस्थान, सिक्किम, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल हैं। इन राज्यों की कुल आबादी में आदिवासियों की संख्या लगभग 10 फीसदी से 34 फीसदी तक है। 4 अन्य राज्य जहां 2024 तक विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें भी आदिवासी आबादी 5 फीसदी से 9 फीसदी तक है। ये 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हिमाचल और

दलित के बाद अब आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश

मोदी सरकार पिछली बार दलित समुदाय से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर चुनावी दृष्टिकोण से एक बड़े वर्ग तक संदेश देने में सफल रही थी। इस बार उसने आदिवासी समुदाय को साधने का प्रयास किया। भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से उपेक्षित रहे दलित और आदिवासी जैसे समुदाय के लोगों को इस प्रकार शीर्ष स्तर पर प्रतिनिधित्व देकर मोदी सरकार अपने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले समावेशी राजनीति के नारे को वास्तविकता का रूप देने के लिए तत्पर दिखाई पड़ती है। मुर्मू का चयन भी इसी कड़ी के अंतर्गत किया गया है। हाल-फिलहाल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें आदिवासी समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है। इसे देखते हुए यह प्रधानमंत्री मोदी का एक और राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक कहा जा सकता है। गौरतलब है कि इसी वर्ष गुजरात, अगले वर्ष के अंत में राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों में चुनाव होने हैं।

कर्नाटक में वर्तमान में भाजपा की सरकार है। इन 18 राज्यों में केवल हरियाणा अकेला है, जहां आदिवासी आबादी नहीं है, लेकिन यहां भी पहले से भी भाजपा की सरकार है।

वर्ष 2024 तक जिन 18 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 11 राज्यों में पहले से ही भाजपा गठबंधन (एनडीए) की सरकार है। 18 में से 7 राज्य ऐसे हैं, जहां फिलहाल भाजपा की सरकार नहीं है। ये राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड। आदिवासी समुदाय के जरिए भाजपा इन राज्यों में भी चुनावी गणित अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी। 2014 तक जिन 18 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से हरियाणा को हटा दें तो शेष 17 राज्यों में देश की 84.4 फीसदी आदिवासी आबादी निवास करती है। इस तरह से आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर भाजपा ने अगले ढाई वर्ष के चुनावों में विपक्ष को चित करने का दांव खेल दिया है।

2024 तक जिन 18 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें पूर्वोत्तर के 6 राज्य भी शामिल हैं। ये राज्य हैं मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश। इन राज्यों में आदिवासी आबादी 34 से 94 फीसदी तक है। वर्तमान में यहां भाजपा की सरकार है। राष्ट्रपति चुनाव के जरिए भाजपा ने एक बार फिर पूर्वोत्तर में कमल खिलाने की तैयारी कर ली है। वर्ष 2018 में मप्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार की मुख्य वजह आदिवासी वोट बैंक रहा था। इन चुनावों में आदिवासी मतदाताओं ने भाजपा से मुंह मोड़ लिया था। इससे पहले वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 27 पर जीत दर्ज की थी। 2018 में आदिवासी वोट बैंक के मुंह मोड़ने के बाद भाजपा ने इस तरफ फोकस किया और 2019 के लोकसभा चुनावों में आदिवासियों की 31 सीटें जीतने में सफलता मिली। आदिवासी समुदाय के जरिए भाजपा आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में विपक्ष को पटखनी देने की तैयारी में है।

राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग और विपक्षी खेमे ने अपने-अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। जहां सत्तारूढ़ पक्ष ने बहुत ही रणनीतिक रूप से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन भेजने की पहल की, वहीं विपक्ष की दमदार साझा उम्मीदवार उतारने की रणनीति धरी की धरी रह गई। शरद पवार जैसे कद्दावर नेता द्वारा राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने से इनकार करने के बाद फारूक अब्दुल्ला और गोपालकृष्ण गांधी ने भी इसके प्रति अनिच्छा जताई। इससे यही प्रतीत होता है कि विपक्ष की ओर से यह पहले ही हारी हुई लड़ाई थी और कोई भी उसमें बलिदान होने को तैयार नहीं था। जिस तरह चौथी पसंद के रूप में यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बनी, उससे वह एक मजबूरी का विकल्प ही अधिक लगते हैं।

भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाकर विपक्षी खेमे में और खलबली मचा दी है। अब हेमंत सोरेन जैसे जनजाति समुदाय के नेताओं के लिए बड़े धर्मसंकट और दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या वह चाहेंगे कि इतिहास उन्हें देश में पहली बार शीर्ष पद पर विराजमान होने जा रही जनजाति समुदाय की महिला की राह में बाधक बनने वाले नेता के रूप में याद करे? केवल हेमंत सोरेन ही नहीं छत्तीसगढ़, मप्र, राजस्थान और ऐसे ही जनजाति बहुल वाले राज्यों के विपक्षी नेताओं के समक्ष भी यह संकट उत्पन्न होगा कि वे पार्टी लाइन पर मतदान करें या फिर सामाजिक अस्मिता के पहलू को प्राथमिकता दें?

यह एक संयोग ही है कि इस बार रायसीना की राह में उतरे दोनों प्रत्याशियों का झारखंड से कोई न कोई संबंध है। यशवंत सिन्हा जहां अविभाजित बिहार में जन्मे और झारखंड की राजनीति में सक्रिय रहे, वहीं द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। अब दोनों अपने अभियान को परवान चढ़ाएंगे। यह अभियान चाहे जिस प्रकार चलाया जाए, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना एक औपचारिकता मात्र रह गया है। स्वतंत्र भारत का इतिहास रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में कभी भी सत्तापक्ष के उम्मीदवार को मुंह की नहीं खानी पड़ी। इस बार भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजग का पलड़ा पहले से ही भारी था। निर्वाचक मंडल में करीब 49 प्रतिशत मत पहले से ही उसके पास थे। बीजू जनता दल द्वारा द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन की घोषणा से आवश्यक मत भी पूरे हो गए हैं। जदयू ने भी मुर्मू का साथ देने का ऐलान कर दिया है। यह लगभग तय है कि आने वाले दिनों में मुर्मू के लिए समर्थन निरंतर बढ़ता जाएगा।

आखिर भाजपा ने तमाम संभावित नामों में से द्रौपदी मुर्मू के नाम पर ही क्यों मुहर लगाई? इस प्रश्न के उत्तर की पड़ताल में कई पहलू स्पष्ट होते जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतीकों की राजनीति में महारत रखते हैं और द्रौपदी मुर्मू के चयन में भी उनकी कसौटी में यह पैमाना प्राथमिकता में रहा।

● इन्द्र कुमार

मिशन 2023 और 2024 का खाका तैयार करेगी भाजपा

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा मिशन 2023 और 2024 की रणनीति पर मंथन करेगी। दरअसल पार्टी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। इसलिए पार्टी अभी से इसकी तैयारी में जुटी हुई है। इस पर मंथन के लिए इस बार दक्षिण भारत को चुना गया है। पार्टी एक रणनीति पर पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहती है। गौरतलब है कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2-3 जुलाई को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होनी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर बैठक की सुरक्षा को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ता भी इस बैठक को लेकर उत्साहित हैं। भाजपा की 2 और 3 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर हैदराबाद पुलिस सुरक्षा इंतजाम करने में लगी हुई है। बताया गया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य शीर्ष नेता हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एचआईसीसी) में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव हैं। चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ताधारी दल कांग्रेस और भाजपा ने चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने उदयपुर के चिंतन शिविर में तैयार हुए 'फॉर्मूला 75' पर काम तेज कर दिया है। वहीं भाजपा ने भी अपना 'फॉर्मूला 75' बनाया है। कांग्रेस के 'फॉर्मूला 75' के तहत कांग्रेस के विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि ग्राउंड लेवल पर भ्रमण करेंगे। कांग्रेस नेता हर विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर पैदल चलकर जनता से मुखातिब होंगे। इसमें कांग्रेस के विधायक और सांसद भी शामिल रहेंगे। वहीं भाजपा के 'फॉर्मूला 75' के तहत भाजपा के सांसद, विधायक और पदाधिकारी बूथ में 15 दिनों में 75 घंटे का वक्त देंगे। इससे भाजपा भी जनता के बीच पकड़ बनाने को तैयार है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले ही कांग्रेस नेताओं के पसीने छूटने वाले हैं। क्योंकि प्रदेश कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर पैदल चलकर जनता के बीच जाने का फैसला लिया है। डिजिटल प्रचार के इस दौर में कांग्रेस ने नेताओं को घर से बाहर निकलकर मतदाताओं से सीधे मुखातिब होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल उदयपुर के चिंतन शिविर के निर्देशों को लागू करने की कार्ययोजना तैयार करने के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नव संकल्प शिविर का आयोजन किया। जिसमें ये फैसला लिया गया कि उदयपुर के चिंतन शिविर के हर एक निर्देश का पालन किया जाएगा। इसके अलावा मंथन से निकले 75 के फॉर्मूले को भी प्रदेश में लागू किया जाएगा। जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राजधानी में बड़ा आयोजन भी किया जाएगा।

बता दें कि उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने हर जिले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने का फैसला लिया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे विधानसभावार कर दिया गया। इसकी बड़ी वजह एंटीइंकमबेंसी को दूर करना माना जा रहा है। पार्टी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कई विधायकों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से दूरी बना ली है और जमीनी स्तर पर भी जनता से संवाद कम हो गया है। इसलिए जिले की जगह हर विधानसभा में 75 किलोमीटर तक विधायक, नेता और पदाधिकारी पैदल चलेंगे। पीसीसी संचार विभाग प्रमुख का कहना है कि इसका फायदा पार्टी को मिलेगा।

वहीं कांग्रेस के साथ भाजपा ने भी अगले साल के चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। हाल ही में भाजपा की कार्यसमिति और पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई थी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भाजपा के विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों को 15 दिनों में 75 घंटे बूथ में बिताने का टारगेट दिया है। वहीं कांग्रेस के 'फॉर्मूला 75' पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस भाजपा की नकल कर रही है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए संजय श्रीवास्तव ने कहा कि जो विधायक साढ़े तीन साल में साढ़े सात किलोमीटर भी पैदल ना चले हों वो कहां 75 किलोमीटर पैदल चल पाएंगे। छत्तीसगढ़ की दोनों ही प्रमुख पार्टियां 75 का फॉर्मूला लेकर मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के 75 किलोमीटर ज्यादा भारी पड़ते हैं या भाजपा के 75 घंटे। दूरी और समय में से कौन इस बार बाजी जीत पाता है।

लगातार 15 सालों तक सत्ता चलाने के बाद साल 2018 में विपक्ष में आई छत्तीसगढ़ भाजपा के अब तक मजबूत विपक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। गाहे-बगाहे नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा होते ही रही है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनीतिक **विश्लेषक** रामअवतार शर्मा का कहना है कि मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित संगठन के अन्य बड़े पदाधिकारी रमन गुट के हैं और जो धार विपक्ष में होना चाहिए वह धार धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। इन सबके बीच एक बार फिर भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की बयार बहने लगी है। बदलाव के बयार को उस वक्त और हवा मिली जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से रायपुर लौटे डॉ. रमन सिंह ने कहा कि कुछ नेता तो कपड़े सिलवाकर बैठे हुए हैं। भाजपा में बदलाव के इस बयार पर कांग्रेस चुटकी लेते हुए कह रही हैं कि भाजपा संगठन ताश के 52 पत्तों की तरह है, जिसे भी जिम्मेदारी दी जाए सब के सब दागदार हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भाजपा नेतृत्व किसी को भी दे, लेकिन हाल जस का तस ही रहना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ भाजपा के सभी नेताओं का हाल एक जैसा ही है। ऐसा नहीं हैं कि छत्तीसगढ़ संगठन में बदलाव की बयार कोरी बयार की तरह बह रही हो। दरअसर भाजपा संगठन में जिम्मेदारों के कार्यों से संगठन आलाकमान बेहद ही नाराज चल रहा है। युवामोर्चा हो या महिला मोर्चा दोनों के प्रमुख जिम्मेदारों को कई बार फटकार लग चुकी है। मगर इसका व्यापक असर दिखाई नहीं दे रहा। इन सबके बीच जो चर्चा है वह यह कि प्रमुख पदों से औसत नेताओं की छुट्टी होगी। कार्यकारी पद देने की भी तैयारी में भाजपा आलाकमान है। इसके अलावा अध्यक्ष का चेहरा बदलने चर्चा तेज, दो-तीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चा, युवा और महिला मोर्चे के अध्यक्ष को बदलने की भी चर्चा, अलग-अलग वर्ग के नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी, सभी वर्गों को साधने संगठन में प्रमुख पद देने की कवायद, रमन गुट के ताकत को कम करने अन्य गुटों के नेताओं को एंट्री की भी चर्चा तेज है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

संघ की शरण में भाजपा

छत्तीसगढ़ में सत्ता का वनवास झेल रही भाजपा एक बार फिर से संघ की शरण में जाती दिख रही है। दरअसल राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा उससे पहले अपने संगठन को धार देने में जुट गई है। बता दें कि 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान ये चर्चा थी कि संघ की भाजपा संगठन पर तत्कालीन सत्ता हावी हो गई थी। जिसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। हार और सत्ता से दूर रहने का असर पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ा है। यही वजह है कि पार्टी ने अभी से ही संगठन को धार देनी शुरू कर दी है। पार्टी प्रदेशभर में जिला संगठनों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर शहर और रायपुर ग्रामीण के नेताओं का प्रशिक्षण शिविर 17 से 19 जून तक राजधानी के पास चंपारण में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में करीब 300 नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान 3 दिन तक भाजपा संगठन, रीति-नीति, इतिहास और वर्तमान परिपेक्ष्य की चुनौतियों के साथ कुल 15 बिंदुओं पर प्रशिक्षण हुआ।

फडणवीस नए चाणक्य

महाराष्ट्र की राजनीति में 10 जून से 29 जून 2022 के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती के असली चाणक्य हैं और नि:संदेह मराठा क्षत्रप शरद पवार का युग लगभग समाप्त हो चुका है। जाहिर है इसे पवार साहब को स्वीकार करके सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि यह भी साबित हो गया है कि बालासाहेब ठाकरे के अयोग्य उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर उनकी आड़ में राज्य में सत्ता के संचालन की उनकी कोशिश अंतत: नाकाम हो गई।

शरद पवार की इमेज जहां आज भी वर्ष 1978 के उस राजनेता की है, जिसने मुख्यमंत्री वंसतदादा पाटिल के साथ कपट किया और उनके विधायकों को तोड़कर राज्य की सत्ता हथिया ली थी। पवार आज भी उस तिकड़मी छवि से बाहर नहीं आ सके हैं। लेकिन दूसरी ओर फडणवीस की इमेज मौजूदा राजनीतिक बवंडर के दौरान जेंटलमैन नेता की बनी रही। एकनाथ शिंदे से बगावत करवाई, लेकिन इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला करार दे दिया। शिवसेना विधायकों की बगावत करवा करके फडणवीस ने पवार और उद्धव दोनों को उन्हीं की स्टाइल में करारा जवाब दिया है। चतुर राजनेता की चतुर नीति से सांप भी मर गया और लाठी भी अक्षुण्ण रही। एक तरह से यह 2019 का भूल-सुधार भी कहा जाएगा।

वैसे सोशल मीडिया पर हैशटैग मी पुन: येईन मतलब मैं फिर से आ रहा हूं, ट्रेंड करने लगा है। यह वर्ष 2019 में फडणवीस का चर्चित स्लोगन था, जो उन्होंने अपनी जनादेश यात्रा के दौरान लगाया था। उस समय वह ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार हो गए थे और उद्धव ठाकरे के चक्रव्यूह में फंस गए थे, इसीलिए नवंबर 2019 में जब बाल ठाकरे की ठाकरे परिवार के चुनाव की राजनीति से दूर रखने की परंपरा को तोड़ते हुए शरद पवार ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई तो फडणवीस के स्लोगन मी पुन: येईन का मजाक उड़ाया जाने लगा था। कहा जा सकता है कि नवंबर 2019 के बाद देवेंद्र फडणवीस को लग गया कि ठाकरे परिवार और पवार परिवार पर भरोसा करना उनके राजनीतिक जीवन के दो ब्लंडर थे। पहला 2019 में चुनाव से पहले भाजपा के विन-विन पोजिशन में रहने के बावजूद शिवसेना से गठबंधन करना और दूसरे चुनावी नतीजे आने के बाद अजित पवार पर भरोसा करना और एकदम सुबह राजभवन में उनके साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, उनकी राजनीतिक भूल थी।

विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद फडणवीस राजनीति रूप से अधिक परिपक्व हुए। उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि कौन उनका असली साथी है और कौन हाथ में कटार लेकर उनके साथ है। बतौर विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस कभी घर नहीं बैठे। यहां तक कि जब कोरोना महामारी के कारण अनिच्छा से मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने वाले उद्धव ठाकरे मातोश्री से बाहर ही नहीं निकलते थे, वहीं फडणवीस राज्य का दौरा करते रहे और लोगों का दुख-दर्द बांटते रहे। कोंकण जैसी आपदा समेत कई जगह तो फडणवीस या उनके लोग सरकार से पहले पहुंच जाते थे। इससे राज्य की जनता का फडणवीस में भरोसा बढ़ता ही गया। राज्य के लोग भी मानने लगे कि 2019 के चुनाव में जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन को वोट दिया था, उसे राजनीतिक साजिश के तहत भले सत्ता नहीं मिल पाई लेकिन वह नेता उनसे कटा नहीं है।

कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान फडणवीस उतने ही सक्रिय रहे, जितने सक्रिय वह राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए थे। उनकी सक्रियता का आलम यह था कि वह दो-दो बार वह कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन जनता की सेवा करने के अपने इरादे से विचलित नहीं हुए। यही बात फडणवीस के पक्ष में जाती है। देश की राजनीति में फडणवीस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। राजनीतिक पंडित मानने लगे हैं कि फडणवीस में भाजपा की अगली पीढ़ी के शीर्ष नेता बनने की पूरी कूव्वत है और जब नरेंद्र मोदी राजनीति से संन्यास की घोषणा करेंगे तो उनके उत्तराधिकारियों की फेहरिस्त में फडणवीस प्रमुख तीन लोगों में होंगे।

भाजपा को सबक सिखाने के चक्कर में उद्धव पवार के चक्रव्यूह में फंस गए। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठन किया। सीनियर ठाकरे की परंपरा से हटकर मुख्यमंत्री बने और बेटे को भी मंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे की शिवसेना सेक्युलर शिवसेना के रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगी। उद्धव ने शिवसेना को ऐसी सेक्युलर राजनीतिक दल बना दिया जो हिंदू विरोधी कार्य करती दिख रही थी। जो जिंदगी भर शिवसैनिक राग हिंदू आलापता था, वह समझ ही नहीं पाया कि उद्धव साहेब यह क्या कर रहे हैं। वे देख रहे थे कि हिंदूवादी शिवसेना सरकार हिंदुत्व के पैरोकारों की ही ऐसी की तैसी कर रही है। ढाई साल में शिवसेना हिंदू-विरोधी पार्टी बन गई। इससे शिवसेना विधायकों की हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें साफ दिखने लगा कि उद्धव की हिंदू विरोधी नीति से उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव का विरोध करने की पहल की तो दो तिहाई से ज्यादा विधायक उनके साथ हो लिए। अब तो भविष्य में उद्धव के साथ रहने वाले 10-12 विधायक और राज्यभर में शाखा प्रमुख के भी शिंदे खेमे में चले जाएं तो हैरानी नहीं होगी।

● **बिन्दु माथुर**

उद्धव ठाकरे को ना माया मिली ना राम

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में यही कहा जा सकता है कि पवार के झांसे में आकर सेक्युलर बनने का उनका फैसला ब्लंडर साबित हुआ और इस चक्कर में उन्होंने अपने पिता की विरासत को भी गंवा दिया। राजनीतिक हलकों में 22 जून से ही कहा जा रहा है कि वर्षा छोड़ते समय उद्धव मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिए होते तो थोड़ी सहानुभूति मिलने की गुंजाइश रहती। उद्धव को 10 जून 2022 को राज्यसभा चुनाव में एहसास हो गया था कि शिवसेना पर से उनकी पकड़ ढीली पड़ गई है और बगावत के दूसरे दिन यानी 22 जून से ही उद्धव को पता चल गया था कि बगावत करने वाले शिवसेना विधायक किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि उन्हें संदेह है कि सेक्युलर पॉलिटिक्स से वे दोबारा विधायक चुने जा सकेंगे।

गहलोत का जादू बरकरार

प्रदेश में राज्यसभा की चार सीटों के लिए हुए चुनाव में तीन पर जीत हासिल कर राजनीति के चाणक्य तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और अन्य दूसरे नेताओं की नजर में गहलोत का कद और बढ़ गया है। चुनावों को लेकर भले ही सियासत पैंतरे बदलती रही। लेकिन गहलोत को जीत को सहेजना था और साधना था, इसलिए उन्होंने हर चुनौती का सामना करते हुए सियासी शतरंज पर फतेह का परचम लहरा दिया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूरा भरोसा था कि चुनौतियों की कसौटी पर गहलोत ही खरे साबित हो सकते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि यह अशोक गहलोत के शानदार उदय की अद्भुत शुरुआत है। उन्होंने अपने आपको नई भूमिका में स्थापित कर लिया है और राजस्थान में एक सुनहरे युग का सूत्रपात करने की डगर पर दमदार सफर शुरू कर दिया है। गहलोत के मिजाज और सियासी सूझबूझ का फलसफा समझने की कोशिश करें, तो वे स्वभाव से विनम्र और अच्छे जनसंपर्क वाले राजनेता माने जाते हैं। उनकी सियासी सूझबूझ और गणित को समझना आसान नहीं है। फिलहाल तो बेचैनियां पायलट खेमे में ही दिखाई देती हैं। क्योंकि सियासत के बाजीगर गहलोत की सियासी दानिशमंदी पर पकड़ बेमिसाल है।

यही नहीं, जादूगर के नाम से विख्यात गहलोत ने विरोधियों को एक बार फिर अपना लोहा मनवा दिया। अब विरोधियों के मुंह स्वत: ही बंद हो गए। चुनाव से ठीक पहले तक भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने दावा किया था कि कांग्रेस खेमे से आठ विधायक उसके पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन गहलोत ने अपनी जादुई कला से सभी 13 निर्दलीयों, बीटीपी के दो सीपीआईएम के दो और आरएलडी का एक मत लेने के साथ ही उलटा भाजपा में क्रॉस वोटिंग तक करवा दी। गहलोत ने चुनावों से पहले कई बार दावे किए थे कि उनके पास 126 मत हैं, जो अंत तक रहेंगे। कांग्रेस के समर्थित सभी विधायक न तो बिके और न ही झुके। राज्यसभा के इस चुनाव की कमान खुद अशोक गहलोत के अपने हाथों में रखी थी। कुछ विधायकों में जो नाराजगी थी, उनको भी सुना और उसे दूर भी किया। उदयपुर में की गई बाड़ेबंदी में भी अपने साथियों के बीच रहे और एक-एक विधायक से कई बार संपर्क भी किया। यहां तक कि मतदान के दौरान भी खुद गहलोत एक एजेंट के रूप में बैठे और एक-एक मत पर नजर भी रखी। राज्यसभा में प्रदेश की सभी 10 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, लेकिन अब गहलोत चाणक्य नीति से तीन पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। इस चुनाव अभियान में गहलोत ने न केवल बीमार विधायकों के घर या अस्पताल में जाकर मुलाकात की, बल्कि रोजाना उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। जब गहलोत को पता लगा कि कांग्रेस के तीसरे प्रत्याशी प्रमोद कुमार तिवारी संकट में आ सकते हैं, तो उन्होंने अपने अनुभव और जादुई कला से भाजपा के वोटों में सेंध भी मारी और उसमें सफल भी हुए। भाजपा की विधायक शोभारानी का वोट कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद कुमार को जिताकर पिछले दो साल में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार हॉर्स ट्रेडिंग को मात दे दी। राजनीतिक हलकों में इसे गहलोत की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

प्रदेश में राज्यसभा में 10 सांसद थे, जिसमें सात भाजपा एवं तीन कांग्रेस से है। चार सांसद ओम माथुर, हर्षवर्धन सिंह, केजे अल्फांस एवं राजकुमार वर्मा का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो रहा था। खाली हो रही इन्हीं चार सीटों पर 10 जून को चुनाव हुए थे। कांग्रेस के तीन और भाजपा के एक सीट जीतने से भी राज्यसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या बढ़ गई। यानी राज्यसभा में कांग्रेस का पलड़ा फिर से थोड़ा भारी हो गया है।

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को और भाजपा ने घनश्याम तिवाड़ी को मैदान में उतारा था। इसके अलावा भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवार सुभाश चंद्रा को समर्थन दिया था। चंद्रा के चुनाव मैदान में आने से मुकाबला काफी रोचक हो गया था। इसे बाद कांग्रेस-भाजपा ने खरीद-फरोख्त के चलते क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों की बाड़ेबंदी में ले लिया था। इसके बावजूद भाजपा विधायक शोभारानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक परसराम मोरदिया का वोट खारिज हो गया। कांग्रेस ने माकपा, बीटीपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से तीनों सीटों पर बाजी मार ली।

मुख्यमंत्री के कंधे पर इस चुनाव की जिम्मेदारी थी। नाराजगी के चलते चुनाव की घोषणा के साथ ही उन्होंने विधायकों को साधना शुरू कर दिया था। कुछ विधायकों की अपने खिलाफ बयानबाजी के बावजूद एक जादूगर की तरह उन्होंने सभी को साथ ले लिया। कांग्रेस के पास मात्र 108 वोट थे। ऐसे में 15 वोटों की और जरूरत थी। गहलोत ने बहुमत से भी अधिक 18 वोट जुटा लिए। इस जीत के बाद अब वे प्रदेश में सरकार को और मजबूती के साथ चलाएंगे। भाजपा में चुनाव की कमान किसी एक नेता के हाथ में नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मिलकर संभाल रहे थे। ये तीनों नेता अपने खेमें से वोट क्रॉस होने से भी नहीं रोक सके। वहीं भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के लिए भी वोट नहीं जुटा सके।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

चंद्रा के दावे बेकार

राज्यसभा चुनाव हारे निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा ने वोटिंग से तीन दिन पहले यहां प्रेसवार्ता कर दावा किया था कि उनके पास भाजपा के तीस कांग्रेस के आठ और आरएलपी, अन्य दलों-निर्दलीयों के नौ विधायकों का समर्थन है, लेकिन चंद्रा के दावे फेल हो गए। भाजपा के पूरे 30 वोट तक उनको नहीं मिल पाए। कांग्रेस और अन्य दलों निर्दलियों के वोट तो दूर की कौड़ी साबित हुए। सिर्फ आरएलपी के तीन वोट चंद्रा को मिल सके। आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने तीनों विधायकों के वोट देने के बाद कहा कि उन्होंने अपना वादा निभा दिया है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि उनके पास 126 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस प्रत्याशियों को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। तीनों प्रत्याशियों को कुल 127 वोट मिले। हालांकि एक वोट खारिज हो गया। इस वजह से वोट का आंकड़ा वापस 126 पहुंच गया। वहीं भाजपा और भाजपा समर्थित प्रत्याशी को 74 वोट मिलने के दावे थे, लेकिन 73 वोट ही मिल सके।

भाजपा की जीत खतरे की घंटी है

आजमगढ़ और रामपुर में भाजपा ने अखिलेश यादव से 2019 के आम चुनाव का हिसाब बराबर कर लिया है और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनावों में मिली हार की कसक भी मिटा ली है। आजमगढ़ में भाजपा उम्मीदवार निरहुआ और रामपुर में घनश्याम सिंह लोधी ने अपनी-अपनी सीटें जीत ली हैं।

2018 में गोरखपुर और फूलपुर सीट पर योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव से ही शिकस्त मिली थी। तब बसपा के समर्थन से समाजवादी पार्टी ने दोनों ही लोकसभा सीटों पर भाजपा को हरा दिया था। हार का बदला तो भाजपा ने अगले आम चुनाव में ही ले लिया था, जब सपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले नेता ने पाला बदलकर भगवा चोला धारण कर लिया, लेकिन असल मायने में योगी आदित्यनाथ को अब जाकर सुकून महसूस हो रहा होगा और इस बात की खुशी भी महसूस हो रही होगी कि उप्र में भाजपा को चुनाव जीतने के लिए मायावती क्या मायने रखती हैं। लोकसभा की दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव से अखिलेश यादव को जितना बड़ा नुकसान हुआ है, उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतने ही फायदे में हैं। एक बात कॉमन कही जा सकती है, जैसे रामपुर की हार से सपा पर अखिलेश यादव की पकड़ मजबूत हो सकती है, दोनों उपचुनावों में जीत से योगी आदित्यनाथ का भाजपा के अंदर दबदबा और बढ़ेगा। ये भाजपा नेतृत्व के लिए चिंता की बात जरूर हो सकती है। खासकर उप्र चुनाव 2022 से पहले अरविंद शर्मा को कैबिनेट में शामिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ के तैयार न होने को लेकर लगातार चली चर्चाओं को देखें तो।

चुनाव प्रचार करने नहीं गए अखिलेश यादव ने तो एक तरीके से पहले ही अपनी जिम्मेदारी झाड़ ली थी। हो सकता है अखिलेश यादव का लॉजिक रहा हो कि बड़े नेता उपचुनावों में जाते कहा हैं? बेशक वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन वो दिल्ली छोड़कर लखनऊ में डेरा जमा चुके हैं। हो सकता है, आजम खान को रामपुर में सेट कर देने की तरह अखिलेश यादव की धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट देने के पीछे कोई खास रणनीति रही हो, लेकिन अब ये कहने का मौका तो मिल ही गया है कि परिवार में उनके अलावा अपने दम पर कोई अपना चुनाव भी नहीं जीत पा रहा है। लेकिन एक बात तो पक्की है, आजमगढ़ छोड़ने का उनको मलाल जरूर होगा। अगर छोड़ने का न हो तो जिस तरीके से छोड़ा उसे लेकर अफसोस तो हो ही सकता है। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवालों पर अखिलेश यादव ने कहा था कि आजमगढ़ के लोगों से पूछकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक ही उनके करहल से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई। क्या अखिलेश यादव ने चुपके से आजमगढ़ के लोगों से अनुमति ले ली थी, क्योंकि ऐसी कोई सार्वजनिक रायशुमारी सामने तो आई नहीं।

रामपुर लोकसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी भले ही समाजवादी पार्टी के मुस्लिम फेस आजम खान की रही, लेकिन हार और जीत का हिसाब-किताब तो अखिलेश यादव के ही खाते में ही लिखा जाएगा और आजमगढ़ तो पूरी तरह उनके हिस्से का ही मामला रहा। अखिलेश यादव को आजमगढ़ की शिकस्त से राहत रामपुर की हार से ही मिल रही होगी। जैसे आजमगढ़ में अखिलेश यादव के लिए चुनावी राजनीति में करारी हार दर्ज हुई है, रामपुर में हारकर भी अखिलेश यादव फायदे में लगते हैं। ये ठीक है कि आजमगढ़ की हार का ठीकरा अखिलेश यादव के सिर पर भी फूटता है, लेकिन रामपुर उपचुनाव के नतीजे किसी जीत से भी कम नहीं हैं। आजम खान के जेल में रहते तो अखिलेश यादव अपने मुस्लिम विधायकों के निशाने पर रहे ही, पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के बाहर आने के बाद भी काफी दबाव महसूस कर रहे थे। जेल से रिहाई के वक्त भी आजम खान की पत्नी की प्रतिक्रिया भी अखिलेश यादव के लिए परेशान करने वाली रही।

अखिलेश यादव पर धीरे-धीरे ये तोहमत लगने लगी थी कि वो उप्र में हिंदुत्व की राजनीति के दबाव में आ गए हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट और मुस्लिम विधायक पाने के बाद भी उनको आजम खान जैसे नेता तक की परवाह नहीं है। कपिल सिब्बल जैसे वकील की जरूरत तो किसी भी नेता को होगी, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस छोड़ने पर राज्यसभा के चुनाव में उनको सपोर्ट आजम खान की वजह से ही किया, ये तो साफ है और नाराज आजम खान से दिल्ली के अस्पताल में अरसा बाद मिलने गए तो मालूम हुआ कपिल सिब्बल ही माध्यम बने थे। अखिलेश ने आजम के खेल से निजात पा ली है। दिल्ली के अस्पताल में रामपुर के उम्मीदवार का नाम फाइनल भले न हुआ हो, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से आजम खान को अधिकृत तो कर ही दिया था। और जब आजम खान ने अपनी पत्नी तजीन फातिमा या टिकट के लिए तब चर्चा में रही **बड़ी बहू को टिकट** न देने का फैसला किया होगा, तो उसका आधार यही रहा होगा कि वो रामपुर में सपा की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थे, ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को राज्यसभा न भेजने के बावजूद आजमगढ़ से चुनाव लड़ा पाने की हिम्मत नहीं जुटा सके।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

मायावती फिर बनीं भाजपा की मददगार

आजमगढ़ उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ और धर्मेंद्र यादव की जीत-हार का फासला 10 हजार से भी कम है। निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हराया है। इस लिहाज से रामपुर के नतीजे देखें तो भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी ने 42 हजार वोटों के अंतर से सपा के असीम रजा को शिकस्त दी है यानी निरहुआ के मुकाबले चार गुना से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी निरहुआ को 34.39 फीसदी वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 33.44 फीसदी और ध्यान देने वाली बात ये है कि बसपा कैंडिडेट शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 29.27 फीसदी वोट हासिल हुए हैं। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को टिकट देने के पीछे मायावती की दमदार दलील ये भी हो सकती है कि बसपा ने न तो उम्मीदवार बदला, न कोई नया उम्मीदवार खड़ा किया, बल्कि बसपा ने 2014 के ही अपने प्रत्याशी को दोबारा मौका दिया। वोट हासिल करने के हिसाब से भी मायावती कह सकती हैं कि उनका कैंडिडेट मजबूती से चुनाव लड़ा है। लेकिन ऐसे तमाम दलीलों के बीच यह तथ्य है कि मायावती एक बार फिर भाजपा की मददगार बनीं।

सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने का सर्वदलीय निर्णय लिया है। इसके पूर्व फरवरी 2019 और 2020 में बिहार विधानसभा जातिगत जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर चुकी है। क्या बिहार के दल समझते हैं कि जनगणना से बेहतर सामाजिक न्याय मिलेगा? जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने से राजनीतिक दलों को यही तो पता चलेगा कि कौन सा जाति समूह कितने प्रतिशत है। चूंकि बिहार में राजद और जदयू की राजनीति अन्य पिछड़ा वर्ग पर आधारित है, इसीलिए भाजपा सहित सभी दल जातिगत जनगणना का श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन जनता को पता है कि जातीय जनगणना मात्र से उसे आरक्षण या सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि देश में अस्मिता की राजनीति अर्थात् जातीय राजनीति की जमीन खिसक रही है और लोग धीरे-धीरे समावेशी राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिसमें सभी का विकास निहित है।

जातिगत जनगणना की कवायद आसान नहीं। उसके आंकड़ों को एकत्र कर विश्लेषित करना भी एक चुनौती है। मनमोहन सरकार द्वारा 2011 में जो सामाजिक-आर्थिक-पारिवारिक जनगणना हुई, उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हो सके। अंतिम जातिगत जनगणना 1931 में हुई, जिसमें 4,147 जातियां चिन्हित की गई थीं, किंतु 2011 की जनगणना में 46 लाख से अधिक जातियों-उपजातियों को दर्ज किया गया। आखिर इतनी बढ़ोतरी कैसे संभव हुई?

देश में राष्ट्रीय स्तर पर जातियों का समरूप वर्गीकरण संभव नहीं है, क्योंकि कोई जाति एक राज्य में ओबीसी है, तो दूसरे राज्यों में सामान्य वर्ग में है। बिहार में बनिया/वैश्य ओबीसी, तो उप्र, मप्र, दिल्ली में सामान्य वर्ग में हैं। रेड्डी कर्नाटक में ओबीसी तो आंध्र में सामान्य वर्ग में हैं। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में जनगणना 2011 के जातिवार आंकड़े सार्वजनिक न करने के यही सब कारण बताए थे। जातिगत जनगणना कराना न तो व्यावहारिक है, न ही **प्रशासकीय रूप** से संभव है। यदि बिहार में जाति जनगणना हो भी गई, तो क्या उसके आंकड़े प्रकाशित हो पाएंगे? क्या उससे जनता को कोई लाभ मिलेगा? कुछ दल निहित स्वार्थों के लिए ही इसका प्रयोग करेंगे। यदि 'ओबीसी' की जनसंख्या बढ़ गई तो राजनीतिक दल संभवत: 'कर्नाटक मॉडल' के आधार पर कानून बनाने और आरक्षण 69 प्रतिशत करने की मांग करें या केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करें, जिसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में पड़े।

जातिगत जनगणना में नागरिक से केवल उसकी जाति या जाति-समूह पूछा जाएगा। उसे कोई दस्तावेज नहीं दिखाना पड़ेगा। बिहार में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिमों का जमावड़ा है। संभव है वे स्वयं को न केवल जातिगत जनगणना में शामिल करा लें, बल्कि कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया अदि जिलों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए स्वयं को ओबीसी में शामिल कराएं। अनेक मुस्लिम जातियां जैसे कसब, चिक, डफली, धोबी, धुनियां, नट, नालबंद, पमारिया, भतिआर, मेहतर, लालबेगी, अंसारी, जुलाहा, रंगरेज, कुंजरा, दर्जी आदि पहले से बिहार में ओबीसी शामिल हैं और आरक्षण का लाभ ले रही हैं।

चूंकि जातिगत जनगणना के आंकड़े विधिक दस्तावेज नहीं, इसलिए उसके द्वारा किसी को अपनी जाति या जाति-समूह प्रमाणित करने का कानूनी आधार नहीं मिलेगा। प्रख्यात समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवास के संस्कृतिकरण सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संरचना में नीचे के सोपान पर स्थित व्यक्ति ऊपर बढ़ने की अभिलाषा रखता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि नागरिक अपना पंथ बदल सकता है, मगर जाति नहीं। स्पष्ट है कि जातिगत जनगणना से नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, केवल ओबीसी पर जातिगत राजनीति करने वाले दलों को चुनावी लाभ मिल सकता है। ओबीसी कोई समरूप सामाजिक वर्ग नहीं है। उसमें तीन उपवर्ग हैं, जिनमें पिछड़े (यादव/अहीर), मध्यम-पिछड़े (कुर्मी, लोध) और सर्वाधिक पिछड़े (कुशवाहा, कहार, शाक्य, निषाद, पाल, गड़रिया आदि) हैं। क्या कभी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे दलों ने इन सभी के लिए सामाजिक न्याय की बात की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि ने तो उनके लिए अलग-अलग कोटा बनाया है, लेकिन जब उप्र में भाजपा सरकार ने हुकुम सिंह समिति की 2001 में आई रिपोर्ट के आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण इन उपवर्गों में जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया तो इन्हीं दलों ने विरोध किया और उसे लागू नहीं होने दिया। उस समय वे सामाजिक न्याय भूल गए। काका कालेलकर और मंडल आयोग, दोनों में उप-वर्गीकरण की बात उठी थी। वर्तमान में रोहिणी आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी का उप-वर्गीकरण और आरक्षण का समानुपातिक विभाजन विचाराधीन है। देखना है कि सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले दल इसे स्वीकार करते हैं या नहीं?

● **विनोद बक्सरी**

भाजपा से कड़ी चुनौती

पिछड़ों की राजनीति करने वाले दलों को अब भाजपा से कड़ी चुनौती मिल रही है। भाजपा ने न केवल जुलाई 2015 में ओबीसी-मोर्चा गठित किया, वरन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर नीट परीक्षा में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी को 40 प्रतिशत स्थान देकर और उप्र जैसे बड़े राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ओबीसी को 40 प्रतिशत टिकट देकर सामाजिक न्याय की अवधारणा को एक नया आयाम दिया। यही कारण है कि विपक्षी दलों के संयुक्त प्रयास के बावजूद भाजपा का जनाधार बढ़ता जा रहा है। जनता अब समझ रही है कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण ही एकमात्र मार्ग नहीं है। आरक्षण एक जाति समूह को लाभ दे रहा है, पर उसी जाति समूह के अनेक सीमांत उपवर्ग उससे वंचित हैं। आरक्षण इतने विशाल समाज को लाभ नहीं दे सकता, क्योंकि आज के तकनीकी युग में नौकरियों की संख्या में कमी हो रही है। जातिगत जनगणना पिछड़े, दलित, सीमांत वर्ग को चिन्हित अवश्य करेगी, पर यह कहना कठिन है कि इससे इनमें से कितनों को सामाजिक न्याय या आरक्षण मिल पाएगा? सामाजिक न्याय के लिए हमें आरक्षण से आगे सोचना होगा। समावेशी राजनीति से ही हम एक समावेशी अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज की ओर बढ़ सकेंगे, जो इस वृहद समाज में संविधान के सामाजिक न्याय के संकल्प को चरितार्थ कर सकेगा।

अफगानिस्तान में सांस्कृतिक संहार

अफगानिस्तान का हिंदू-सिख विहीन होना अब अंतिम चरण में है। बीते दिनों राजधानी काबुल में एक गुरुद्वारे पर हमला इसी मकसद से किया गया। इस हमले के बाद भारत सरकार ने 111 हिंदुओं-सिखों को आपातकालीन ई-वीजा जारी किए। उनके भारत लौटने पर अफगानिस्तान में हिंदू-सिख-बौद्ध का नाम लेने वाला शायद ही कोई बचे। किसी समय विश्व का यह भू-भाग हिंदू-बौद्ध परंपरा का एक प्रमुख केंद्र था। यह विनाशकारी परिवर्तन लगभग एक हजार वर्ष में अपनी तार्किक परिणति पर पहुंचा है। क्या इस सांस्कृतिक संहार पर खुलकर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जिस दर्शन के कारण अफगानिस्तान में यह सब हुआ, क्या उसके रक्तबीज भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद नहीं? क्या अफगानिस्तान के वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश और खंडित भारत में गैर-इस्लामी अनुयायियों के भविष्य को देखना गलत होगा?

तालिबान शासित अफगानिस्तान में करते परवान गुरुद्वारा ही शेष बचा है। इस गुरुद्वारे पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएस खुरासान ने ली है। बकौल मीडिया उसने भाजपा से बाहर किए गए नेताओं की पैगंबर साहब पर टिप्पणी के विरोध में हमले को अंजाम दिया। क्या वाकई ऐसा है? वर्ष 2020 में इसी जिहादी संगठन ने काबुल के एक अन्य गुरुद्वारे पर हमला कर 25 निरपराध लोगों, जिनमें अधिकांश सिख थे, को मौत के घाट उतार दिया था। लगभग आठ माह पहले तालिबान के एक गुट ने गैर-मुस्लिमों विशेषकर हिंदू-सिखों से इस्लाम अपनाने या अफगानिस्तान छोड़ने में से कोई एक विकल्प चुनने को कहा था। यही नहीं, चाहे हामिद करजई का शासन हो या फिर अशरफ गनी की सरकार, उस दौरान भी हिंदुओं-सिखों को निशाना बनाकर कई हमले हुए। पिछली सदी के आठवें दशक में अफगानिस्तान में हिंदुओं-सिखों की संख्या लगभग सात लाख थी। गृहयुद्ध, मजहबी शासन और तालिबानी जिहाद के बाद आज उनकी संख्या अंगुलियों पर गिनने लायक ही बची है। यदि हालिया हमला पैगंबर साहब के अपमान का बदला लेने के लिए किया गया तो अतीत में आतंकी हिंदुओं-सिखों को किस अपराध की सजा देते रहे?

हिंदू-सिखों ने जो कुछ अफगानिस्तान में झेला, ठीक वैसा ही अनुभव उन्होंने अन्य गैर-मुस्लिमों के साथ इस्लामी पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी किया है। इन सभी देशों में गैर-मुस्लिमों की संख्या में भारी कमी आई है। इसका कारण उस कालक्रम में छिपा है, जिसमें उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए विवश होना पड़ा या फिर मजहबी उत्पीड़न से बचने के लिए भारत सहित अन्य देशों में पलायन करना पड़ा। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कश्मीर में आज भी हिंदुओं को इसी नियति से गुजरना पड़ रहा है। यह ठीक है कि शेष भारत में इस्लाम के नाम पर इन मध्यकालीन गतिविधियों का खुलेआम संचालन संभव नहीं, लेकिन कई तरीकों से ऐसे कुप्रयास आज भी जारी हैं। गत वर्ष ही उप्र पुलिस ने एक बड़े इस्लामी मतांतरण गिरोह का भंडाफोड़ किया था। चिंताजनक बात यह है कि ऐसे क्रियाकलापों को हिंदू विरोधी विचाराधाराओं से प्रत्यक्ष-परोक्ष सहानुभूति मिलती रहती है।

काबुल में गुरुद्वारे पर हमले को लेकर समाचार माध्यमों ने यह तो बताया कि अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की संख्या निरंतर घट रही है, किंतु इसके लिए जिम्मेदार वैचारिकी पर चर्चा का साहस नहीं दिखाया गया। आज जैसा अफगानिस्तान दिखता है, वह सदियों पहले ऐसा नहीं था। यहां तक कि तब अफगानिस्तान नाम का कोई देश भी नहीं था। पुरातात्विक उत्खनन से स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान अफगानिस्तान भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अंग रहा है। 12वीं शताब्दी तक वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर मुख्य रूप से हिंदू-बौद्ध और शैव मत के प्रमुख केंद्र थे। वैदिककाल में अफगानिस्तान भारत के पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक गांधार था, जिसका वर्णन महाभारत, ऋग्वेद आदि ग्रंथों में मिलता है। यह मौर्यकाल और कुषाण साम्राज्य का भी हिस्सा रहा, जहां बौद्ध मत फला-फूला। चौथी शताब्दी में कुषाण शासन के बाद छठी शताब्दी के प्रारंभ में हिंदू-बौद्ध बहुल काबुलशाही वंश का शासन आया, जो नौवीं शताब्दी के आरंभ तक रहा। इसके बाद हिंदूशाही वंश की स्थापना राजा लगर्तूमान के मंत्री कल्लर ने की, जिसके शासकों का कालांतर में महमूद गजनवी से सामना हुआ। मात्र 17 वर्ष की आयु में खलीफा बने गजनवी ने प्रतिवर्ष भारत के विरुद्ध जिहाद छेड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। 32 वर्ष के शासनकाल में उसने एक दर्जन से अधिक बार भारत पर हमले किए। उसने काफिर-कुफ्र की अवधारणा से प्रेरणा लेकर तलवार के बल पर हिंदुओं-बौद्धों को इस्लाम अपनाने के लिए विवश किया। जब हिंदूशाही शासक गजनवी के हाथों पराजित हुए, तब क्षेत्र का मजहबी स्वरूप और चरित्र बदलना प्रारंभ हुआ। मार्च 2001 में तालिबान ने गजनवी वाली मानसिकता से प्रेरित होकर बामियान में भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमाओं को ध्वस्त किया।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

तालिबान और आईएस खुरासान के बीच प्रभुत्व की लड़ाई

काबुल में गुरुद्वारे पर आतंकी हमले के सिलसिले में यह भी सामने आया कि तालिबान ने जहां जवाबी कार्रवाई करते हुए आईएस खुरासान के जिहादियों को मारने का दावा किया, वहीं तालिबानी गृहमंत्री और घोषित आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी ने सिखों से मुलाकात की। अभी अफगानिस्तान में तालिबान और आईएस खुरासान के बीच प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है। ये दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं, जिनका जन्म एक ही विषाक्त गर्भनाल से हुआ है। वे परस्पर सहयोग भी करते हैं और एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं। दोनों गजनवी वाली मानसिकता को अंगीकार किए हुए हैं। दोनों में बस एक रणनीतिक अंतर है। आईएस के लिए मुसलमानों में राष्ट्रीयता, नस्लीय और भौगोलिक पहचान का कोई अर्थ नहीं, जबकि तालिबान अफगान पहचान से जुड़ा है। तालिबान जहां अफगानिस्तान तक सीमित रहना चाहता है, वहीं आईएस स्वयं को वैश्विक बनाने के लिए तत्पर है।

चीन के खिलाफ बनानी होगी नई रणनीति

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए पिछले दस साल से चल रही वार्ता हास्यास्पद स्थिति में पहुंच गई है। ऐसा उदाहरण दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। रिश्ते सुलझने के बजाय वार्ताओं के दौर के साथ और ज्यादा ही उलझते गए। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए स्थापित व्यवस्था (डब्ल्यूएमसीसी) के तहत पिछली बैठक भी बेनतीजा रही। जनवरी 2012 से शुरू हुए वार्ता के इस सिलसिले में यह 24वीं कड़ी थी। पिछले हर दौर की तरह इस बार भी वार्ता इसी सहमति के साथ समाप्त हुई कि इस वार्ता के सिलसिले को जारी रखा जाए। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच भी 25 दौर की वार्ता हो चुकी है और वे भी बेनतीजा ही रहीं।

चीन की दलील है कि चूंकि सीमा विवाद बहुत पेचीदा है तो उसे किनारे रखकर दोनों देशों को आर्थिक, व्यापारिक और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिए। वहीं भारत सरकार का कहना है कि भारत की जमीन पर कब्जा करके चीन ने खुद ही सीमा विवाद को पेचीदा बनाया है। एक ओर वह बातचीत का दिखावा कहता है तो दूसरी ओर कब्जाई भूमि की किलेबंदी करके आगे की भूमि पर दावा करता रहता है। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल में चीनी सेना की नई आक्रामकता इसी रणनीति का हिस्सा है। यही कारण है कि भारत इस पर अड़ा है कि जब तक चीन मई 2020 की यथास्थिति पर नहीं लौटता तब तक उसके साथ किसी और विषय पर कोई बात नहीं होगी।

चीन के साथ दस साल के वार्ताक्रम में भारत को समझ आने लगा है कि इसकी आड़ में चीन उसे उलझाकर न केवल सीमाओं पर भारत के खिलाफ अपनी सैनिक किलेबंदी मजबूत करने में लगा रहा, बल्कि भारत के पड़ोस में सेंध लगाकर उसकी घेराबंदी में भी जुटा हुआ है। इसके सहारे चीन भारत को हाशिये पर धकेल देना चाहता है, ताकि वह उसके विश्व शक्ति बनने के अभियान में बाधा न उत्पन्न कर सके। इसी दौरान चीन ने पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और जिबूती जैसे कई देशों में ऐसी सामरिक-आर्थिक बिसात बिछाई है कि भारत के लिए उसकी काट बड़ी चुनौती बन गई है।

यदि भारत की उत्तरी सीमा की बात करें तो 1951 में तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन वहां एक लाख किमी लंबी सड़कें, हवाई अड्डे और सैनिक ठिकाने बना चुका है। उसने तिब्बत की सीमा पर 600 से ज्यादा आधुनिक गांव बसाकर अपनी पैठ मजबूत की है। जबकि भारत की अग्रिम रक्षा पंक्ति माने जाने वाले अधिकांश सीमावर्ती गांव तो सड़क-रोजगार के अभाव में लगभग उजड़ चुके हैं। मई 2020 में गलवन और लद्दाख के कई क्षेत्रों पर चीनी हमले का उद्देश्य यही था कि भारत का सीमावर्ती इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होने से पहले ही दौलतबेग ओल्डी और सियाचिन पर कब्जा कर लिया जाए।

हालांकि, दारबुक-श्योक-दौलतबेग ओल्डी सड़क बन जाने से गलवन में भारतीय सैनिकों को समय रहते नई कुमुक मिल गई और यह इलाका चीन के हाथ जाने से बच गया। उसी तनाव के दौरान भारतीय सैनिकों ने लद्दाख की कैलास हाइट्स पर रातों-रात नए मोर्चे लगाकर सैनिक समीकरणों को भारत के पक्ष में कर दिया। यही कारण है कि गलवन में अपनी योजना के विफल होने के बाद पिछले दो साल में चीन ने डब्ल्यूएमसीसी वार्ताओं के लिए अपनी उत्सुकता तो बढ़ाई है, लेकिन इसकी आड़ में वह उन कमजोरियों को दुरुस्त करने में जुटा है, जिनके चलते गलवन में उसका अभियान विफल हो गया था। अब उस इलाके में चीन ने आधुनिक उपकरणों से लैस नई चौकियां बनाकर, नए हवाई अड्डे बनाकर और मिसाइलें लगाकर इस कमजोरी की पूर्ति का प्रयास किया है। दुर्भाग्य से इन वार्ताओं के दौरान भारत ने चीन से कोई रियायत लिए बिना ही कैलास हाइट्स पर मिली बढ़त रूपी तुरुप के इक्के को गंवा दिया। चीन ने पैंगोंग झील के बीचोबीच दो नए पुल बनाकर स्थानीय रक्षा समीकरणों को फिर से पलट दिया है। अब भारतीय सेना के लिए झील की आठ में से शेष चार 'फिंगर्स' को बचाना भी एक चुनौती बन चुका है। यह मात्र दुर्योग नहीं कि एक ओर शांति बहाली के नाम पर चीन ने भारत से वार्ता की पहल की तो दूसरी ओर उसे घेरने के लिए बेल्ट एंड रोड जैसा दांव चला। इसकी शुरुआत 2013 में पाकिस्तान के साथ सीपैक संधि के रूप में हुई। उसके अंतर्गत चीन गुलाम कश्मीर के रास्ते अरब सागर तक सड़क बनाने और अपने नौसैनिक एवं व्यापारिक इस्तेमाल के लिए ग्वादर बंदरगाह बना रहा है। इसी तरह चीन ने 2014 में श्रीलंका के हंबनटोटा में, 2016 में मालदीव के फेंधू-फिनोलू द्वीप में, 2016-17 में जिबूती में और उससे पहले बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के कोको द्वीप में जो नौसैनिक सुविधाएं हासिल कीं, उनके बूते वह भारत की सामुद्रिक घेराबंदी करने की ओर बढ़ रहा है।

● **कुमार विनोद**

क्वाड से भारत को बहुत आशाएं

दुर्भाग्य से अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी स्थितियां अभी भारत के बहुत अनुकूल नहीं हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले ने जहां अमेरिका एवं यूरोपीय देशों को उलझा दिया है, वहीं चीन की गोद में जा चुके रूस से भी अब भारत कोई बड़ी उम्मीद नहीं रख सकता। कहने को तो अमेरिकी पहल पर फिर से सक्रिय किए गए क्वाड से भारत को बहुत आशाएं हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया, तिब्बत और वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे दोस्तों को उनके नाजुक दौर में दगा देकर खिसक जाने वाले और उन्हें दुश्मन के रहम पर छोड़ जाने वाले अमेरिका का पिछला इतिहास यह भरोसा नहीं देता कि चीन के साथ युद्ध की हालत में वह सचमुच भारत के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे में भारत को दो मोर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। एक तो यह कि चीन के साथ टकराव को डब्ल्यूएमसीसी जैसी वार्ता के माध्यम से टाले रखकर भारत अपने ही बूते पर अपनी रक्षा पंक्ति को चीन का जवाब देने योग्य बना ले। दूसरा कदम यह हो कि अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय भारत को जापान, ताइवान, आस्ट्रेलिया, वियतनाम, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया के उन सभी देशों के साथ एक ऐसा आर्थिक एवं सामरिक संगठन बनाना चाहिए, जो चीन की दादागीरी के सताए हुए हैं और उन्हें भी चीन से टकराव की स्थिति में भरोसेमंद दोस्तों की सख्त जरूरत है।

पिंक स्क्वाड्स तक ही सीमित न रखें

जहां भी महिला पुलिस अच्छा प्रदर्शन करती है, सुर्खियां बड़ी आसानी से हासिल हो जाती हैं। हालांकि वर्दी वाली महिलाओं के प्रति यह आकर्षण, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, कुछ बताने के बदले छुपाता ज्यादा है। हाल के वर्षों में प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में महिलाओं की हिस्सेदारी ठहरी हुई रही है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) के आंकड़ों से पता चलता है कि यह संख्या कुल पुलिस बल में महज 12 फीसदी है। हालांकि पुलिस नेतृत्व में बढ़ती महिलाओं की हिस्सेदारी से पुलिस बल में महिलाओं की पेशेवर भूमिका पर बहस आगे नहीं बढ़ सकी। क्या महिला कांस्टेबल के पास वही अधिकार और जिम्मेदारियां हैं, जो उनके पुरुष साथियों के पास है? पुलिस थाने का दायरा 'बीट' में बंटा होता है, और बीट कांस्टेबल किसी तय इलाके में अपराध की पड़ताल, शिकायतों की जांच, कानून-व्यवस्था के हालात पर काबू पाना, सामुदायिक सुरक्षा और पुलिस-जनता के बीच संबंधों का पुल बनने के लिए नियुक्त होता है। ये पुलिस व्यवस्था की जरूरी 'एक्जिक्यूटिव' ड्यूटी और खास पहलू होता है।

पुलिस थाने में अमूमन महिला कांस्टेबल को जनरल ड्यूटी या डेस्क ड्यूटी दी जाती है। मेरी 10 साल की सर्विस में मुझे एक भी महिला कांस्टेबल बीट की ड्यूटी नहीं मिली। यह गौर करना दिलचस्प है कि पुलिस बल में महिलाओं को शामिल करने का विचार इस तथ्य से आया कि वे महिलाओं को छू सकती हैं, गिरफ्तार कर सकती हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकती है और समाज में महिलाओं से बात कर सकती हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि महिला कांस्टेबल संगठन के हाशिए पर रहती हैं, नाम मात्र की भूमिकाओं में दिखती हैं। पुलिस में महिलाओं को महज 'पिंक स्क्वाड्स' और 'एंटी-रोमियो स्क्वाड्स' के अलावा दूसरी जिम्मेदारियों के लिए भी विचार करने की दरकार है।

कड़क वर्दी में मलिाओं के होने भर से कार्यस्थल या घर में उन्हें बराबरी का व्यवहार हासिल नहीं हो जाता। निजी जिंदगी स्त्री-पुरुष के बीच श्रम विभाजन में जैसे महिलाएं मुख्य रूप से तीमारदारी की भूमिकाओं में रहती हैं, सार्वजनिक स्थितियों में भी उसकी वही हिस्सेदारी होती है। महिला कांस्टेबल को घर की जिम्मेदारियों को भी उसी तरह निभाना पड़ता है, जिससे उसके कार्यस्थल में आम ड्यूटी में खलल पड़ती है।

घर और कार्यस्थल में जरूरी मददगार व्यवस्थाओं के बगैर, बच्चे पालने और स्तनपान कराने की अनोखी शारीरिक स्थिति का मतलब है कि महिला कांस्टेबल की निजी जिंदगी में प्रगति से वह पेशेवर जिंदगी में पीछे छूट जाती है। इस वजह से वे खास तरह की ड्यूटी पसंद कर सकती हैं, जिससे घर में काम के असंतुलित बंटवारे को संभाला जा सके। महिला कांस्टेबल के जीवंत अनुभव और काम के प्रति उनकी धारणा को किसी सरल-सी व्याख्या में परिभाषित नहीं किया जा सकता। महिला कांस्टेबल की पेशेवर भूमिका और स्त्री के प्रति धारणाएं बड़ी उलझन पैदा करती हैं। हालांकि, पुलिस बल में महिलाओं की दिखने वाली, मजबूत और अनिवार्य भूमिका अब अकाट्य है। अब वक्त आ गया है कि उसमें नई ताजगी लाई जाए। औरंगाबाद (ग्रामीण) की सुपरिंटेंडेंट के नाते मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि हमारे कहने पर 37 महिला कांस्टेबल 'बीट इन-चार्ज या बीट अमलदार' के लिए आगे आ गईं, जबकि मैंने बस कुछेक की उम्मीद ही की थी।

पुरुष और महिला कांस्टेबलों में एक्जिक्यूटिव ड्यूटी के समान बंटवारे से फौरन पुलिस बल की कारगरता बढ़ गई और लोगों का भरोसा बढ़ा, जिससे पुलिस और लोगों के बीच संबंध आसान हुए। यह सीखने वाला अनुभव था कि पुरुष और महिला कांस्टेबल आपस में मुझसे अपनी पेशेवर समस्याओं पर विचार-विमर्श करते थे। यह सुनना सुखद था कि एक नवनियुक्त महिला कांस्टेबल ने अपने इलाके में एक पुरुष शव के मिलने पंचनामा लिखने में दिक्कत महसूस की तो उसके एक पुरुष साथी ने उसकी मदद की। उनका सुपरिंटेंडेंट होने के नाते मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता था।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

आगे की राह

अब वक्त आ गया है कि महिला कांस्टेबलों के लिए काम का सहज माहौल तैयार करने के लिए एक नया जज्बा भरा जाए। सक्रिय भूमिकाओं से पुलिस की बतौर संगठन कई कामकाजी चुनौतियां आसान रहेंगी और उसकी कारगरता बढ़ेगी। पुलिस नेतृत्व के लिए कामकाजी बढ़त इसे क्षेत्रीय स्तर पर अमल में लाने की अच्छी दलील हो सकती है। औरंगाबाद में महिला 'बीट अमलदार' की भूमिका क्षेत्रीय नेतृत्व के सहयोग और संकल्प से संभव हुई। देश में लोगों को बेहतर पुलिस व्यवस्था मुहैया कराने के लिए ऐसे प्रमुख संगठनात्मक बदलाव जरूरी हैं। फिर, फील्ड ड्यूटी के लिए आवास, टॉयलेट, बाल गृह, लंबे दौरों और देर तक शारीरिक मेहनत के मुद्दे भी अहम हैं। इसके बावजूद पुलिस बल में मर्दों और औरतों ने बड़ी चुनौतियों के दौर में समाज की सेवा की है। अब वक्त आ गया है कि महिला कांस्टेबल को सक्रिय भूमिकाएं दी जाएं और सभी मामलों की पड़ताल तथा उनके बीट की आधिकारिक ड्यूटियां दी जाएं। यह कहा जा सकता है कि स्त्री की आम भूमिकाओं पर गहराई से गौर किए बगैर सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं को शुमार करना 'अव्यावहारिक' होगा। हालांकि 'व्यावहारिकता' के मुद्दों की चिंता से थोड़ी-सी समस्याएं ही सुलझ पाई हैं। आदर्श तय करना और उस दिशा में लगन से बढ़ना ही धीरे ही सही राह दिखाता है, चाहे घर हो या कार्यस्थल।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

तृप्ति

अनुराधा ने देखा क्लास रूम में भोले-भाले बच्चे सहमे-सहमे बैठे हैं। साफ-सुथरा यूनिफार्म पहने। उसके आते ही सबने खड़े होकर अभिवादन किया। जब बैठने के लिए कहा गया, चुपचाप बैठ गए। अनुशासित, बड़ों-सा सधा हुआ व्यवहार। न कोई ऊर्जा, न उल्लास। जैसे जबरदस्ती दिलो-दिमाग पर किसी ने बोझा लाद दिया हो। अनुराधा मन ही मन सोच रही थी, बच्चे खिलखिलाते अच्छे लगते हैं। यह तनाव, यह शांति कैसी? अनुराधा का व्यक्तित्व सादगीपूर्ण, हसमुख, प्रसन्नचित्त था। हंसते हुए उसने अपने विद्यार्थियों से दोस्ती का निश्चल रिश्ता बनाया। महकती मुस्कान और मासूम चहक से आह्लादित हुआ वातावरण। बच्चे खुलकर बातें करने लगे। नटखट पवन हिलोरे लेने लगी। कथा, कहानियां, कविताएं, इतिहास, भूगोल खेलते-खेलते अंकों से भी प्यार हो गया। पढ़ना-लिखना अब मजेदार हो गया और अनुराधा को ज्ञान-दान करते मिल रही थी संतुष्टि और तृप्ति।

- चंचल जैन

आत्ममुग्धा

नीलम अभी अभी अपनी ननद अभिलाषा के घर आई, आते ही अपनी तारीफों के पुल बांधने लगी। नीलम से जब भी कोई बात करो घुमा फिरा कर खुद पर ले आती है हमेशा खुद की तारीफ करती रहती है उसके मुंह से कभी भी किसी की तारीफ नहीं सुनी, वो चलता-फिरता कम्प्लेन बॉक्स है। नीलम के पति एक सरकारी अधिकारी हैं और उसके दो बच्चे हैं दोनों इंजीनियर हैं। उसे इस बात का बड़ा गुमान है हर किसी से कहती रहती है कि उसकी बदौलत ही उसके पति और बच्चे कामयाब हैं। एक दिन राहुल को कह रही थी 'अगर रमेश की जिंदगी में मैं नहीं आती तो इनका कुछ बनना ही नहीं था मेरे ही कारण रमेश का प्रमोशन हुआ और मैंने अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया।' राहुल तो बस उसका मुंह ही देखता रह गया।

नीलम का रंग कुछ सांवला है मगर नैन-नक्श अच्छे हैं। उसे अपने लुक पर बड़ा घमंड है, सारा दिन आईने के सामने खुद को निहारना और सजना-संवरना दिनभर सोसायटी में घुमाना और गॉसिप करना। घर के कामों में उसका जी ही नहीं लगता। पति और बच्चे ज्यादातर बाहर ही खाना खाते क्योंकि घर में खाना बना ही नहीं होता था। दिनभर तितली बनी फिरती थी। सोसायटी के मनचले आशिक उसके इर्दगिर्द घूमते रहते और उसकी तारीफें करते। उनकी तारीफें सुन-सुनकर वो खुद पर मुग्ध रहती। दिनभर में कई बार अपनी प्रोफाइल चेंज करती सेल्फी खींचना तो मानो उसका शौक हो। अभिलाषा को आश्चर्य होता है कि कोई भी इतना खुद पसंद कैसे हो सकता है।

- विभा कुमारी 'नीरजा'

घास में कीड़े

हरी घास में कीड़े पनपे,
हर पल्लव छलनी होता।
सुमन खिलें शाखा पर कैसे,
सूखा है सुगंध-सोता।।

पादप की सूखी शाखा पर,
सुमन नहीं, फल क्यों आएं?
जैसे बोए बीज बाग में,
वे बबूल बस चुभ पाएं।।
घुड़शाला में गधे पले हैं,
खड़ा-खड़ा हाथी रोता।।
हरी घास में कीड़े पनपे,
हर पल्लव छलनी होता।।

घुट्टी में घिस जहर पिलाया,
जहर सपोले उगलेंगे।
आस्तीन के सांप दोमुंहे,
आजीवन क्या सुधरेंगे??
वही काटता फसल आदमी,
जो अतीत में वह बोता।
हरी घास में कीड़े पनपे,
हर पल्लव छलनी होता।।

दूध पिला कर पाल रहे हो,
दोष किसे अब देते हो?
मिल जाए ऊंचा सत्तासन,
मत भी तो तुम लेते हो!!
खंड-खंड हो जाए भारत,
भावी भले रहे रोता।
हरी घास में कीड़े पनपे,
हर पल्लव छलनी होता।।

श्रम के बिना पेट जब भरता,
कौन काम करने जाए?
पैरों की जूती पैरों से,
निकल शीश पर जा धाए!!
अपनी करनी का फल देखो,
हाथों से उड़ता तोता।।
हरी घास में कीड़े पनपे,
हर पल्लव छलनी होता।।

डेंगू, मसक चूसते लोहू,
नाली में है घर जिनका।
मेवा मिसरी चाभ रहे हैं,
आश्रय थल जिनका तिनका।
'शुभम' योजना बदलें अपनी,
लगा रही जनता गोता।
हरी घास में कीड़े पनपे,
हर पल्लव छलनी होता।।

- डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'

मप्र ने रचा इतिहास

मप्र ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को फाइनल में 6 विकेट से हराकर इतिहास रचते पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। मप्र ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर अंतिम दिन 108 रन के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यह मप्र क्रिकेट इतिहास का स्वर्णिम दिन है, जिसने पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। आदित्य श्रीवास्तव के नेतृत्व वाली मप्र की टीम की सफलता का श्रेय कोच चंद्रकांत पंडित को दिया जा रहा है।

मप्र के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। बता दें कि मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2022 फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। मुंबई की पहली पारी 374 रन पर ऑलआउट हुई थी। इसके जवाब में मप्र ने पहली पारी में 536 रन बनाए और पहली पारी के आधार पर 162 रन की बढ़त हासिल की। चौथे दिन मुंबई ने तेजी से खेलकर आउटराइट जीत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दूसरी पारी 269 रन पर सिमट गई। इस तरह मप्र को जीत के लिए 108 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 29.5 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। बता दें कि 23 साल पहले यानी 1998-99 में मप्र की टीम रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंची थी। तब टीम के कप्तान चंद्रकांत पंडित ही थे। मगर तब मप्र को कर्नाटक के **हाथों शिकस्त झेलनी** पड़ी थी। मप्र ने 69 साल पहले अपने पुराने अवतार होल्कर के रूप में आखिरी बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था। अब मप्र के रणजी ट्रॉफी खिताब का सूखा समाप्त हुआ और पहली बार वह चैंपियन बनी। मप्र रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने वाली 20वीं टीम बनी। अब तक केवल 8 टीमों ने एक बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। वहीं 12 अन्य टीमों ने कई बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीते हैं।

छोटे शहरों में फैल रहा क्रिकेट

वर्ष 2010 के बाद से रणजी ट्रॉफी में कुछ सत्र कर्नाटक का दबदबा रहा, लेकिन इसके बाद सिर्फ मुंबई ही एक खिताब जीत पाई जबकि अधिकांश खिताब राजस्थान (दो), विदर्भ (दो), सौराष्ट्र (एक) और मप्र (एक) जैसी टीम ने जीते जिन्हें घरेलू क्रिकेट में कमजोर माना जाता था। यह दर्शाता है कि मुंबई के शिवाजी पार्क, आजाद मैदान या क्रॉस मैदान, दिल्ली और बेंगलुरु या कोलकाता से क्रिकेट अब छोटे शहरों में भी फैल रहा है। रणजी ट्रॉफी जब शुरू हुई तो मप्र की टीम बनी भी नहीं थी और तब ब्रिटिश युग के राज्य होलकर ने देश के कई दिग्गज क्रिकेटर दिए जिसमें करिश्माई मुश्ताक अली और भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान सीके नायुडू भी शामिल रहे। होलकर 1950 के दशक तक मजबूत टीम थी जिसे बाद में मध्य भारत और फिर मप्र नाम दिया गया। मप्र ने इसके बाद कई अच्छे क्रिकेटर तैयार किए, जिसमें स्पिनर नरेंद्र हिरवानी और राजेश चौहान भी शामिल रहे, जिनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोटा लेकिन प्रभावी रहा। अमय खुरसिया ने भी काफी सफलता हासिल की। मध्यक्रम के बल्लेबाज देवेंद्र बुंदेला दुर्भाग्यशाली रहे क्योंकि वह 1990 और 2000 के दशक में उस समय खेले जब मध्य क्रम में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज खेल रहे थे।

5वें दिन चायकाल से पहले मप्र ने जीत पर मुहर लगाई जब रजत पाटीदार ने सरफराज खान की गेंद पर एक रन लिया। बता दें कि मुंबई ने आखिरी दिन अपनी पारी 113/2 के स्कोर से आगे बढ़ाई। अरमान जाफर अपने कल के स्कोर में 5 रन जोड़कर गौरव यादव की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। सुवेद पारकर (51) ने अपना अर्धशतक पूरा किया और सरफराज खान (45) के साथ चौथे विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी की। कार्तिकेय ने पारकर को क्लीन बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद मुंबई को जल्दी-जल्दी झटके लगे। यशस्वी जायसवाल को कार्तिकेय ने मंत्री के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई को पांचवां झटका दिया। शम्स मुलानी (17) को सारांश जैन ने रनआउट किया। पार्थ सहानी ने सरफराज को अर्धशतक जमाने से रोका और अग्रवाल के हाथों कैच आउट कराया। मप्र की तरफ से कुमार कार्तिकेय ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए। गौरव यादव और पार्थ साहनी को दो-दो विकेट मिले।

मप्र को जीत के लिए 108 रन बनाने थे और उसके पास 50 से ज्यादा ओवर थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मप्र की शुरुआत धवल कुलकर्णी ने बिगाड़ी। कुलकर्णी ने दूसरे ओवर में पहली पारी के शतकवीर यश दुबे (1) को क्लीन बोल्ड कर दिया। फिर हिमांशु मंत्री (37) और शुभम शर्मा (30) ने दूसरे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की। शम्स मुलानी ने मंत्री को बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ा। पार्थ साहनी (5) को मुलानी ने कोटियन के हाथों कैच आउट कराकर अपना दूसरा शिकार किया। शुभम शर्मा ने फिर रजत पाटीदार (30*) के साथ चौथे विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी करके मप्र को 100 रन के पार पहुंचाया। मुलानी ने शुभम शर्मा को अरमान जाफर के हाथों कैच आउट कराया। फिर रजत पाटीदार ने विजयी शॉट जमाकर मप्र खेमे में खुशियां बिखेर दी। पाटीदार के साथ कप्तान आदित्य श्रीवास्तव (1*) नाबाद लौटे। मुंबई की तरफ से शम्स मुलानी ने तीन जबकि धवल कुलकर्णी को एक विकेट मिला।

● **आशीष नेमा**

...जब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के कारण सोनाली बेंद्रे ने खो दी थीं कई फिल्में

अंडरवर्ल्ड की वजह से मुझे कई फिल्मों को छोड़ना पड़ा था। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है जब मैं कोई फिल्म साइन करती थी, लेकिन बाद में मेरा रोल किसी और को दे दिया जाता था।

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने खुलासा किया कि उन्हें कई फिल्मों से सिर्फ इसलिए हाथ धोना पड़ा क्योंकि उन फिल्मों का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके पति गोल्डी बहल ने इस दौरान उनकी खूब मदद की थी। सोनाली ने कहा, 90 के दशक में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अंडरवर्ल्ड के दबाव में रहते हुए काम करते थे। उस समय कई फिल्मों में गैर-कानूनी तरीके से पैसा लगाया जाता था। हैरानी की बात ये है कि अगर इस मामले में सिनेमा जगत के लोग उनका साथ न दें तो उनको काम कभी नहीं मिलता था।

सोनाली ने आगे बताया, मैं खुद को हमेशा उन फिल्मों से दूर रखने की कोशिश करती थी, जिसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होता था और इस काम में गोल्डी ने मेरा साथ दिया था। अंडरवर्ल्ड की वजह से मुझे कई फिल्मों को छोड़ना पड़ा था। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है जब मैं कोई फिल्म साइन करती थी, लेकिन बाद में मेरा रोल किसी और को दे दिया जाता था। इस दौरान कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है जब डायरेक्टर या फिर को-एक्टर मुझे फोन करके सिचवेशन समझाने की कोशिश करते थे और बताते थे कि उन पर दबाव है। बता दें कि गोल्डी बहल फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और इसी वजह से उन्हें उन फिल्मों की जानकारी होती थी जिसमें गैरकानूनी पैसा लगा होता था।

अपने स्ट्रगल के दिनों में कार्तिक आर्यन बनाते थे 12 लोगों का खाना

कार्तिक आर्यन हाल ही में भूषण कुमार से भारत में पहली जीटी पॉश मैकलारेन कार गिफ्ट में मिलने को लेकर चर्चाओं में हैं। भूषण कुमार ने ये कार कार्तिक को फिल्म भूल भूलैया-2 की जबरदस्त सफलता के लिए दी है। फिल्म में कार्तिक की क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया है। कार्तिक पहले भी अपनी फिल्मों से लोगों का दिल जीतते आए हैं। उन्होंने प्यार का पंचनामा और प्यार का पंचनामा 2 में भारत में अब तक का सबसे बड़ा मोनोलॉग किया था। दोनों ही फिल्मों के डायलॉग जबरदस्त हिट हुए थे, जिससे कार्तिक आर्यन को एक अलग पहचान मिली। कार्तिक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। उनका यहां तक पहुंचने का सफर काफी मुश्किल भरा था। मुंबई में रहने के दौरान ही कार्तिक को पैसों की तंगी होने लगी। ऐसे में वो 12 स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ रहते थे। मुंबई में रहने के लिए कार्तिक उन 12 लोगों का खाना बना दिया करते थे। इससे उनकी कुछ कमाई हो जाया करती थी। लगातार ऑडिशन देने के बाद भी कार्तिक का किसी फिल्म में सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसे में उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। मॉडलिंग के दौरान ही एक दिन कार्तिक को फेसबुक के जरिए 2011 में फिल्म प्यार का पंचनामा में काम करने का मौका मिला। ऑडिशन का कॉल आने के 6 महीने बाद कार्तिक को इस फिल्म का ऑडिशन करने का मौका मिला था।

कभी ढाई रुपए में नाटक कंपनी में काम करते थे रघुबीर यादव

एक्टर रघुबीर यादव ने हाल ही में अपना 72वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। रघुबीर बॉलीवुड में अपने देसी किरदारों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था और वो बॉलीवुड में सिंगर बनना चाहते थे। मां-बाप की सहमति न मिलने पर वो 15 साल की उम्र में घर से भाग गए थे।

रघुबीर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका एक दोस्त था, जिसे वे प्रोफेशनल भगोड़ा कहते हैं, क्योंकि वो अपने घर से महीने में 2 से 3 बार भागता था। फिर जब पैसे खत्म हो जाते थे तब फिर घर वापस आ जाता था। वे बताते हैं, उस समय मैं परेशान था क्योंकि मैं फेल हो गया था। उस दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं? तब तक भगोड़ा आ गया और उसने मुझसे कहा कि भागोगे, तो

मैंने कहा कि हां भाग लेंगे। उसने कहा कि चलो मैं भाग रहा हूं आज। फिर हम ललितपुर पहुंचे और वो मुझे वहां से भी छोड़ कर भाग गया, क्योंकि उसकी भागने की आदत थी। उसके बाद मैंने वहीं ढाई रुपए में नाटक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वे कहते हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी मुंबई पहुंच पाऊंगा। मुझे हमेशा से म्यूजिक बहुत पसंद था। मैं अक्सर गांव में फोक म्यूजिक ही सुनता था और उसी में डूबा रहता था। रात में जगह-जगह कव्वालियां होती थीं और मैं चुपके से उसे सुनने के लिए घर से भाग जाता था।

तीन पहियों वाली गाड़ी

बहुत दिनों बाद आज कुछ सोचते-सोचते अच्छी नींद आ गई। जब नींद अच्छी हो तो सपने का आना तो तय ही हैं। सपने में ही सही करोना के डर से बाहर जाने से डरने वाली मैं बाहर जाने के लिए तैयार होने लगी। अच्छी जींस और टॉप पहन सड़क के किनारे सवारी की खोज में खड़ी हो गई। काफी देर इंतजार के बाद भी कोई सवारी नहीं मिलने पर जुंजलाके के घर की और वापस जाने की सोची तो देखा तो एक तीन पहिए वाली गाड़ी जिस पर उसके मालिक ने बड़े प्यार से नाम लिखवाया था- बड़ाराष्ट्र (बदराष्ट्र) वह आके खड़ी हो गई। मैं फटाफट चढ़ बैठी कि कहीं और कोई बुला लेगा तो मेरी सवारी छूट जाएगी। सामान्यत: तो सवारी कैसी है, कोई कील-शील तो नहीं निकला हुआ जो मेरे कपड़े फाड़ देगा, पुरानी तो नहीं हैं जो चलेगी तो बहुत झटके देगी। इन बातों में से कुछ भी सोचे बगैर जल्दी से बैठ ही गई। जब देखा मेरी जल्दबाजी का नतीजा तो गलती समझ में आ गई। ये गड्डी के तो तीनों पहियों का आकार प्रकार और डीलडॉल अलग-अलग थे। गाड़ी चली तो ऐसे लग रहा था जैसे मेले में कोई बड़े से झूले में झूल रहे हो। कभी दाई और से ऊपर और बाईं ओर से नीचे, आगे वाला पहिया तो जाम ही था। उसकी हवा ही निकली हुई थी। मैंने गाड़ी चालक को पूछा कि ये आगे वाले पहिए को क्या हुआ है, तो वह कुछ सकपकता सा बोला कि वह पहिया बहुत पुराना है, समझों कि 75 साल हो गए हैं उसे। इसमें हवा भरवाने का खूब प्रयत्न करने के बावजूद हवा टिकती ही नहीं है। बस निकल ही जाती हैं, टायर पुराने हैं, उसका चक्के को भी जंग खा गया है पता नहीं कितने साल चलेगा ये। वैसे उसे ठीक करने इटली के कारीगर का सहारा लिया था लेकिन उसने तो उसको और खराब कर दिया। उसने पहले तो खुद ठीक करने की कोशिश की फिर किसी विद्वान अर्थशास्त्री को देकर ठीक करने की ठानी, किंतु ये अर्थशास्त्री बेचारा था तो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। अब इस पहिए को अपने नादान नन्हे मुन्नों को सौंप रखा है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन उन्होंने तो कभी गराज में काम ही नहीं किया है। बिनानुभवी होने से संभालना तो क्या उल्टा खराब कर के रखा है। हर बार लगातार कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं कर पाते हैं ये लोग। हां एक रास्ता है, उनके पास कुछ बुजुर्ग कारीगरों का हुजूम है जिनका इटली से कुछ लेना-देना नहीं है उनसे मरम्मत करवाएं तो शायद ठीक हो जाएं। वैसे उनकी सलाह तो लेते रहते हैं लेकिन जिम्मा नहीं देते तो कैसे ये ठीक चलेगा, ये समझ से परे हैं।

तब मैंने दूसरे पहिए के बारे में पूछ ही लिया, ये दाहिना पहिया है उसका क्या प्राब्लम है। तब चालक बोला कि बहनजी ये भी तो वही कंपनी के तहत बना हैं जिसे आगे वाले पहिए को बनाया था लेकिन उससे छोटा है किंतु उसे बनाने वाला भी काफी वयस्क और अशक्त है लेकिन वह अपने को कमजोर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका भी हाल कुछ वैसा ही है, जो उस कंपनी से उसे बाहर ले आया वह भी तो सिर्फ अपने फायदे के लिए लाया था। उसमें हवा टिक तो जाती हैं किंतु समय-समय पर फुस्स से निकल जाती है। बेईमानी की जो है वह हवा, तो टिकना तो मुश्किल है ही। उसके टायर तो नए ही हैं किंतु चक्के में कुछ खराबी है, उसे जंग तो नहीं लगा है अभी लेकिन कुछ निम्न कक्षा का, कबाड़ वाला समान उपयोग में लेने की वजह से गुणवत्ता के हिसाब से कुछ कमियां तो हैं ही, और कुछ तो उसके आसपास के लोगों से उल्टे-पुल्टे प्रयोग करवाने से ये असंतुलित ही रहता हैं। हमेशा संतुलन की कमी की वजह से गड्डी को ठीक नहीं चलने दे रहा है। बस थोड़ा पंगेबाज होने से बदनाम होता रहता है ये। हां ईमानदारी में तो ये भी अपनी मातृ शाखा जैसा ही है। हमेशा ही कौभांडी सा है चलना तो है किंतु तरीके से नहीं, सभी कुछ दो नंबरी का चाहिए तो कैसे ठीक चलेगा ये भी प्रश्न है। जब मुड़के उस तरफ देखा तो टेढ़ा मुंह लिए वह बेतरतीब ही चल रहा था। बायां पहिया तो कुछ ठीक ही लग रहा था तो मैंने भी पूछ ही लिया की इसका तो सब ठीक ही होगा न। लेकिन उसका भी वर्तमान और भविष्य के बारे में चिंतित ही लगा वह, बोला इसका उत्पति स्थान तो बेहतरीन है, एक वफादार और असूलन पक्के बंदे ने बनाया था जो किसी भी प्रकार के प्रलोभन के लिए अपने असूलों को छोड़ ही नहीं सकता था लेकिन आजकल सब आयाराम गयाराम सा व्यवहार कर रहा है ये। इसका भी एक नादान नन्हा-मुन्ना है जो इसका संतुलन बिगाड़ने को तैयार सा बैठा है। थोड़ी दगाबाजी भी है इसके चक्के में और टायर में बेईमानी और स्वार्थ की हवा भरी होने से ठीक से चल नहीं पा रहा है। किंतु अपने को संतुलित बताकर काम तो चला ही रहा है अपने नन्हे को छुपाकर। अपनी ताकत आजमाने का शौक रखता है। हालांकि कमजोर मनुष्य ज्यादा जोर से चिल्लाएगा ये प्रचलित है, जैसा हाल है इनका। थोथा चना बाजे घना देखें कब तक बजेगा ये, या तूती बंद कर देंगे उसके साथी ये मुश्किल सवाल है। उन तीन पहियों वाली गाड़ी से कहीं पहुंचना मुश्किल दिख रहा था तो मैंने चालक से रोकने के लिए बोला और नीचे उतर गई, ओह वो तो मैं अपने पलंग से उतर खड़ी थी और आंखों के सामने से राजकरण के कई धुरंधर चेहरे गुजरने लगे और मैं भी सोचने लगी ये तीन असंतुलित पहियों वाली गाड़ी कब तक, कहां तक चलेगी। कोई आकस्मिक अंत होगा या खुशहाल अंत होगा ये सभी प्रश्नों के साथ चाय का भगोना चूल्हे पर चढ़ाया और स्वप्न से बाहर आने की कोशिश करने लगी।

ये व्यंग मैंने 19/12/2021 के दिन लिखा था जो आज के महाराष्ट्र के हालात देख सही होता नजर आ रहा हैं। शतरंज की बिसात बिछ चुकी हैं जिसमे प्यादे इतने आगे बढ़ चुके हैं कि ऊंट और हाथी घोड़े की जगह लेने के लिए तैयार बैठे हैं। इस शतरंज की बिसात जो सर्वव्यापी दल ने बिछाई है जिसमें तीनों पहियों की हवा निकलती है या फिर से बच निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिसात बिछाने से पहले सभी पहियों के आरों को बहुत ही कमजोर कर दिया है और कुछ 37 जीतने स्क्रू या तो निकल लिए हैं या ढीले कर दिए हैं।

अब तो सिद्धांतों का पालन कर पितृ तर्पण कर उनको श्रृद्धांजली देने का समय आया है अगर तर्पण नहीं किया तो अंत आने की नौबत आ सकती है। अस्तित्व का बचाव या दल का अंत दो ही चीज में से एक को चुनना पड़ेगा।

● **जयश्री बिरमी**

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_0/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

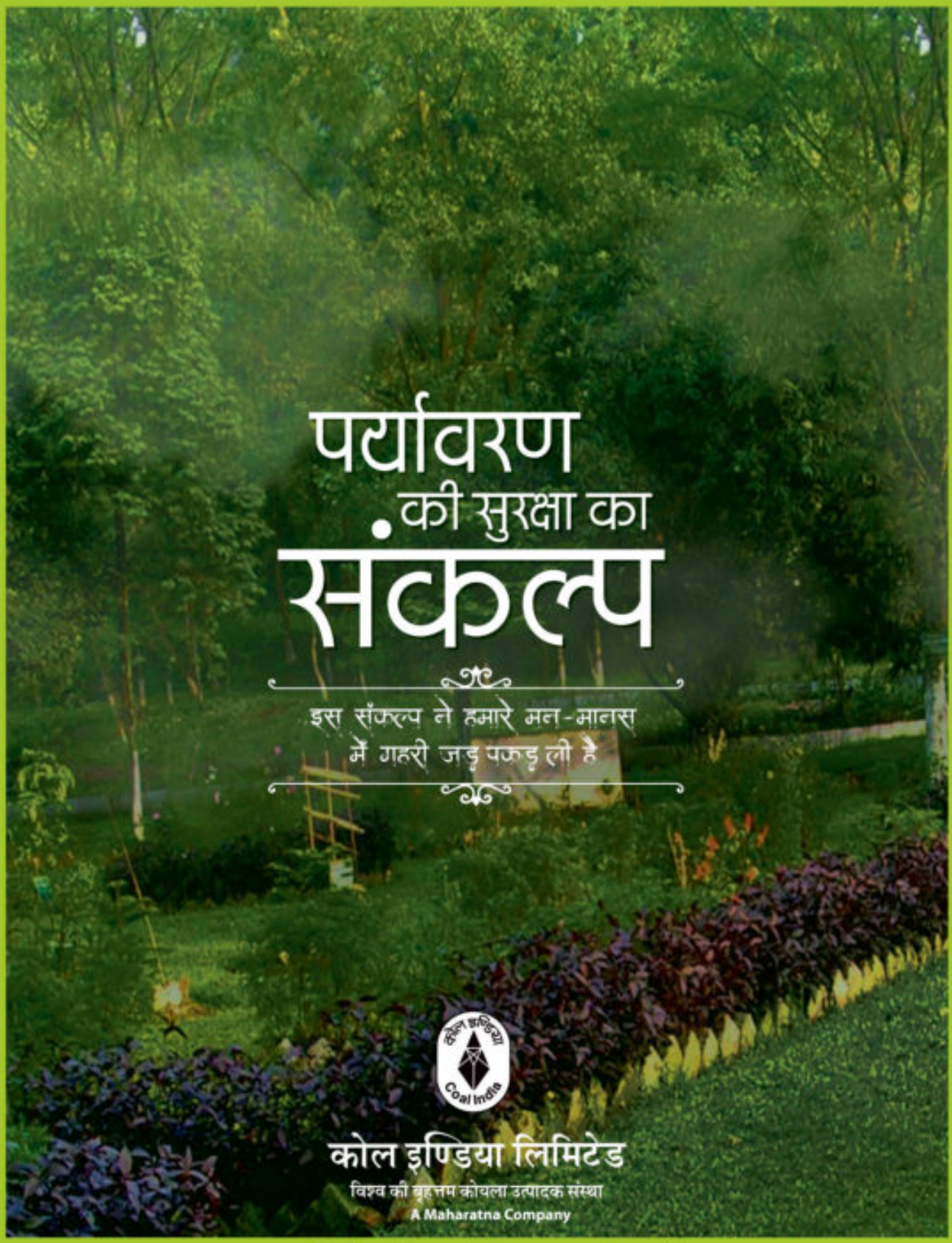

प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है